



ओपनिंग के लिए
विनती करनी पड़ी
थी : तेंदुलकर

>> 14

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 109

सरोकार

जहरीले रसायन से पर्यावरण
को बचाएगा बल्ब ईटर

चंडीगढ़ : केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने ऐसा कंटेनर विकसित किया है, जो इस्तेमाल के बाद कूड़े में फेंक दिए जाने वाले ट्यूबलाइट और बल्ब के बेहतर निस्तारण में उपयोगी साबित होगा। 'बल्ब एंड ट्यूबलाइट ईटर' नामक इस कंटेनर में खराब बल्ब या ट्यूबलाइट तोड़ते ही मौजूद रसायनों का सुरक्षित समाधान हो जाएगा। (पेज-10)

जागरण विशेष

डीएम ने खून देकर बचाई
गर्भवती आदिवासी की जान

सुकमा : छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 25 वर्षीय आदिवासी महिला हिड्डमे गर्भवती हैं। गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिला को तत्काल खून चढ़ाए जाने की जरूरत थी। सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी मिलने पर डीएम चंदन कुमार जिला अस्पताल पहुंचे और रक्तदान कर एक साथ दो जिंदगियां बचा लीं। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

12 वैज्ञानिकों को मिलेगा शांति
स्वरूप भटनागर पुरस्कार

नई दिल्ली : विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के 12 वैज्ञानिकों को 2019 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाएगा। बायोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र में आइआएएसईआर पुणे के डॉ. के श्रीकृष्णन और एनआइआइ दिल्ली के डॉ. सौमेन बसाक को संयुक्त रूप से इसके लिए चुना गया है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

पुणे में वारिस का कहर, विभिन्न
घटनाओं में 21 की मौत

मुंबई : महाराष्ट्र के पुणे जिले में बुधवार-गुरुवार की रात हुई मूसलधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई। विभिन्न घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी हैं। बाढ़ जैसे हालात पैदा होने से 10 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

सऊदी क्राउन प्रिंस की निगरानी
में हुई थी खशोमी की हत्या

रियाद : एक डाक्ट्यूमेंटरी में दावा किया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान ने पत्रकार जमाल खशोमी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। क्राउन प्रिंस ने कहा कि खशोमी की हत्या को उनकी निगरानी में अंजाम दिया गया था। इस डाक्ट्यूमेंटरी का प्रसारण एक अक्टूबर को किया जाएगा। खशोमी की पिछले साल दो अक्टूबर को सऊदी एजेंटों ने हत्या कर दी थी।

स्पोर्ट्स ▶ पृष्ठ 14

टीएनसीए अध्यक्ष बनीं श्रीनि की
वैटी रूपा गुरुनाथ

चेन्नई : बीसीसीआइ के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की बेटी रूपा गुरुनाथ को गुरुवार को यहां तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया जिससे वह भारतीय बोर्ड की राज्य इकाई की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं। रूपा गुरुनाथ मयापन की पत्नी हैं जिन पर 2013 आइपीएल में स्पोर्ट फिक्सिंग में शामिल होने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगा हुआ है।

बड़ी बात

अमेरिकी कंपनी
ने भारत को दिया
प्रस्ताव, 40 फीसद
अधिक हथियार
क्षमता समेत भारत
की विशेष जरूरत
और इशा रडार से
लैस होगा एफ-21



संजय मिश्र, नई दिल्ली

अमेरिकी वायुसेना की लाइफलाइन मानी जाने वाली लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने एलान किया है कि वह अति आधुनिक एफ-21 लड़ाकू विमान केवल भारत को देने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना एफ-21 को खरीदने का फैसला करती है तो कंपनी इसे दुनिया के किसी दूसरे देश को नहीं देगी। साथ ही उसका मानना है कि नए राफेल लड़ाकू जेट और तेजस विमानों के साथ एफ-21 की लिकड़ी भारतीय वायुसेना को न केवल बेहद ताकतवर बल्कि मार्क भी बनाएगी।

भारतीय वायुसेना की 114 नए लड़ाकू विमानों की खरीदने की दौड़ में शामिल दुनिया की सबसे बड़ी एरोनॉटिक्स कंपनी लॉकहीड मार्टिन के वाइस प्रेसीडेंट एरोनॉटिक्स स्ट्रेटजी डॉ. विवेक लाल ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत के दौरान यह बात कही। भारतीय वायुसेना की और से विमानों की खरीद प्रक्रिया शुरू करने के लिए जारी की गई आरएफआइ में एफ-21 ने भी अपना प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि इस क्रम में वायुसेना की ओर से कुछ सवाल और स्पष्टीकरण पूछे गए जिसका



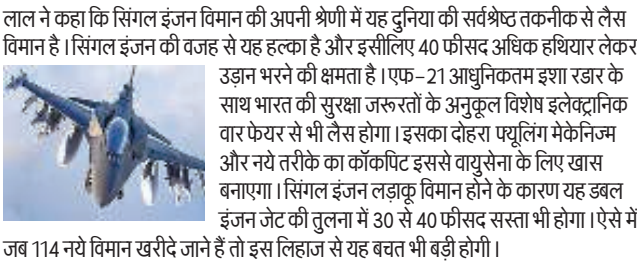
डॉ. विवेक लाल

फाइल फोटो

हमने जवाब दे दिया है। अब अगले दौर की प्रक्रिया होगी लाल ने कहा कि जहां तक एफ-21 की भारत को आपूर्ति का सवाल है तो वायुसेना की शर्तों के अनुरूप 18 विमान पूरी तरह से तैयार आएंगे। बाकी विमान हम भारत में ट्राय समूह के साथ मिलकर बनाएंगे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत ने फ्रांस से 36 और राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का फैसला किया है।

राफेल, तेजस और एफ-21 विमानों की तिकड़ी पेज>>6

सिंगल इंजन के कारण 30-40 फीसद सस्ता होगा



जब 114 नये विमान खरीदे जाने हैं तो इस तिहाज से यह बत भी बड़ी होगी।

भारतीय और अमेरिकी वायुसेना के बीच जबरदस्त समानता दिखेगी

पाकिस्तान को पूर्व में एफ-16 विमान देने के कंपनी के पूर्व के डील को देखते हुए भारत को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि विरोधी को एफ-21 तकनीक न मिले? विवेक ने कहा कि एफ-16 दुनिया के 28 अग्रिम देशों की वायुसेना इस्तेमाल कर रही है और करीब 3000 ऐसे विमान उड़ान भर रहे हैं। अगर जब भारत को एफ-21 का हमारा सबसे सुपीरियर वर्जन देगे तो हम वादा करेंगे कि यह विमान दुनिया के किसी दूसरे देश को नहीं देगे। लाल के मुताबिक एफ-21 की भारत के लिए विशिष्टता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एफ-16 फैमिली अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में चौथे जेनरेशन के एफ-21 की आपूर्ति केवल भारत को होगी तो भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच जबरदस्त समानता दिखेगी।

रूहानी से भेंट कर मोदी ने अमेरिका को दिया संदेश



न्यूयॉर्क में गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना सत्र के इतर पीएम नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी के बीच मुलाकात हुई। एनआइ

आशुतोष झा, न्यूयॉर्क

संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन की कूटनीति के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी की मुलाकात हुई। अमेरिका के साथ ईरान के तनावपूर्ण रिश्ते को देखते हुए इस मुलाकात के खास मायने हैं। इस मुलाकात से अमेरिका समेत अन्य देशों को साफ संदेश भी दे दिया गया है कि भारत किसी भी दबाव में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से नहीं डिगेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर दोनों नेताओं की मुलाकात की जानकारी दी। जबकि, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा हुई।

वहीं, मुलाकात के बाद जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने यह माना कि भारत और ईरान के बीच प्राचीन संबंध हैं। दोनों नेताओं ने 2015 में उफा में हुई मुलाकात के बाद आपसी संबंधों की प्रगति की भी समीक्षा की। दोनों के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर विशेष चर्चा हुई और अफगानिस्तान और मध्य एशिया क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के तौर पर इसके महत्व को भी स्वीकार किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए कूटनीति, संवाद और विश्वास बढ़ाने वाले उपायों को प्राथमिकता देने के भारत के समर्थन को भी दोहराया। दोनों देशों के बीच 2020 में राजनयिक संबंधों के 70वें

स्थापना दिवस को मनाने पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी और रुहानी की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पिछले कुछ दिनों में दो बार मुलाकात हो चुकी है। वहीं, रुहानी और ट्रंप की न तो कोई मुलाकात हुई है और ही आगे होने की संभावना है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान के साथ उसके संबंध भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं।

अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगा रखी हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने भी मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा हुई।

वहीं, मुलाकात के बाद जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने यह माना कि भारत और ईरान के बीच प्राचीन संबंध हैं। दोनों नेताओं ने 2015 में उफा में हुई मुलाकात के बाद आपसी संबंधों की प्रगति की भी समीक्षा की। दोनों के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर विशेष चर्चा हुई और अफगानिस्तान और मध्य एशिया क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के तौर पर इसके महत्व को भी स्वीकार किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए कूटनीति, संवाद और विश्वास बढ़ाने वाले उपायों को प्राथमिकता देने के भारत के समर्थन को भी दोहराया। दोनों देशों के बीच 2020 में राजनयिक संबंधों के 70वें

स्थापना दिवस को मनाने पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी और रुहानी की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पिछले कुछ दिनों में दो बार मुलाकात हो चुकी है। वहीं, रुहानी और ट्रंप की न तो कोई मुलाकात हुई है और ही आगे होने की संभावना है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान के साथ उसके संबंध भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं।

अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगा रखी हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने भी मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा हुई।

वहीं, मुलाकात के बाद जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने यह माना कि भारत और ईरान के बीच प्राचीन संबंध हैं। दोनों नेताओं ने 2015 में उफा में हुई मुलाकात के बाद आपसी संबंधों की प्रगति की भी समीक्षा की। दोनों के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर विशेष चर्चा हुई और अफगानिस्तान और मध्य एशिया क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के तौर पर इसके महत्व को भी स्वीकार किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए कूटनीति, संवाद और विश्वास बढ़ाने वाले उपायों को प्राथमिकता देने के भारत के समर्थन को भी दोहराया। दोनों देशों के बीच 2020 में राजनयिक संबंधों के 70वें

स्थापना दिवस को मनाने पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी और रुहानी की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पिछले कुछ दिनों में दो बार मुलाकात हो चुकी है। वहीं, रुहानी और ट्रंप की न तो कोई मुलाकात हुई है और ही आगे होने की संभावना है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान के साथ उसके संबंध भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं।

अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगा रखी हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने भी मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा हुई।

वहीं, मुलाकात के बाद जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने यह माना कि भारत और ईरान के बीच प्राचीन संबंध हैं। दोनों नेताओं ने 2015 में उफा में हुई मुलाकात के बाद आपसी संबंधों की प्रगति की भी समीक्षा की। दोनों के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर विशेष चर्चा हुई और अफगानिस्तान और मध्य एशिया क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के तौर पर इसके महत्व को भी स्वीकार किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए कूटनीति, संवाद और विश्वास बढ़ाने वाले उपायों को प्राथमिकता देने के भारत के समर्थन को भी दोहराया। दोनों देशों के बीच 2020 में राजनयिक संबंधों के 70वें

स्थापना दिवस को मनाने पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी और रुहानी की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पिछले कुछ दिनों में दो बार मुलाकात हो चुकी है। वहीं, रुहानी और ट्रंप की न तो कोई मुलाकात हुई है और ही आगे होने की संभावना है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान के साथ उसके संबंध भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं।

अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगा रखी हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने भी मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा हुई।

वहीं, मुलाकात के बाद जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने यह माना कि भारत और ईरान के बीच प्राचीन संबंध हैं। दोनों नेताओं ने 2015 में उफा में हुई मुलाकात के बाद आपसी संबंधों की प्रगति की भी समीक्षा की। दोनों के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर विशेष चर्चा हुई और अफगानिस्तान और मध्य एशिया क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के तौर पर इसके महत्व को भी स्वीकार किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए कूटनीति, संवाद और विश्वास बढ़ाने वाले उपायों को प्राथमिकता देने के भारत के समर्थन को भी दोहराया। दोनों देशों के बीच 2020 में राजनयिक संबंधों के 70वें



इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो महीने में लिखा था फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद करीब दो महीने का समय फैसला देने में लिया था। हाई कोर्ट ने जुलाई, 2010 में सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था और 30 सितंबर, 2010 को फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट में जनवरी से जुलाई तक करीब सात महीने नियमित सुनवाई चली थी। इस दौरान मई-जून में गर्मी की छुट्टी के कारण दो महीने तक कोर्ट बंद रहा था।

हाई कोर्ट से 15 बक्सों में आए

हैं दस्तावेज : सुप्रीम कोर्ट के लिए चार सप्ताह में फैसला लिखना लिखना चुनौती भरा काम है इसे इस बात से ही जाना जा सकता है कि हाई कोर्ट से 15 बक्सों में मुकदमे से जुड़े साक्ष्य और रिकॉर्ड मूल फैसले की

चार सप्ताह में फैसला लिखना चुनौतीपूर्ण काम

सुप्रीम कोर्ट अगर 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी कर लेगा तो प्रधान न्यायाधीश रजन गोगोई की सेवानिवृत्ति तक फैसला लिखने के लिए उसके पास करीब चार सप्ताह का समय बचेगा। अरोध्या विवाद जैसे विस्तृत मामले में चार सप्ताह में फैसला लिखना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इस मुकदमे में 14 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में विचारार्थ हैं, जिस पर 32 दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है। कुल 41 दिन सुनवाई होगी। हालांकि यह अभी तक किसी भी मुकदमे में चली सबसे लंबी सुनवाई होगी।

कोर्ट ने तीन हिस्सों में बांट दी थी जमीन

हाई कोर्ट ने अरोध्या में राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था जिसमें एक हिस्सा रामलला विराजमान को, दूसरा निर्माही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को दिया गया था। सभी ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

प्रति के साथ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं जिन पर

सुनवाई के दौरान विचार किया जाता है। इसमें करीब 8,000 पेज का मूल फैसला है। 13,000 पेज की गवाहियां हैं और 250 अभिलेखी साक्ष्य (दस्तावेजी सबूत) हैं। इन पर कोर्ट को फैसला लिखते समय गौर करना है।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पक्षकारों की ओर

से दी गई मौखिक और लिखित दलीलों पर भी

विचार किया जाएगा।

कोर्ट ने पूछ, अगर ईदगाह थी तो इमाम के बैठने

की जगह कहा है

पेज>>3

मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण तय

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : एंटिगुआ एवं बरबुडा के

प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने कहा है कि मेहुल चोकसी 'धोखेबाज' है और उसके सभी कानूनी विकल्प समाप्त होने पर उसे भारत को सौंप दिया जाएगा। उनका देश उसे रखने का इच्छुक नहीं है क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है। ब्राउन ने कहा एंटिगुआ की नागरिकता हासिल करने में भारतीय अफसरों ने उसकी मदद की थी। पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई को हीरा कारोबारी चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी की तलाश है। सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह ने कहा है कि पीएम ब्राउन का चोकसी को धोखेबाज कहना भारतीय एजेंसियों के लिए सकारात्मक संकेत है।

एंटिगुआ और बरबुडा के पीएम संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र में भाग लेने न्यूयॉर्क आए हुए हैं। डीडी न्यूज चैनल से बातचीत में ब्राउन ने कहा बैंक धोखाधड़ी के भगोड़े को वापस भेजना बेहद जरूरी है। इसमें चोकसी को वापस भेजना बेहद जरूरी है। 'मैं आपको आश्चर्य

एंटिगुआ के पीएम ने कहा, धोखेबाज है

भगोड़ा हीरा कारोबारी



गेस्टन ब्राउन

मेहुल चोकसी

कर सकता हूं कि उसकी सभी अपील खत्म होने के बाद उसे वापस भेज दिया जाएगा। उसके खिलाफ जो भी आरोप हों, उसका सामना करने को उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा।' चोकसी की नागरिकता पर उन्होंने कहा, 'हमें पता होता कि वह धोखेबाज है तो उसे एंटिगुआ की नागरिकता नहीं मिलती। हमारे अधिकारियों ने भारत से मिली सूचना पर काम किया और उसे नागरिक बनाया। उस स्थिति के लिए भारतीय अधिकारियों को जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए।' चोकसी को जनवरी 2018 में एंटिगुआ एवं बारबुडा की नागरिकता दे दी गई।

वर्षा जोशी ने किया टवीट-मैं
अपने दफ्तर में सुरक्षित नहीं

नई दिल्ली : दिल्ली में महिला सुरक्षा के बढ़े-बढ़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आयुक्त और 1995 बैच की आइएएस अधिकारी वर्षा जोशी ने टवीट कर खुद को अपने दफ्तर में असुरक्षित बताया है। उन्होंने लिखा कि लोग अक्सर महिला अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें एहसास नहीं होता है कि वह ऐसा कर रहे हैं। दरअसल निगम की आयुक्त वर्षा जोशी ने एक महिला के 'सर्वजनिक स्थानों पर बदसलुकी की शिकायत वाले टवीट के जवाब में यह बात कही। (पेज-2)

महाराष्ट्र में अपने दम पर बहुमत
हासिल करने में जुटी भाजपा

नई दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पिछली बार स्पष्ट बहुमत से चुन जाने वाली भाजपा इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वैसे शिवसेना के साथ सीटों के बँटवारे के बाद कम सीटों पर चुनाव लड़कर अपने दम पर बहुमत हासिल करने की राह उसके लिए आसान नहीं होगी। शायद यही कारण है कि अमित शाह ट्रंप ने कश्मीर पर फिर की मध्यस्थता की बात भारत ने कहा, मंजूर नहीं पेज>>5

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत को चुनौती दी है। उसने कहा कि मनी लाँड्रिंग मामले में वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जबकि पैसों की चैन प्रोथे तौर पर उनसे जुड़ी हुई है। इसलिए उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है। हाई कोर्ट ने इस पर अंतिम बहस के लिए सुनवाई 5 नवंबर के लिए तय की है।

ईडी को चुनौती याचिका पर वाड्रा ने भी हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मामले से जुड़े सभी दस्तावेज जांच एजेंसी के कब्जे में हैं। ऐसे में उसके साथ छेड़छाड़ होने का भी खतरा नहीं है। अगर कोई खुद पर लगे आरोप नहीं मानता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा। वाड्रा को निचली अदालत ने अग्रिम जमानत दी थी। फैसले को चुनौती देते हुए जांच एजेंसी ने कहा था कि निचली अदालत मामले को समझने में

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, जांच में
सहयोग नहीं कर रहे वाड्रा



रॉबर्ट वाड्रा

फाइल फोटो

नाकाम रही और इस तरह के मामले में रूटीन तरीके से जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। वाड्रा के खिलाफ विदेश में सटिथ्र संपत्ति और बीकानेर में जमीन खरीदने की जांच चल रही है। लंदन में एक फ्लैट को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा के खिलाफ मनी लाँड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी का आरोप है कि वह फ्लैट मनोज अरोड़ा का नहीं बल्कि वाड्रा का है जिसे हथियार डीलर संजय भंडारी से 2010 में खरीदा गया था।

नारद कांड में सीबीआई ने आइपीएस मिर्जा के रूप में की पहली गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल के बहुचर्चित नारद स्टिंग कांड में गुरुवार को सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की। जांच एजेंसी ने आइपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा को विशेष अदालत में पेश किया। वहां से उन्हें 30 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया। 2014 में नारद न्यूज पोर्टल के तत्कालीन सीईओ व संपादक मैथ्यू सेमुअल ने कोलकाता में तुणमूल के एक दर्जन से अधिक मंत्रों, सांसद व विधायकों और नेताओं के साथ बर्धमान जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आइपीएस मिर्जा का भी स्टिंग आपरेशन किया था।

इन लोगों को एक काल्पनिक कंपनी की मदद के एवज में मोटी रकम दी गई थी जिसका वीडिया तैयार किया गया था। मिर्जा खुद ही वीडियो में यह कहते दिखाई दिए थे कि वह तुणमूल के कई मंत्री, सांसद, विधायक व नेताओं के बेहद करीब हैं। सीबीआई नारद कांड में मिर्जा की भूमिका को लेकर पूछताछ करना चाहती है। मामले के अन्य आरोपितों के साथ

सीबीआई में फिर रार

संयुक्त निदेशक
पर फर्जी मुठभेड़
का लगाया आरोप

नई दिल्ली, एएनआइ : सीबीआई के अफसरों के बीच अंदरूनी लड़ाई फिर सामने आई है। डिप्टी एसपी रैंक के एक अधिकारी ने संयुक्त निदेशक के खिलाफ फर्जी मुठभेड़ में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिसमें झारखंड में 14 निर्दोषों की जान गई थी। एएनआइ ने इस मामले में सीबीआई की प्रतिक्रिया जाननी चाही, पर कोई जवाब नहीं मिला। ज्ञात हो, पिछले साल सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक रमेश अस्थाना की अंदरूनी लड़ाई में जांच एजेंसी की जमकर किरकिरी हुई थी। बाद में दोनों की सीबीआई से विदाई हो गई थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक, मुख्य सतर्कता आयुक्त और प्रधानमंत्री कार्यालय से की गई अपनी शिकायत में पुलिस उपाधीक्षक एनपी मिश्र ने आरोप लगाया है कि एजेंसी के संयुक्त निदेशक एके भटनागर झारखंड में हुई फर्जी मुठभेड़ में शामिल थे। इस मामले की सीबीआई की विशेष अपराध शाखा-प्रथम जांच कर रही है। सीबीआई की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए भटनागर को तुरंत एजेंसी से हटाया जाना चाहिए, अन्यथा वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच प्रभावित कर सकते हैं। भटनागर इस समय सीबीआई में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के पद पर तैनात हैं। एनपी मिश्र ने कहा है कि इस संबंध में मारे गए लोगों के परिजन ने भी शिकायत दर्ज कराई है। डिप्टी एसपी ने यह भी कहा है कि भटनागर के खिलाफ भ्रष्टाचार के भी गंभीर मामले हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार की है।

दूसरे मामलों में भी
कर चुके हैं शिकायत

यह पहला मौका नहीं है कि मिश्र ने सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पत्रकार उमेश राजपूत हत्याकांड में भी सीबीआई के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और सुबुकी से छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, लेकिन तब जांच एजेंसी ने दो मिश्रों को नकार दिया था। आरोपों के बाद मिश्र का तबादला कर दिया गया था, जिसे उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है और उस पर एक अक्टूबर को सुनवाई होनी है।

बीकानेर जमीन मामले में समय
पूर्व सुनवाई पर ईडी को आपत्ति

जागरण संवाददाता, जोधपुर : रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े बीकानेर के कोलायत में जमीन मामले को लेकर गुरुवार को कोर्ट में तय समय से पहले सुनवाई होने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल, सुनवाई का समय दो बजे तय था, लेकिन वाड्रा के अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने इससे पहले ही पेश हो कर सुप्रीम कोर्ट में वल रही सुनवाई के बाद ही इस मामले को सुनने का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने 5 नवंबर की तारीख तय कर दी। दोपहर दो बजे के बाद ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल आरडी रस्तोगी कोर्ट पहुंचे और इस बात पर अपनी आपत्ति जताई कि सुनवाई तय समय से पहले क्यों की गई। सहायक सॉलिसीटर जनरल भानु प्रकाश बीहरा ने कोर्ट में प्रार्थना- पत्र दाखिल कर दो बजे से पहले मामले की सुनवाई का कारण पूछ, जिस पर कोर्ट ने वाड्रा के वकीलों से जवाब मांगा और 24 नवंबर को सुनवाई तय कर दी। तब तक वाड्रा व उनके कारोबारी सहयोगियों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।

कोलकाता में सीबीआई ने गुरुवार को एसएमएच मिर्जा (पृष्ठ 2) को अदालत में पेश किया। प्रेट्र

आइपीएस अधिकारी का क्या लेन-देन हुआ था, इसका भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। मिर्जा की गिरफ्तारी पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र ने कहा, इस मामले में जल्द ही और भी गिरफ्तारियां होंगी। वहीं भाजपा ने कहा है कि मिर्जा की गिरफ्तारी पहले हो जानी चाहिए थी।

2014 में एक दर्जन तुणमूल नेता, मंत्री, सांसद व विधायकों का हुआ था स्टिंग

नारद न्यूज पोर्टल के स्टिंग के दौरान बर्धमान जिले के एसपी थे मिर्जा



कोलकाता में सीबीआई ने गुरुवार को एसएमएच मिर्जा (पृष्ठ 2) को अदालत में पेश किया। प्रेट्र

व्या है नारद स्टिंग कांड

पेज>>3

पराली प्रदूषण से बचाव के लिए ठोस कदम उठाने की मांग

पहल ▶ चिंतित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, ट्वीट कर दी जानकारी

राजधानी में पिछले चार वर्षों में 25 फीसद तक प्रदूषण हुआ है कम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

हर साल अक्टूबर और नवंबर में पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा पराली जलाए जाने से दिल्ली की हवा खराब होने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताई है। केजरीवाल ने गुरुवार को हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों समेत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। इस पत्र की जानकारी केजरीवाल ने ट्वीट करके दी है।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि सभी सरकारी एजेंसियों और दिल्लीवासियों के प्रयासों के कारण दिल्ली आज उन कुछ शहरों में शामिल है, जहां पिछले चार वर्षों में 25 फीसद तक प्रदूषण कम हुआ है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में पराली जलने के कारण होने वाले प्रदूषण से लड़ने में दिल्ली के लोग सक्षम नहीं हैं। आकांषी सरकार पराली जलने से रोकने के संबंध में कुछ कदम उठा रही है, लेकिन मुझे

न्यूज गेलरी

डीयू में प्लेसमेंट के लिए दस हजार छात्रों ने कराया पंजीकरण

नई दिल्ली :दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की तरफ से अब लसेमंट ड्राइव को व्यापक स्तर पर शुरू किया जा रहा है। डीयू प्रशासन, विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों के छात्रों को एक वंच प्रदान करेगा। इसमें उन्हे देश-विदेश से आने वाली कंपनियों से नौकरियों के ऑफर मिलेंगे। डीयू की स्टूडेंट वेल्फेयर की डिप्टी डीन प्रो. हेना सिंह ने बताया कि दो सितंबर से डीयू के केंद्रीय प्लेसमेंट सेल की वेबसाइट पर प्लेसमेंट के लिए पंजीकरण शुरू किया गया था। इसमें अब तक 10,786 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। इसी के तहत डीयू में गुरुवार को कई छात्र लसेमंट प्रक्रिया में शामिल हुए। प्रो. हेना ने कहा कि सभी कॉलेजों को ईमेल के जरिये प्लेसमेंट से जुड़े संदेश भेजे जा रहे हैं। डीयू के सभी कॉलेजों के कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम के तीसरे वर्ष के छात्र इसमें हिस्सा ले रहे हैं। (जास)

महिला पत्रकार से लूट, वारदात सीसीटीवी में हुई कैद

नई दिल्ली : कुछ दिन पहले ग्रेटर केलारा में महिला पत्रकार के साथ हुई लूट की वारदात अभी सुनझी भी नहीं कि दूसरी वारदात सामने आ गई। इस बार ग्रेटर केलारा में महिला पत्रकार से लूट का मामला सामने आया था। ओखला औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी चैनल में काम करने वाली महिला पत्रकार राधिका से बाइक सवार बदमाशों ने उनका मोबाइल झपट लिया। पूरी वारदात घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस के मुताबिक, राधिका (23) परिवार के साथ गोविंदपुरी इलाके में रहती है। वह एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर है। 23 सितंबर की शाम वह ऑफिस से घर जा रही थीं बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से आकर उनका मोबाइल लूट लिया। इसके बाद वे तेज रफ्तार बाइक से भाग गए। (जास)

ईरानी गैंग की ग्वाला यूनिट का कमांडर गिरफ्तार

गाजियाबाद : साहिबाबाद पुलिस ने कुख्यात ईरानी गैंग की ग्वाला यूनिट के कमांडर को गिरफ्तार किया है। चोरी की बाइक, तमबा, बैग और 1.10 लाख रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस ने मुरादाबाद की रेवेन्यू हथौला कोलीन निवासी धर्मवीर सिंह उर्फ धर्मी की गुरुवार सुबह साहिबाबाद में दिल्ली सीमा के पास से पकड़ा है। धर्मवीर पर दिल्ली पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। उसे राजहंस, अरुण ग्वाला, राजन और दीपक शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसके खिलाफ दिल्ली, उ्प्र, पश्चिम बंगाल, असम व राजस्थान के साथ महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में 150 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को 111 मामलों में उसकी तलाश है, जिसमें उसकी सास की हत्या का केस भी शामिल है। (जास)

नया कदम

सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए करेंगे काम, दोनों संस्थानों के छात्र विभिन्न विषयों की पढ़ाई भी साथ-साथ कर सकेंगे



अरविंद केजरीवाल।

(फाइल)

यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि बहुत कुछ करने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने अंत में लिखा, मेरा निवेदन है कि आपकी सरकार इस बार यह अवश्य ही सुनिश्चित करेगी कि पराली जलाने पर तत्काल रोक लगे। यही एकमात्र तरीका है, जिससे हम पंजाब और दिल्ली के लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह पहले ही प्रदूषण से निपटने और लोगों को राहत देने के लिए सात सूत्रीय पराली प्रधान कार्ययोजना और पांच सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा कर

मैं दफ्तर में सुरक्षित नहीं : वर्षा जोशी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में महिला सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आयुक्त और 1995 बैच की आइएएस अधिकारी वर्षा जोशी ने ट्वीट कर खुद को अपने दफ्तर में असुरक्षित बताया है। उन्होंने लिखा कि लोग अक्सर महिला अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें एहसास नहीं होता है कि वह ऐसा कर रहे हैं।

दरअसल, बुधवार को उन्हें एक महिला ने ट्वीट पर टैग करते हुए लिखा कि उनके इलाके में सड़क पर कुछ लोग हुक्का पीते हैं, ताश खेलते रहते हैं और महिलाओं को घुरते हैं। इस वजह से महिलाओं का उस सड़क से निकलना मुश्किल हो गया है।

इस ट्वीट के जवाब में वर्षा जोशी ने लिखा कि यह मामला पुलिस से संबंधित है। उत्तर भारत में 24 घंटे सातों दिन ऐसी चुनौतियां रहती हैं। उनके साथ खुद उनके दफ्तर में दुर्व्यवहार और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं। उनके इस ट्वीट के बाद महिला सुरक्षा के मुद्दे पर टिप्पणियों की बाढ़ सी आ गई।

वर्षा जोशी दिसंबर 2018 से उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आयुक्त हैं। वह एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के 1995 बैच की आइएएस हैं। इससे पहले वह परिवहन विभाग

अक्टूबर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का परिसर प्लास्टिक भुक्त हो जाएगा। इसके तहत पूरे परिसर में, छात्रावास में, सभी कैटीन, दुकानों और कॉफी हाउस पर सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

चुके हैं। एक तरफ जिस तरह से दिल्ली प्रदूषण से लड़ने के लिए प्लान बना चुकी है, उस तरह अन्य राज्यों को भी ठोस कदम उठाने चाहिए। दिल्ली सरकार ने उठाए ये कदम : मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पहले ही सर्दियों में फसल जलने के कारण वायु गुणवत्ता बिगड़ने की समस्या से निपटने के लिए सात सूत्री पराली प्रधान कार्य योजना और पांच सूत्री शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की है। 50 लाख मास्क की खरीद शुरू हो गई है और ऑड-इवेन योजना पर भी काम किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर होने वाले सामुदायिक दिवाली कार्यक्रम के लिए लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है, जिससे लोग पटाखे नहीं जलाएं। वह त्योहार के लिए एक साथ आएँ और लेजर शो का आनंद लें।

दिल्ली देश का एकमात्र शहर जहां प्रदूषण में आई कमी : बता दें कि दिल्ली देश का एकमात्र शहर है, जहां पिछले दिनों प्रदूषण में कमी आई है। पीएम 2.5 में पिछले तीन वर्षों में 25 फीसद की कमी आई है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की नवीनतम रैंकिंग में टॉप टेन में सात भारतीय शहर हैं, जबकि दिल्ली इस सूची में 11वें स्थान पर है। शीर्ष तीन भारतीय शहर गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद हैं।

डीटीयू के अध्ययन में ऑड-इवेन के आए सकारात्मक नतीजे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली की हवा में प्रदूषण को कम करने के लिए लागू की गई ऑड-इवेन योजना को लेकर दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) के अध्ययन में सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। जनवरी 2016 में दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना से वायु प्रदूषक तत्व पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 और पीएम 1.0 की सांद्रता में कमी आई थी। केवल 15 दिन के ट्रायल में ही पीएम 2.5 में औसतन 5.73 फीसद और पीएम 1.0 में औसतन 4.70 फीसद की कमी दर्ज की गई थी। यह अध्ययन दिल्ली के तीन प्रमुख कॉरिडोर पर किया गया।

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि दिल्ली सरकार ने पहली बार परीक्षण के आधार पर जो ऑड-इवेन योजना लागू की थी, उसके पहले चरण को लेकर पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. राजीव कुमार मिश्रा और उनकी शोध टीम ने अध्ययन किया।

एलजी का पुलिस को निर्देश, नशे की गिरफ्त से बचाएं दिल्ली को

जास, नई दिल्ली : राजनिवास में आयोजित बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने संगठित अपराधों जैसे अवैध हथियारों का उपयोग करने वाले अपराधियों व ड्रग तस्करो से निपटने में दिल्ली पुलिस की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक, दिल्ली सरकार के विशेष गृह सचिव, विशेष आयुक्त सतीश गोलवा आदि उपस्थित थे।

इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने उपराज्यपाल को बताया कि अवैध हथियारों के उपयोग करने वाले सक्रिय अपराधियों व जेल से बाहर आने वाले अपराधियों के बारे में सूचनाओं को साझा कर उसके निपटा जा रहा है। ड्रग तस्करी रोकने व उक्त धंधे में शामिल तस्करो की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी उपराज्यपाल को दी गई। उन्हें बताया गया कि ड्रग तस्करी जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए हर जिले में एंटी नारकोटिक्स सेल भी स्थापित किया गया है जिसके द्वारा संबंधित क्षेत्रों में निगरानि निगरानी की जाती है। बैजल ने बच्चों व किशोरों को ड्रग की लत से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस को शिक्षण संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों की विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए।

वाहनों से निकलने वाले धुएं से होती है पीएम में वृद्धि

प्रो. योगेश सिंह ने बताया कि अध्ययन में पता चला कि योजना के क्रियान्वयन के दौरान पीएम 1.0 के मुकाबले पीएम 2.5 की सांद्रता में अधिक कमी आई। यह तीनों कॉरिडोर में वाहनों से निकलने वाले धुएं के उत्सर्जन को दर्शाता है।

उन्होंने हाल ही में ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च के तहत ‘पीएम 2.5 और पीएम 1.0 उत्सर्जन पर ऑड-इवेन ड्राइविंग स्कीम का प्रभाव’ शीर्षक से एक पेपर प्रकाशित किया है। इस शोध में उक्त योजना के काफी सकारात्मक प्रभाव सामने आए।

मुख्य कॉरिडोर पर हुआ अध्ययन : कुलपति ने बताया कि शोध टीम ने दिल्ली के पोतमपुरा (मधुवन चौक), पचकुइयां रोड और

क्या है पीएम 2.5 और पीएम 1.0

पीएम का अर्थ है पार्टिकुलेट मैटर, जो कि वातावरण में मौजूद ठोस और तरल कणों का मिश्रण है। इन कणों को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिये ही देखा जा सकता है। इसमें धूल व धातु आदि के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। पीएम 2.5 का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम और पीएम 1.0 का व्यास 1.0 माइक्रोमीटर से कम होता है।

नजफगढ़ रोड के तीन प्रमुख कॉरिडोर में ऑड-इवेन योजना पर अध्ययन किया। अध्ययन में पीएम 2.5 और पीएम 1.0 के रियल टाइम पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) डाटा को एकत्र किया गया था। ऑड-इवेन लागू होने से पहले और उसके दौरान पीएम 2.5 और पीएम 1.0 की सांद्रता के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चला कि इन तीनों कॉरिडोर में प्रदूषक तत्वों में कमी आई थी।

देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना ही असली देशभक्ति : केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

देशभक्ति पाठ्यक्रम बनाने के लिए गठित कमेटी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पहली बैठक की। इसमें उन्होंने कमेटी के सामने साफ किया कि उनकी नजर में देश से प्यार और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना ही असली देशभक्ति है। उन्होंने इसी तर्ज पर पाठ्यक्रम बनाने की भी अपेक्षा की। वहीं पाठ्यक्रम बनाने के लिए मांगे गए बच्चों के सुझावों को मुमकिन सुनकर सीएम ने कहा, अगर हमारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं तो देश का भविष्य सुनहरा दिख रहा है।

केजरीवाल ने कमेटी को कहा कि अब जनता की राय भी ली जाए। इससे पता चलेगा कि उनके लिए देशभक्ति क्या है। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूल के अभिभावकों को पत्र लिखकर जानकारी लेंगे कि बच्चों को देशभक्ति पाठ्यक्रम क्यों पढ़ाया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घोषणा की थी कि विद्यार्थियों के मन में देशभेम पैदा करने के लिए अगले साल सरकारी स्कूलों में देशभक्ति का

घी के डिब्बों से 26 पिस्टल बरामद, दो तस्कर दबोचे

जास, नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो और अंतरराज्यीय हथियार तस्करो को दबोचा है। उनके पास से प्वाइंट 32 बोर की 26 पिस्टल व 26 अतिरिक्त मैग्जीन बरामद हुई हैं। तस्करो की बोलरो जीप को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस की चेंकिंग से बचने के लिए तस्कर हथियारों व मैग्जीन को वनस्पति घी से भरे डिब्बों के अंदर रखकर मध्य प्रदेश के भिंड से दिल्ली लाए थे। घी में रखने से पहले हथियारों को पॉलीथिन से लपेटकर तारों के जरिये बांध दिया गया था। हथियारों की आपूर्ति दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के बदमाशों की की जानी थी।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तस्करो के नाम जितेंद्र उर्फ जीतू (25) व राज बहादुर (30) हैं। जितेंद्र भिंड, मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जबकि उसका साला राज बहादुर आगरा का रहने वाला है। जितेंद्र 2013 से ही हथियारों की तस्करी से जुड़ा हुआ है। 2018 में उसने अपने साले राज बहादुर को भी इस धंधे में शामिल कर लिया। उसके पास बोलरो जीप है। साले के साथ मिलकर जितेंद्र बोलरो से हथियार दिल्ली ला रहा था। पुलिस के अनुसार, 23 सितंबर को सेल को सूचना मिली कि कुख्यात हथियार तस्कर जितेंद्र अपने एक साथी के साथ रमेशान घाट, गाजीपुर के पास किसी को हथियार आपूर्ति करने आने वाला है। पुलिस ने सूचना के आधार पर कारवाई करते हुए दोनों तस्करो को दबोच लिया।

ग्रे लाइन पर मेट्रो परिचालन की मिली मंजूरी

राब्यू, नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो की नवनिर्मित ग्रे लाइन पर सुरक्षा मानकों की जांच के बाद मेट्रो रेल संस्था आयुक्त (सीएमआरएस) ने गुरुवार शाम को इस कॉरिडोर को यात्रियों के लिए खोलने की स्वीकृति दे दी। इस लाइन पर द्वारका से नजफगढ़ के बीच जल्द मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) का कहना है कि तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी।

डीएमआरसी 30 सितंबर तक इस कॉरिडोर पर परिचालन शुरू करना चाहता है। यह फेवरीन का आखिरी कॉरिडोर है। इससे नजफगढ़ व इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र मेट्रो कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे। नजफगढ़ से दिल्ली के विभिन्न हिस्सों, नोएडा, गाजियाबाद व एनसीआर के अन्य शहरों के बीच आवागमन की सुविधा बेहतर हो जाएगी। करीब एक घंटे में लोग नजफगढ़ से मेट्रो से नोएडा पहुंच सकेंगे। उल्लेखनीय है कि द्वारका से नजफगढ़ के बीच 4.29 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इस कॉरिडोर पर तीन मेट्रो स्टेशन द्वारका, नंगली व नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें द्वारका एलिवेटेड स्टेशन है। दो अन्य स्टेशन भूमिगत हैं। द्वारका स्टेशन ब्लू लाइन के साथ इंटरचेंज स्टेशन होगा। जहां यात्री द्वारका स्टेशन पीएम 2.5 और पीएम 1.0 की सांद्रता के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चला है कि इन तीनों कॉरिडोर में प्रदूषक तत्वों में कमी आई थी।

बच्चों की दृष्टि में असली देशभक्ति

- अपने काम के प्रति ईमानदारी का भाव।
- पशु-पक्षियों की जरूरतों का ध्यान रखना।
- लोगों में जात-पात का भेदभाव न रखना।
- ईर्ष्या, अहंकार आदि न करना।
- नियमों का पालन करना।
- अच्छी आदतें अपनाना।
- कामज, पानी, बिजली बचाना।
- भारत स्वच्छ और स्वस्थ रहे।
- अच्छा ईसान बनाना।
- भाईचारा, करतूतों का पालन करना।
- प्रदूषण न फैलाना।
- महिलाओं को सम्मान देना।
- हेलमेट पहनना।

ईमानदारी से निर्वहन करें। कमेटी ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि पाठ्यक्रम को इसी हिसाब से बनाया जाएगा।

ये हैं कमेटी के सदस्य : चेयरपर्सन - मोती बाग स्कूल की प्रिंसिपल रेणु भाटिया सचिव - लेक्चरर सपना यादव सदस्य - डाइट प्रिंसिपल डा. शारदा, शिक्षिका पूजा राठी, शिक्षक अश्वय कुमार

केजरीवाल के खिलाफ भाजपा पूर्वांचल मोर्चा का प्रदर्शन



चंदगीराम अखाड़े के पास मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पानी की तेज बौछार मारकर भगाते पुलिसकर्मी। जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

भाजपा पूर्वांचल मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सुबह 11 बजे चंदगीराम अखाड़े के पास एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़े। वे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मामले में केजरीवाल द्वारा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग कर रहे थे। उन्होंने हाथों में तिरछायें ले रखी थीं जिन पर लिखा था ‘केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो।’ पुलिस द्वारा लगाए गए अवरोधों को पार कर प्रदर्शनकारी केजरीवाल के सरकारी निवास के नजदीक पहुंच गए, जहां पुलिस ने पानी की बौछारें मार कर उन्हें रोका। फिर सभी को हिरासत में लेकर थाने ले गईं। वहां से कुछ देर बाद सभी को रिहा कर दिया गया।

पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अभय वर्मा ने कहा कि क्या केजरीवाल पूर्वांचलवासियों को अवैध बांग्लादेशी, रोहिंया या विदेशी घुसपैठियों के साथ तुलना कर रहे हैं। ऐसा करना प्रवासी लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला है।

सीएम के बयान के खिलाफ भाजपा ने दर्ज कराई शिकायत : जास, नई दिल्ली : एनआरसी दिल्ली में लागू किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर प्रेश भाजपा ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्रदेश भाजपा है मीडिया रिलेशन के प्रमुख नीलकांठ बक्शी और पूर्व विधायक कपिल मिश्रा ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) नेता सीराम भारद्वाज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में लिखा



समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के दौरान जेएनयू के कुलपति प्रो. एम जगदीश कुमार और आइआइटी दिल्ली के निदेशक प्रो. वी रामगोपाल राव।

होगा। दोनों संस्थानों के छात्र पाठ्यक्रम की भी पढ़ाई भी साथ कर सकेंगे। जेएनयू में कई भाषाओं के कोर्स हैं। आइआइटी छात्र अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए सेमेस्टर में क्रेडिट भी मिलेगा। इसी तरह से जेएनयू के

किसी भी पाठ्यक्रम के छात्र आइआइटी दिल्ली में पढ़ाए जा रहे विषयों की पढ़ाई कर सकेंगे। जेएनयू में शोध के लिए एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन रिसर्च फैसिलिटी (एआइआरएफ) है, जहां सभी प्रकार के शोध का विश्लेषण किया जाता

जेएनयू ने स्पेशल सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टडीज और स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च की स्थापना की है। [आपदा प्रबंधन समेत कई तरह के शोध में दोनों संस्थान साथ मिलकर सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में और नीतियों के निर्माण में सहयोग कर सकेंगे।

— प्रो. एम जगदीश कुमार, कुलपति, जेएनयू

आइआइटी दिल्ली की विशेषता नई तकनीक विकसित करने की है तो जेएनयू बॉयोलॉजी साइंस, ह्यूमिनिटी और सोशल साइंस के क्षेत्र में काफी मजबूत है। मिलकर शोध कार्यों से देश को फायदा मिलेगा।

— प्रो. वी रामगोपाल राव, निदेशक, आइआइटी दिल्ली

है। आइआइटी के शोधकर्ता भी इसका लाभ उठा सकेंगे। आइआइटी में सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज और सेंटर ऑफ एक्सप्लैस फॉर रिसर्च ऑन क्लीन एयर है। इसमें जेएनयू के छात्र भी काम कर सकेंगे।

अगर ईदगाह थी तो इमाम के बैठने की जगह कहां : सुप्रीम कोर्ट

जिरह ► विवादित ढांचे के नीचे ईदगाह होने के दावे पर शीर्ष अदालत ने सुन्नी वक्फ बोर्ड से किया सवाल

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या मामले में एएसआइ (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की खुदाई में विवादित ढांचे के नीचे पाई गई विशाल संरचना के खंडहरों को मंदिर की जगह ईदगाह के खंडहर बता रहे सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं अन्य से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर वह ईदगाह थी तो वहां इमाम के बैठने की जगह कहां थी? हाई कोर्ट के आदेश पर विवादित स्थल की खुदाई करने के बाद दो गई रिपोर्ट में एएसआइ ने कहा है कि विवादित ढांचे के नीचे विशाल संरचना मिली है जो कि उत्तर भारत के मंदिरों से मेल खाती है।

गुरुवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं अन्य की ओर से पेश वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि खुदाई में जो बड़ी और मोटी दीवार मिली है वह दीवार ईदगाह की है। उन्होंने कहा कि यह कहना ठीक नहीं है कि वहां नीचे विशाल मंदिर था। वहीं ईदगाह क्यों नहीं हो सकती जबकि इस्लाम के मुताबिक ईदगाह में एक बड़ी सी दीवार पश्चिम में होती है। अरोड़ा ने कहा कि दीवार में आला पाया गया है जो कि मस्जिद में होता है। ईदगाह की दलीलों पर पीठ के न्यायाधीश जस्टिस एस.

उप्र उर्दू अकादमी के पुरस्कारों पर रोक

जासं, लखनऊ : उप्र उर्दू अकादमी की ओर से घोषित पुरस्कारों पर संस्कृति विभाग ने रोक लगा दी है। साथ ही मामले में जवाब तलब किया है। दरअसल, बुधवार को घोषित नाम में अकादमी की चेयरमैन आसिफा जमानी ने खुद को भी एक लाख रुपये पुरस्कार यशि वाला डॉ. सुगरा मेहंदी सम्मान दे दिया। इस पर सचिव संस्कृति जीतेंद्र कुमार ने अकादमी से पुरस्कार नियमावली के साथ आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अकादमी को तीन दिन का समय दिया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच के बाद ही पुरस्कारों के लिए भुगतान किया जाएगा।

असम में 200 और फॉरेनर ट्रिब्यूनल स्थापित होंगे

गुवाहाटी, प्रे्ट : असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से बाहर रह गए लोगों की अपीलों की सुनवाई के लिए राज्य के 33 जिलों में 200 और फॉरेनर ट्रिब्यूनल (विदेशी न्यायाधिकरण) स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है। असम में ऐसे 100 ट्रिब्यूनल पहले से काम कर रहे हैं। अंतिम एनआरसी सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। करीब 19 लाख लोग इससे बाहर रह गए हैं। उनके पास अपील करने के लिए 120 दिन का समय है। असम में एनआरसी की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरी की गई।

सीबीआइ ने कर्नाटक के तीन आइपीएस अधिकारियों से की पूछताछ

बेंगलुरु, प्रे्ट : सीबीआइ ने अलग-अलग मामलों में कर्नाटक के तीन आइपीएस अधिकारियों से पूछताछ की है। एजेंसी ने राज्य की कांग्रेस-जदएफ सरकार में नेताओं और नौकरशाहों के कथित फोन टैपिंग मामले में बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त अलोक कुमार के घर छापेमारी कर उनसे पूछताछ की। उधर, करोड़ों रुपये के आइ-मॉनिटी एडवाइजरी (आइएमए) घोटाले में पुलिस महानिरीक्षक हेमंत निंबालकर व उपायुक्त रैंक के अधिकारी अजय हिलोरी के बयान भी दर्ज किए गए। अधिकारियों के अनुसार, करीब 20 सीबीआइ अधिकारी गुरुवार की सुबह सात बजे कुमार के अड्डागोडी स्थित आवास पर पहुंचे। जांच अधिकारी कथित तौर पर कुछ पेन ड्राइव व कंप्यूटर की तलाश कर रहे थे। कुमार अभी राज्य रिजर्व पुलिस बल में एडीजी हैं। सीबीआइ ने इस मामले को बेंगलुरु पुलिस की अयोग्य ठहराए गए विधायक एएच विश्वनाथ अगस्त में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

कह के रहेंगे



110 शहरों में आठ दिसंबर को आयोजित की जाएगी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा । आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है । तीन अक्टूबर तक अभ्यर्थी फीस का भुगतान कर सकेंगे। चार से 10 अक्टूबर तक फार्म में सुधार किए जा सकेंगे ।

12 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार

12 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले देश के अलग-अलग क्षेत्रों के 12 प्रख्यात वैज्ञानिकों को वर्ष 2019 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बायोलाजिकल साइंस के क्षेत्र में आइआइएसईआर पुणे के वैज्ञानिक डॉ. के श्रीकृष्णन और एनआइआई दिल्ली के वैज्ञानिक डॉ. सोमैन बसाक को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुरुवार किसी भी संस्कृति या समुदाय के लोग हो सकते हैं। वह अनुमान लगा रहे हैं। इन सवालों पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप ये सवाल कोर्ट से क्यों पूछ रही हैं? आपको कानून के मुताबिक हाई कोर्ट में विशेषज्ञों से ये सवाल करने चाहिए थे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा कि रिपोर्ट के विपरीत अर्थ निकालने की जगह आपको विशेषज्ञों से जिह करनी चाहिए थी।

एएसआइ रिपोर्ट के लेखक पर नहीं उठा रहे सवाल : गुरुवार को यजीव धवन ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं अन्य एएसआइ रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं जबकि आज 21वीं शताब्दी है, ऐसे मे हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उस समय भी निर्माण का एलाइनमेंट उतना ही समतल होगा जैसा आज है।

कोर्ट से क्यों सवाल कर रहे हैं विशेषज्ञों से पूछते : जब अरोड़ा ने

लंबित एफआइआर नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने का आधार नहीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लंबित एफआइआर किसी को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करने का आधार नहीं हो सकती। विनोत कुमार शर्मा ने दायर याचिका में कहा था कि उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में सब इंस्पेक्टर (एसआइ) के पद पर आवेदन किया था। 5 जुलाई 2017 को आयोजित परीक्षा पास की थी। सभी औपचारिकताओं और मानकों को भी पूरा किया था। 12 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ की तरफ से नियुक्ति पत्र जारी कर उन्हें 13 मार्च को पुणे में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। उन्होंने ट्रेनिंग शुरू करने के साथ ही स्थापना फार्म में खुद पर देहज उत्पीड़न का एफआइआर दर्ज होने की जानकारी दी थी। इसके बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया।

न्यायमूर्ति एम सुरलीथर और तलवंत सिंह की पीठ ने आदेश दिया कि चार हफ्ते के अंदर सीआरपीएफ के एएसआइ की नियुक्ति की जाए। पीठ ने गृह मंत्रालय के पहली फरवरी 2012 के निर्देश का हवाला देते हुए कहा, सिर्फ केस दर्ज होना और लंबित जांच किसी की उम्मीदवारी खातिर करने का आधार नहीं हो सकती। अगर याचिका के खिलाफ दर्ज एफआइआर में कोई कार्रवाई होती है, तो सीआरपीएफ नियमानुसार कार्रवाई पर विचार कर सकती है।

पीएम मोदी, सोनिया ने मनमोहन सिंह को दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली, प्रे्ट : पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह गुरुवार को 87 साल के हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य कई नेताओं ने मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, 'हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। मैं उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।' कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बयान में कहा, 'हम राष्ट्र निर्माण, समावेशी विकास और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में मनमोहन सिंह के शानदार योगदान को याद करते हैं। उनके बेहतरीन नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि मुश्किल समय में भी भारत प्रतिबद्धित विकास की तरफ बढ़े। मौजूदा समय के शासक उनके नैसर्गिक ज्ञान से बहुत कुछ सीख सकते हैं।'

राज-नीति 3

राज-नीति

चयनित प्रतिभाओं को फरवरी-मार्च में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सम्मानित

विज्ञान-तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिलता है पुरस्कार



प्रतीकात्मक

ओसियन साइंस के क्षेत्र में आइआइटी बांबे के डॉ. सुबीराल घोस को और इंजीनियरिंग साइंस के क्षेत्र में माइक्रोसाफ्ट रिसर्च इंडिया के डॉ. मानिक वर्मा को चुना गया है। इनके अतिरिक्त मैथेमेटिकल साइंस के क्षेत्र में चेन्नई स्थित द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथेमेटिकल साइंस के डॉ. दिशांत मयूरभाई पंचोली और आइएसटी कोलकाता की डॉ. नीना गुप्ता को भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसी तरह फिजिकल साइंस के क्षेत्र में आइआइएससी बेंगलुरु के डॉ. अनंदा सिन्हा और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डॉ. शंकर घोष को चुना गया है।

भारत की तर्ज पर अब बांग्लादेश भी चलाएगा मिड डे मील योजना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

स्कूली बच्चों के ड्राप आउट और कुपोषण की समस्या से मिड-डे मील के जरिये भारत को मिली कामयाबी की गूँज अब पड़ोसी देशों को भाने लगी है। यही वजह है कि बांग्लादेश ने भी इससे निपटने के लिए अपने वहां अब भारत की तर्ज पर स्कूली बच्चों को मिड-डे मील में तैयार पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने की तैयारी है। फिलहाल इसे अमली जामा पहनाने के लिए था। 12 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ की तरफ से नियुक्ति पत्र जारी कर उन्हें 13 मार्च को पुणे में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। उन्होंने ट्रेनिंग शुरू करने के साथ ही स्थापना फार्म में खुद पर देहज उत्पीड़न का एफआइआर दर्ज होने की जानकारी दी थी। इसके बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया।

न्यायमूर्ति एम सुरलीथर और तलवंत सिंह की पीठ ने आदेश दिया कि चार हफ्ते के अंदर सीआरपीएफ के एएसआइ की नियुक्ति की जाए। पीठ ने गृह मंत्रालय के पहली फरवरी 2012 के निर्देश का हवाला देते हुए कहा, सिर्फ केस दर्ज होना और लंबित जांच किसी की उम्मीदवारी खातिर करने का आधार नहीं हो सकती। अगर याचिका के खिलाफ दर्ज एफआइआर में कोई कार्रवाई होती है, तो सीआरपीएफ नियमानुसार कार्रवाई पर विचार कर सकती है।

पीएम मोदी, सोनिया ने मनमोहन सिंह को दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली, प्रे्ट : पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह गुरुवार को 87 साल के हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य कई नेताओं ने मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, 'हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। मैं उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।' कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बयान में कहा, 'हम राष्ट्र निर्माण, समावेशी विकास और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में मनमोहन सिंह के शानदार योगदान को याद करते हैं। उनके बेहतरीन नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि मुश्किल समय में भी भारत प्रतिबद्धित विकास की तरफ बढ़े। मौजूदा समय के शासक उनके नैसर्गिक ज्ञान से बहुत कुछ सीख सकते हैं।'

जनरल रावत आज संभालेंगे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन का पदभार



बिपिन रावत

फाइल फोटो

नई दिल्ली, प्रे्ट : सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत शुक्रवार को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे। अब तक भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ इस पद को संभाल रहे थे, जो महीने के अंत में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में तीनों सेनाओं (थल, जल व वायु) के प्रमुख शामिल होते हैं। इयंमें से जो वरिष्ठतम होता है, उसे कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ आधिकारिक सूत्र ने बताया, 'वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन के रूप में सेना प्रमुख को शुक्रवार को सौंप देंगे।' चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बैठाने और बाहरी सुरक्षा खतर्ों से निपटने के लिए साक्षा रणनीति बनाने की जिम्मेदारी होती है। सेना प्रमुख रावत भी इसी साल 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वायुसेना प्रमुख धनोआ ने नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लॉबा से 29 मई को कमेटी के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया था।

- योजना का अध्ययन करने के लिए बांग्लादेश के मंत्री की अगुआई में भारत पहुंची उच्चस्तरीय टीम
- भारत की तरह स्कूली बच्चों के ड्रॉप आउट और कुपोषण जैसी समस्या से पड़ोसी देश भी है पीडित

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, बांग्लादेश भी भारत की तरह स्कूली बच्चों को तैयार किया हुआ पौष्टिक खाना देना चाहता है। इसके लिए उन्होंने 2023 तक लक्ष्य भी तय किया है। फिलहाल बांग्लादेश की इस पूरी योजना को लेकर रुचि इस्पाईल भी है, क्योंकि भारत जैसी समस्या बांग्लादेश में भी है। हर साल बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। साथ ही वह कुपोषण से भी ग्रसित है। हालांकि बांग्लादेश के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में वे अपने कुछ चुने हुए स्कूलों में पहले वाले बच्चों को खाने के लिए पैकड बिरिकेट देते हैं। उल्लेखनीय है कि देश में बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने और इस बीच दिल्ली के कुछ स्कूलों का जायजा भी लिया है। गुरुवार शाम यह टीम तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हुई, जहां स्कूली बच्चों का खाना बनाने के लिए तैयार किए गए अत्याधुनिक भोजनालय को देखेगी।

लोस चुनाव के दौरान वैध तरीके से मिला द्रमुक से चंदा : वाम दल

नई दिल्ली, प्रे्ट : भाकपा और माकपा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान द्रमुक ने उन्हें पारदर्शी तरीके से चंदा दिया था। माकपा ने चुनाव खाते में इसे दर्शाते हुए चुनाव आयोग को सौंप दिया है। द्रमुक ने चुनाव खाते पर आयोग को सौंप गए शपथपत्र में कहा है कि पिछले संसदीय चुनाव के दौरान उसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) को अंगोगुनाडु मक्कल दैसिय कांची को 15-15 करोड़ रुपए माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) को 10 करोड़ रुपये दिए थे। मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि वामपंथी पार्टियों ने अपने चुनाव खाते में शपथपत्र में इस राशि की जानकारी नहीं दी है। भाकपा महासचिव डी राजा ने गुरुवार को स्वीकार किया कि उनकी पार्टी ने द्रमुक से पैसा लिए थे। लेकिन कोष पारदर्शी तरीके से हस्तांतरित हुआ था और इसका ब्योरा चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा। भाकपा नेता ने कहा कि यह तमिलनाडु में गठबंधन राजनीति का हिस्सा था। इसमें कुछ भी अनैतिक नहीं है क्योंकि लेनदेन बैंक के जरिये हुआ। पार्टी को 40 चुनाव क्षेत्रों में काम करना था और गठबंधन के हर साझीदार को एक दूसरे के लिए काम करना था। सभी दलों के बीच लिखित समझौता हुआ था।

माकपा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि मीडिया में पार्टी के चुनावी चंदे और खर्च के बारे में आई रिपोर्ट कुछ और नहीं दुष्प्रचार है। यह माकपा को बदनाम करने के लिए तैयार की गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान मिले चंदे का उल्लेख चुनाव खाते में किया गया है। यह चुनाव खाता चुनाव आयोग को सौंपा जा चुका है।

FREE IAS COACHING
EWS/OBC/SC/ST DELHI RESIDENCE ONLY
9350933144
9958589406
11 Flat No.-22, Rajendra Park, Old Rajinder Nagar
21418 1st Floor Dr.Mukherjee Nagar, Main Road

सिंगापुर के शिक्षा मंत्री ऑंग-ये कुंग भी हिस्सा लेंगे।

गौतमलव है कि भारत और सिंगापुर के बीच साझा

हैकथन की शुरुआत पिछले साल हुई थी। उस समय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर गए हुए थे।

स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छ ऊर्जा होगी

30 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए, ईडी ने दायर की थी अभियोजन की शिकायत



भूपेंद्र सिंह हुड्डा व मोतीलाल वोरा

नए सिरे से एजेएल को 1982 की दर (91 रुपये प्रति वर्ग मीटर) और ब्याज के साथ फर्जी तरीके से आवंटित कर दिया। एजेंसी ने कहा था कि 2005 में इस पुनः आवंटन से एजेएल को अनुचित फायदा हुआ। ईडी के मुताबिक इस से पूछताछ की थी। पंचकुला स्थित यह भूखंड सेक्टर-6 में सी-117 नंबर एजेएल को आवंटित किया गया था। इसे पिछले साल ईडी ने कुर्क कर लिया था। एजेएल को कथित तौर पर नेहरू-गांधी परिवार के सदस्यों सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा संचालित किया जाता था। यह गुप लोग इससे बाहर रह गए हैं। उनके पास अपील करने के लिए 120 दिन का समय है। असम में एनआरसी की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरी की गई।

टैप किए जाने और जासूसी की शिकायत की थी। येदियुरप्पा ने 19 अगस्त को इसकी

सीबीआइ जांच की घोषणा की थी। बेंगलुरु के मौजूदा पुलिस आयुक्त भास्कर राव समेत कुछ अधिकारियों ने भी फोन टैपिंग की शिकायत की थी। इसी मामले में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर राव किसी मध्यस्थ के साथ बेंगलुरु पुलिस आयुक्त पद के लिए लॉबींग करते हुए सुने गए।

आइएमए घोटाले के शिकार ज्यादातर मुसलमान : आइएमए समूह ने लाखों लोगों से पॉली स्क्रीम के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी की है। इनमें ज्यादातर मुसलमान हैं। आरोप है कि लोगों को भ्रष्टाचिक तरीके से निवेश पर बेहतर रिटर्न का झरोसा दिया गया था। सीबीआइ ने इस मामले में आइएमए समूह के प्रबंध निदेशक व ठगी के मास्टर माईंड मंसूर खान, चार सहयोगी कंपनियों व 24 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नेताओं व नौकरशाहों को कथित संलिप्तता के कारण यह मामला चर्चा में रहा था।

बड़ा कदम

भारत में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है, इसी क्रम में सरकार अन्य देशों के साथ समझौते कर रही है

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव आर सुब्रमण्यम ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी। साथ ही भारत-सिंगापुर के बीच 28 और 29 सितंबर को आइआइटी मद्रास में आयोजित होने वाले दूसरे साझा हैकथन का भी पलान किया। उन्होंने बताया कि इसके विजेताओं और प्रतिभागियों को 30 सितंबर को आइआइटी मद्रास में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कृत करेंगे। इस दौरान वह आइआइटी के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे। इस आयोजन में

जमानत के लिए अब हाई कोर्ट पहुंचे शिवकुमार

जासं, नई दिल्ली : मनी लाँडिंग के मामले में आरोपित कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने गुरुवार को हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की। इसमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है और खराब स्वास्थ्य की दलील देते हुए जमानत मांगी है। निचली अदालत ने बुधवार को शिवकुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ईडी उनकी जमानत का लगातार विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि मामले की जांच बेहद गंभीर प्रड़ाव पर है और ऐसे में जमानत पर बाहर आकर बच जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी का दावा है कि शिवकुमार की करोड़ों 800 करोड़ रुपये की संपत्ति का कोई हिसाब-किताब नहीं है। वहीं, तिहाड़ जेल संख्या-सात में बंद डीके शिवकुमार से गुरुवार को कांग्रेस नेताओं अहमद पटेल, आनंद शर्मा, डीके सुरेश व केसी वेणुगोपाल ने मुलाकात की।

क्या है नारद स्टिंग कांड

यह स्टिंग ऑपरेशन 2014 में किया गया था, हालांकि 52 घंटे की अवधि वाला इसका वीडियो फूटूज 2016 में बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक न्यूज पीटल पर अपलोड किया गया था, जिससे बंगाल की राजनीति में तहलका मच गया था। 2017 में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर माफिया की जांच अपने हाथों में लेते हुए सीबीआइ ने तृणमूल के 12 नेताओं के खिलाफ 'केस दर्ज किया था, जिसमें सांसद, राज्य के मंत्री और मिर्जा शामिल हैं। मैथ्यू सैमुअल्स ने दावा किया था कि तृणमूल के राज्यसभा सदस्य केडी सिंह ने इस स्टिंग के लिए फंडिंग की थी। सीबीआइ के अलावा ईडी भी इसकी जांच कर रही है।

ये हैं आरोपित : नारद कांड में तृणमूल के मंत्री सुब्रत मुखर्जी, फिरोहद इकॉमि, सांसद प्रसन्न बनर्जी, तत्कालीन सांसद सुल्तान अहमद, विधायक इकबाल अहमद, सांसद सौगत राय, सांसद काकुली घोष दस्तौदार, विधायक मन्दन मित्रा, मुकुल राय, मंत्री व तत्कालीन मेयर शोभन वटर्जी, सांसद अपरराज पोद्दार व तत्कालीनी सांसद शुभेन्द्र अधिकारी के नाम हैं। सुल्तान अहमद का निधन हो चुका है, मुकुल राय और शोभन वटर्जी भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

शोध और नवाचार से मिटेगी वैश्विक दूरियां

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

शोध और नवाचार को लेकर भारत ने सिंगापुर के बाद अब दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी साझा हैकथन को लेकर रुचि दिखाई है। फिलहाल इसे लेकर भारत ने बिस्मटेक देशों सहित कनाडा, आस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों से संपर्क किया है। हालांकि इनमें बिस्मटेक देशों के साथ जल्द ही साझा हैकथन की संभावना जताई गई है। मौजूदा समय में बिस्मटेक संगठन में भारत के अलावा भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड जैसे सात देश शामिल हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव आर सुब्रमण्यम ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी। साथ ही भारत-सिंगापुर के बीच 28 और 29 सितंबर को आइआइटी मद्रास में आयोजित होने वाले दूसरे साझा हैकथन का भी पलान किया। उन्होंने बताया कि इसके विजेताओं और प्रतिभागियों को 30 सितंबर को आइआइटी मद्रास में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कृत करेंगे। इस दौरान वह आइआइटी के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे। इस आयोजन में

भारत ने सिंगापुर के बाद दुनिया के अन्य देशों के साथ साझा हैकथन को लेकर दिखाई रुचि

आइआइटी मद्रास में 28-29 सितंबर को होगा सिंगापुर के साथ हैकथन, 30 को पीएम विजेताओं को करेंगे पुरस्कृत



फाइल फोटो

सिंगापुर के शिक्षा मंत्री ऑंग-ये कुंग भी हिस्सा लेंगे। गौतमलव है कि भारत और सिंगापुर के बीच साझा हैकथन की शुरुआत पिछले साल हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर गए हुए थे। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छ ऊर्जा होगी

पूर्व हॉकी कप्तान संदीप सिंह और ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त भाजपा में शामिल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

हरियाणा में विधानसभा के लिए बने चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ियों को रास आ रही है। ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए।

दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में गुरुवार को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला ने दोनों खिलाड़ियों के साथ ही सिरसा के कालावाली क्षेत्र से अकाली दल के विधायक बलकौर सिंह को भी पार्टी की सदस्यता पचीं सौंपी। इनसे पहले महिला पहलवान बबीता फोगाट और पैराओलंपियन दीपा मलिक भी भाजपा में शामिल हो चुकी हैं।

सूत्रों के अनुसार संदीप सिंह को कुरुक्षेत्र के पिहीवा विधानसभा क्षेत्र से और योगेश्वर दत्त को सोनीपत के बरोदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। योगेश्वर दत्त खेल कोटे से हरियाणा पुलिस में डीएसपी हैं मगर उन्होंने बुधवार को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था।

खेल भावना की अनूठी मिसाल



भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त, पूर्व हॉकी कप्तान संदीप सिंह व बलकौर सिंह।

जागरण

पेश कर चुके हैं योगेश्वर: 2012 में लंदन ओलंपिक के एक मैच में रूस के खिलाड़ी को रजत और योगेश्वर दत्त को कांस्य पदक मिला था। बाद में रूस का खिलाड़ी डोप टेस्ट में फेल हो गया, जिससे योगेश्वर का पदक कांस्य से

रजत हो गया। मगर योगेश्वर ने सदस्यता दिखाते हुए रजत पदक लेने से इन्कार कर दिया।

संदीप सिंह के जीवन पर बनी है सूरमा फिल्म: ओलंपियन संदीप सिंह ने

युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए अपना अलग अभियान शुरू किया हुआ है। संदीप और उनके पिता की प्रेरणा से बहुत से लड़के-लड़कियां आगे बढ़ रहे हैं। संदीप के जीवन पर सूरमा फिल्म भी बनी है।

कर्नाटक में अयोग्य विधायकों पर फैसला होने तक उपचुनाव टला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कर्नाटक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर जारी असमंजस पर विराम लग गया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह कर्नाटक में होने जा रहे 15 सीटों पर उपचुनाव को फिलहाल टालने को तैयार है। कर्नाटक विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आयोग ने यह बात कही। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अयोग्य विधायकों पर फैसला नहीं दे देता, तब तक के लिए कर्नाटक उपचुनाव स्थगित किया जाता है।

असल में सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के 17 विधायकों की अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका लंबित है जिस पर 22 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कर्नाटक में विधानसभा की 15 सीटों पर 21 अक्टूबर को उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की थी। मर्तो की गिनती 24 अक्टूबर को होनी थी। करीब 17 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था जिसके चलते ये सीटें खाली हुई थीं। अयोग्य ठहराए गए इन 17 विधायकों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इनकी मांग थी कि उन्हें उपचुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई दिशानिर्देश या अंतिम आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस याचिका पर 22

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने उपचुनाव टालने पर जताई सहमति

शीर्ष अदालत में विधायकों की याचिका पर 22 अक्टूबर को सुनवाई

चुनाव टालने का फैसला अभूतपूर्व : कांग्रेस

नई दिल्ली, आइएनएस : कर्नाटक में 15 सीटों पर उप चुनाव टालने के फैसले को कांग्रेस ने अभूतपूर्व बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दलबदल कर सरकार गिराने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने का स्पीकर का फैसला सही था। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले पर रोक नहीं लगाई है, इसका मतलब है कि स्पीकर का आदेश सही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले 70 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह कानून निर्धारित कर रखा था कि वे चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 'अब सुप्रीम कोर्ट खुद चुनाव आयोग द्वारा अधिस्थिति चुनावों में हस्तक्षेप कर रहा है। मेरे लिए यह संवैधानिक रूप से अजीब है। सुप्रीम कोर्ट सही है क्योंकि वे अंतिम हैं और इससे आगे कोई अपील नहीं है।'

अक्टूबर को सुनवाई होनी है। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने फिलहाल कर्नाटक में उपचुनाव टालने का फैसला किया है।

राज्यसभा की दो सीटों पर उपचुनाव 16 अक्टूबर को

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और बिहार से राज्यसभा की एक-एक सीटों पर उपचुनाव की घोषणा गुरुवार को कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेटमलानी के निधन से रिक्त हुई राज्यसभा के दो सीटों पर उपचुनाव 16 अक्टूबर को होगा। इसी दिन परिणाम आ जाएंगे।

चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, 27 सितंबर को दोनों सीट के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। उम्मीदवार आर अक्टूबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। नाम वापसी की अंतिम तिथि नौ अक्टूबर तक की गई है। मतदान 16 अक्टूबर को सुबह नौ से शाम चार बजे तक होगा। उल्लेखनीय है कि जेटली उत्तर प्रदेश से उच्च सदन में भाजपा के सदस्य थे जबकि जेटमलानी बिहार से राजद के सदस्य थे। अरुण जेटली का राज्य सभा में कार्यकाल दो अप्रैल 2024 तक था। उनका निधन 24 अगस्त को हो गया था। इसी तरह उच्च सदन में जेटमलानी का कार्यकाल सित जुलाई 2022 तक था। उनका निधन आठ सितंबर को हुआ था।

झाबुआ उपचुनाव के लिए 29 को प्रत्याशी घोषित कर सकती है भाजपा

नईदुनिया, भोपाल : अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित मध्य प्रदेश के झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 29 सितंबर को प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह विदेश प्रवास के बाद गुरुवार को भोपाल पहुंचे। लौटने के बाद सिंह ने झाबुआ के प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा नेताओं से चर्चा की।

माना जा रहा है कि भाजपा पहले कांग्रेस के बागियों का रझाना देख रही है। इसके बाद ही वह प्रत्याशी तय करेगी। खासतौर से भाजपा की नजर 2008 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने जैविवर मेड़ा पर है। मेड़ा ने 2018 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। इसके चलते भाजपा के जीएसए डामोर को विजय मिली थी। भाजपा चाहती है कि ऐसे ही हालात उपचुनाव में भी बन जाएं तो उसकी जीत आसान हो जाएगी। ये सारे समीकरण देखने के बाद 29 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में झाबुआ के प्रत्याशी पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है।

गुजरात में कांग्रेस फिर महात्मा गांधी के सहारे

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : गुजरात में अपने खोए जनाधार को हासिल करने के लिए कांग्रेस एक बार फिर महात्मा गांधी के सहारे है। गांधी जयंती से पहले शुक्रवार को दांडी व पोरबंदर से यात्रा शुरू कर कांग्रेस नेता जनता से संपर्क साधने को पहल करेंगे। गांधी जयंती पर कांग्रेस नेता अहमद पटेल भी आयोजन में शामिल होंगे।

गुजरात कांग्रेस प्रभारी राजीव सावत की उपस्थिति में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विचारों के प्रचार-प्रसार तथा जनता से संपर्क साधने के लिए गुजरात कांग्रेस शुक्रवार को दांडी व पोरबंदर से गांधी संदेश यात्रा करना करेगी।

इस बाइक यात्रा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा दांडी में तथा नेता विपक्ष परेश धनाणी पोरबंदर में हरी झंडी दिखाएंगे। दोनों नेता इस यात्रा में शामिल भी होंगे। दोनों यात्राएं दो अक्टूबर को अहमदाबाद के कोचबक आश्रम पहुंचेंगी, जहां से करीब आठ किलोमीटर लंबी पदयात्रा कर सभी लोग गांधी आश्रम पहुंचेंगे।

गांधी जयंती पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद अहमद पटेल भी इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया गया था।



फाइल

कुलदीप ने की भजनलाल समर्थकों की पैरवी

हरियाणा जनहित कांग्रेस के पार्टी में विलय के बाद कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई चर्चा में हैं। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हुड्डा का नेतृत्व स्वीकार करने से मना कर दिया था, लेकिन दो दिन पहले ही कुलदीप की हुड्डा से मुलाकात हुई है। राज्य कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में कुलदीप बिश्नोई ने हजकां से कांग्रेस में आए कार्यकर्ताओं को सम्मान दिए जाने तथा टिकटों में उनका ख्याल रखने का सुझाव दिया है।

अच्छे संबंध हैं, लेकिन तंत्र अब न तो सैलजा और न ही हुड्डा के किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तंत्र ने राज्य में ठीक उसी तरह से अपनी समानांतर गतिविधियां चला रखी हैं, जिस तरह से हुड्डा चलाया करते थे। तंत्र ने चुनाव समिति,

तंत्र ने पिछड़े वर्ग के लिए अलग से मांगे 15 टिकट

हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंत्र से पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पसंद के उम्मीदवारों की जानकारी चाही है। राज्य में 17 विधानसभा सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। तंत्र ने इन सीटों के अलावा 15 विधानसभा सीटों पर पिछड़े

वैश्य, ब्राह्मण और राजपूतों पर रखा जाए टिकट का फोकस

हरियाणा कांग्रेस राज्य में टिकटों का बंटवारा करते हुए जातीय समीकरणों के साथ-साथ जीतने वाले उम्मीदवारों पर दांव खेलेगी। राज्य चुनाव समिति की बैठक में कई नेताओं ने सझाव दिया कि वैश्य, ब्राह्मण और राजपूत जातिवादी के लोगों को अधिक से अधिक टिकट दिए जाएं। किसी एक जाति विशेष के लोगों के टिकट पर इन नेताओं ने आपत्ति जताई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सुझाव दिया है कि वैश्य व पंजाबी समुदाय भले ही आरएसएस के साथ रहा हो, लेकिन अब यह समुदाय कांग्रेस को चाहता है।

चुनाव प्रचार समिति और चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की बैठकों से भी किनारा कर रहा है। बृहस्पतिवार को दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक थी, लेकिन तंत्र दिल्ली में होते हुए भी इस बैठक में शामिल नहीं होने गए। तंत्र ने अपने

समर्थकों की दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में अलग से बैठक बुला रखी थी। इस बैठक को हालांकि, कांग्रेस के आइटी विंग की बैठक बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि तंत्र प्रदेश में हुड्डा का साथ नहीं देंगे।

कांग्रेस ने 100 प्रत्याशियों के नाम तय किए

नई दिल्ली, प्रे्ट : कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीसीसी) ने 21 अक्टूबर को होने जा रहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक 100 निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। प्रत्याशियों का नाम तय करने के लिए गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बार बैठक हुई। कुछ दिनों पहले हुई अपनी बैठक में सीसीसी ने करीब 65 प्रत्याशियों के नाम की मंजूरी दी थी। गुरुवार की बैठक में लगभग 30 नामों पर सहमति बनी। बैठक के बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट की संतुष्टादाताओं को बताया कि स्क्रूनिंग कमेटी द्वारा 45 सीटों के लिए नाम भेजे गए थे और 32 को मंजूरी दी गई है। सूत्रों ने कहा कि शेष सीटों के प्रत्याशियों के नाम भी जल्दी ही तय कर दिए जाएंगे। सतारा लोकसभा क्षेत्र उपचुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज वट्ठाल के नाम पर भी विचार किया गया। राकांपा सांसद उदयरराज भोसले के भाजपा में वले जाने के कारण यह सीट खाली हो गई है।

अनुमति नहीं दी गई और वहीं खाना मंगाया गया। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगेगी।

आज ईडी कार्यालय जाएंगे शरद पवार, रोके भी जाएंगे

राज्य ब्यूरो, मुंबई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 25,000 करोड़ रुपये के महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक के घोटाले में आरोपित पारटवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार शुक्रवार को मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में हाजिर नहीं होने देगा। हालांकि राकांपा नेता शरद पवार ने शुक्रवार को ईडी के दफ्तर में घुसने का एलान कर दिया है। उन्होंने राकांपा कार्यकर्ताओं से ईडी कार्यालय के बाहर भीड़ न लगाने की अपील की है।

महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक में हुए 25,000 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शरद पवार एवं उनके भतीजे अजीत पवार सहित करीब 70 नेताओं के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। हालांकि ईडी की तरफ से बुधवार को ही स्पष्ट कर दिया गया है कि उनकी ओर से राकांपा अध्यक्ष को कोई समन नहीं भेजा गया है।

लेकिन पवार ने अपनी तरफ से ही शुक्रवार को दो बजे ईडी कार्यालय पहुंचकर उसकी मेहमाननवाजी स्वीकार करने की घोषणा कर दी थी। गुरुवार को उन्होंने टवीट करके अपनी

महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक के घोटाले में आरोपित राकांपा अध्यक्ष बयान देने विन बुलाए पहुंचेंगे

इस घोषणा की पुष्टि की है। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया कि वे ईडी कार्यालय के बाहर भीड़ लगाकर लोगों को तकलीफ न होने दें। बता दें कि पिछले माह 22 अगस्त को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को पूरा एक दिन ईडी कार्यालय में गुजराना पड़ा था।

मांना जा रहा है कि शरद पवार बिना बुलाए ईडी कार्यालय जाकर अपनी ओर से इसे में उहें विपक्ष के बयान देने का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। विपक्ष का मानना है कि इस मुद्दे पर 78 वर्षीय पवार के पक्ष में सहानुभूति जुटाकर भाजपा-शिवसेना के पक्ष में चल रही लहर को काट ढूंढी जा सकती है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सचिव संजय दत्त ने इसे राजनीतिक

बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई करार देते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से पूरे देश में विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।

हरियाणा में भाजपा नहीं करेगी अकाली दल से समझौता

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली: हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हित साधने के लिए दाव-पेंच इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बेशक पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से चुनावी समझौता है, मगर हरियाणा में एसवाईएल नहर निर्माण के मुद्दे पर दोनों पार्टियों के मत भिन्न हैं। भाजपा अब अकाली दल से कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। वहीं 2014 में सिरसा जिले के कालावाली विधानसभा क्षेत्र से जीते एकमत अकाली विधायक बलकौर सिंह भी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। गुरुवार नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने बलकौर सिंह को पार्टी में शामिल किया। **बाधक रहा एसवाईएल का मुद्दा:** सतलुज यमुना लिंक नहर निर्माण हरियाणा का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। इंडियन नेशनल लोकदल को पार्टी में शामिल व जनजा भी इस मुद्दे पर हरियाणा के हितों को लेकर मुखर है। भाजपा के सामने शिरोमणि अकाली दल के साथ समझौते में सबसे बड़ी बाधा एसवाईएल नहर निर्माण का मुद्दा ही है।

चुनावों में आचार संहिता का पालन करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मर्स

नई दिल्ली, प्रे्ट : चुनाव आयोग ने गुरुवार को बताया कि फेसबुक, ट्विटर और वाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मर्स ने सभी चुनावों में स्वेच्छा से आचार संहिता का पालन करने पर सहमति व्यक्त की है। इन चुनावों में आगामी महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभा चुनाव और विभिन्न उपचुनाव भी शामिल हैं।

हालिया लोकसभा चुनावों से पहले 20 मार्च को प्रभावी हुई इस आचार संहिता को ऐसे पेड़ एडवटराइनमेंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार किया गया था जो चुनाव आयोग के मानकों का उल्लंघन करते हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इंटरनेट एंड मोबाइल एप्सोसिएशन ऑफ इंडिया (आइएएमएआइ) ने अपने सदस्यों की ओर से स्वेच्छिक रूप मिल रहा है। विपक्ष का मानना है कि इस मुद्दे पर 78 वर्षीय पवार के पक्ष में सहानुभूति जुटाकर भाजपा-शिवसेना के पक्ष में चल रही लहर को काट ढूंढी जा सकती है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सचिव संजय दत्त ने इसे राजनीतिक

बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई करार देते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से पूरे देश में विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस संहिता के मुताबिक, मतदान खत्म होने से पूर्व के 48 घंटों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मर्स पर किसी भी तरह के राजनीतिक प्रचार की अनुमति नहीं दी जा सकती।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा के चुनावी रण में कांग्रेस जब सत्तारूढ़ भाजपा से टकराने की तैयार है, ऐसे समय में कांग्रेस के निर्वतमान प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अशोक तंत्र के बदले सुर सामने आए हैं। अशोक तंत्र ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कु. सैलजा और केंटरन अजय यादव पर जमकर हमले बोले। तंत्र ने कहा कि बार-बार चुनाव लड़ने और हारने वाले लोगों को इस बार घर बैठ दिया जाना चाहिए।

नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में बृहस्पतिवार को कांग्रेस आइटी सेल की बैठक में अशोक तंत्र ने पार्टी की लोकसभा चुनाव से पहले और मौजूदा स्थिति के बारे में फौंडवैक बातचीत के बाद कुछ मीडिया कर्मियों से बातचीत में तंत्र ने हुड्डा पर हमला किया। हुड्डा का नाम लिए बगैर तंत्र ने कहा कि कुछ लोग जैसे पहले करते थे, अब वैसा न करें तो हमारी जीत तय है। कुरुदने पर तंत्र ने कहा कि कुछ

बबीता फोगाट के लिए दादरी में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। उन्हें बाइंडा और दादरी में से किसी एक पर चुनावी रण में उतारा जा सकता है। योगेश्वर दत्त भी टिकट का भरोसा मिलते ही डीएसपी की नौकरी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वे सोनीपत जिले की बरोदा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बरोदा से फिलहाल कांग्रेस के विधायक श्रीकृष्ण हुड्डा हैं। पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा यदि अपने पिता भूपेंद्र हुड्डा की परंपरागत गढ़ी सांपला किलोई सीट से चुनाव लड़े तो हुड्डा के लिए बरोदा को सेफ माना जा रहा था, लेकिन अब हुड्डा को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है।

भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ संदीप सिंह ने भी भगवा पटका पहन लिया। भाजपा उन्हें पिहीवा हलके से चुनावी मैदान में उतार सकती है। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर चेतन शर्मा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं।

भाजपा व जदयू बिहार में दस चुनावों से निभाते आ रहे दोस्ती

अरविंद शर्मा, पटना : बिहार में महलगठबंधन के घटक दल एक आम चुनाव भी मजबूती से नहीं लड़ पाए और बिहारवर्ष की ओर बढ़ गए। किंतु भाजपा-जदयू की दोस्ती की कहानी 23 साल पुरानी है। इस दौरान बीच के डेढ़ साल को अगर अपवाद मान लिया जाए तो हार या जीत दोनों हालात में दोनों ने एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। बिहार में रणज गठबंधन की नींव 1995 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू की करारी हार के बाद रखी गई थी।

नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस को लेकर 2015 में महलगठबंधन बनाया था। सत्ता में भी आए। किंतु डेढ़ साल में ही स्वार्थ का प्रवेश हो गया और यह टिक नहीं पाया। नीतीश के हटने के बाद लालू प्रसाद ने कई और दलों को जोड़ा। किंतु कुनबा जितना बड़ा होता गया, टकराव उतना बढ़ता गया। अतः उपचुनाव के पहले ही पांच दलों का कुनबा छिन्न गया। राजनीतिक विफलपक्ष और बिहार में एडीआर के प्रमुख राजीव कुमार के मुताबिक मकसद अगर स्वार्थ का नहीं हो तो बुरे दिनों की दोस्ती ज्यादा कामयाब और टिकाऊ होती है। भाजपा-जदयू पर यह फाटला पूरी तरह लागू हुआ। 1996 में दोनों ने मिलकर बिहार में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। चुनावों में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली। यही वजह है कि 2014 में बिछड़ने के बाद भी दोनों के दिल दूसरे के लिए धड़कते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब दोनों दल दोबारा साथ आए तो अन्य सहयोगी दलों की ज्यादा परवाह नहीं रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़े उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा को भाजपा-जदयू के फोल्डर से अलग होना पड़ गया। 1996 के लोकसभा चुनाव में के वक्त बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था। लोकसभा की 54 सीटें हुआ करती थी। दोनों ने पहले प्रयास में 23 सीटें जीत लीं। भाजपा को 18 और समता पार्टी को पांच सीटें मिली थीं। दो साल बाद 1998 का परिणाम भी बेहतर रहा। 1 अगले ही साल 1999 के लोकसभा चुनाव में बिहार ने केंद्र में रणजी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। समता पार्टी तब जदयू के रूप में तब्दील हो चुकी थी। नीतीश कुमार ने वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में सत्ता दिनों के लिए लालू-रावड़ी को सत्ता से बेदखल करके संकेत दे दिया कि आगे कुछ भी हो सकता है। हालांकि, 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा-जदयू को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जदयू को छह और भाजपा को पांच सीटों से ही संतोष करना पड़ा। फिर भी हारना नहीं टूटा। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में रणज और मजबूत हुआ और आखिरकार नवंबर 2005 में राजद को सत्ता से बेदखल कर दिया।

असंतोष

हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका में पहुंचे अशोक तंत्र सैलजा व हुड्डा के समानांतर चला रहे गतिविधियां

हरियाणा में भाजपा के साथ अपनों से भी जूझ रही कांग्रेस

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

हरियाणा में कांग्रेस दो मोर्चों पर जूझ रही है। पहला मोर्चा भाजपा के साथ है तो दूसरे मोर्चे पर खुद कांग्रेस नेता जमे हुए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जिस भूमिका में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, अब विधानसभा चुनाव के दौरान ठीक उसी भूमिका में हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डा. अशोक तंत्र आ गए हैं। हुड्डा और तंत्र के बीच चल रही तनातनी का असर कांग्रेस के विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय है।

अशोक तंत्र जब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब उन्हें पद से हटाने के लिए हुड्डा समर्थक विधायकों ने तगड़ी मोर्चेबंदी की। हुड्डा उन्हें अध्यक्ष के पद से हटवाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन गुटबाजी अभी भी बरकरार है। तंत्र के अध्यक्ष रहते हुए हुड्डा कभी उनके कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए। न ही हुड्डा समर्थक विधायक तंत्र के किसी कार्यक्रम में दिखाई दिए। यही स्थिति अब अशोक तंत्र की है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर हालांकि, राज्यसभा सदस्य कु. सैलजा की नियुक्ति हो चुकी है और सैलजा के तंत्र के साथ



फाइल

तंत्र ने पिछड़े वर्ग के लिए अलग से मांगे 15 टिकट

हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंत्र से पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पसंद के उम्मीदवारों की जानकारी चाही है। राज्य में 17 विधानसभा सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। तंत्र ने इन सीटों के अलावा 15 विधानसभा सीटों पर पिछड़े

वैश्य, ब्राह्मण और राजपूतों पर रखा जाए टिकट का फोकस

हरियाणा कांग्रेस राज्य में टिकटों का बंटवारा करते हुए जातीय समीकरणों के साथ-साथ जीतने वाले उम्मीदवारों पर दांव खेलेगी। राज्य चुनाव समिति की बैठक में कई नेताओं ने सझाव दिया कि वैश्य, ब्राह्मण और राजपूत जातिवादी के लोगों को अधिक से अधिक टिकट दिए जाएं। किसी एक जाति विशेष के लोगों के टिकट पर इन नेताओं ने आपत्ति जताई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सुझाव दिया है कि वैश्य व पंजाबी समुदाय भले ही आरएसएस के साथ रहा हो, लेकिन अब यह समुदाय कांग्रेस को चाहता है।

चुनाव प्रचार समिति और चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की बैठकों से भी किनारा कर रहा है। बृहस्पतिवार को दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक थी, लेकिन तंत्र दिल्ली में होते हुए भी इस बैठक में शामिल नहीं होने गए। तंत्र ने अपने

समर्थकों की दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में अलग से बैठक बुला रखी थी। इस बैठक को हालांकि, कांग्रेस के आइटी विंग की बैठक बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि तंत्र प्रदेश में हुड्डा का साथ नहीं देंगे।

बार-बार हारने वाले कांग्रेसियों को घर बैठाए हाईकमान : तंत्र

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा के चुनावी रण में कांग्रेस जब सत्तारूढ़ भाजपा से टकराने की तैयार है, ऐसे समय में कांग्रेस के निर्वतमान प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अशोक तंत्र के बदले सुर सामने आए हैं। अशोक तंत्र ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कु. सैलजा और केंटरन अजय यादव पर जमकर हमले बोले। तंत्र ने कहा कि बार-बार चुनाव लड़ने और हारने वाले लोगों को इस बार घर बैठ दिया जाना चाहिए।



डॉ. अशोक तंत्र।

फाइल

लोगों को मेरी शकल पसंद नहीं है। मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी की परेशानी मेरी वजह से बढ़ पाई तो मुझे तकलीफ होगी। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश अध्यक्ष के नाते पांच साल आठ माह काम किया। अब 15 दिन इन लोगों को जमकर काम करना चाहिए। किरण चौधरी के नेतृत्व वाली चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की बैठक से दूरी बनाने के सवाल पर तंत्र ने कहा कि 18 अशोक को रोहकाम में हुई एक रैली के दौरान चुनाव घोषणा पत्र तैयार हो चुका है। हुड्डा पर निशाना साधते हुए तंत्र ने कहा कि इस रैली में मुख्यमंत्री भी घोषित किया गया था।

आतंक को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है पाक

दो टूक ▶ विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, हकीकत से रूबरू कराने पर मुकरने की नीति पर भी चलता है पड़ोसी मुल्क

भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर बुनियादी मुद्दा नहीं, कई मुद्दों का हिस्सा

न्यूयॉर्क, एजेंसियां : पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत अपने 'बेहद कुटिल' पड़ोसी से बात नहीं कर सकता। पाकिस्तान बातचीत का भारत पर दबाव बनाने के लिए आतंकवाद को एक कानूनी हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है और हकीकत से रूबरू कराने पर भी उससे मुकर जाने की नीति पर अमल करता है।

जयशंकर बुधवार को यहां थिंक टैंक 'कार्गिसिल ऑन फरिन रिलेशंस' के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर बुनियादी मुद्दा नहीं है। यह हमारे बीच के कई मुद्दों का एक हिस्सा है।'

विदेश मंत्री ने कहा, 'निश्चित ही हर कोई अपने पड़ोसी से बात करना चाहता है। मुद्दा यह है कि मैं एक ऐसे देश से बात कैसे कर सकता हूँ जो आतंकवाद फैलाता है और साफ-साफ कह जाए तो हकीकत से रूबरू कराने पर उससे इन्कार करने की नीति अपनाता है।' सीमापार से रची साजिश और वहीं से भारत में अंजाम दिए गए आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए



अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना सत्र के इतर विदेश मंत्री एस. जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात हुई ।

जयशंकर ने कहा कि मुंबई जूबल नवंबर 2008 के अतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए हज़ार मील ही दूर है। वह कश्मीर से महज कुछ

दोनों देशों के क्रिकेट संबंध पर उन्होंने उरी, पठानकोट और पुलवामा का हवाला देते हुए कहा, 'यदि किसी संबंध पर आतंकवाद,

आत्मघाती हमले, हिंसा का विमर्श हावी हो और फिर आप कहें, 'अच्छा चलिए, अब साथ में चाय पीते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं।'

पांच अगस्त से पहले कश्मीर में बहुत गड़बड़ था : जयशंकर ने कहा कि पांच अगस्त से पहले जम्मू-कश्मीर में बहुत गड़बड़ था, जिसे दूर करने के लिए अनुच्छेद-370 खत्म करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने दो विकल्प थे। पहला यह कि कश्मीर में पिछले 70 सालों से जो चला रहा था उसी पर आगे बढ़ना और दूसरा सबकुछ ठीक करने के लिए कुछ अलग निर्णय करना। जो चला आ रहा था उसका कोई लाभ नहीं नजर आ रहा था। इसलिए बदलाव के लिए दूसरा विकल्प चुना गया। हम मानते हैं कि यह आसान काम नहीं है।

भारत में धर्मान्तरण के खतरे में नहीं : विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में धर्मान्तरण के कोई खतरा नहीं है और इसे सामाजिक लोकाचार से बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि अगर समाज का लोकाचार धर्मान्तरण नहीं है तो कानून की धाराएं उसे धर्मान्तरण नहीं बना सकती। मेरा मानना ​​है कि भारत का लोकाचार, खासकर हिंदुओं का लोकाचार धर्मान्तरण और बहुलवादी है।

भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों की यह शुरुआत है : एक सवाल पर जयशंकर ने कहा

कि भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंधों में बदलाव की शुरुआत हुई है। दोनों देश अपने रणनीतिक संबंधों को बहुत अधिक मजबूत बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के संबंधों में रचनात्मक बदलाव हुआ है। ज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है।

चीन और यूरोप की नकल नहीं कर सकता भारत : विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत चीन और यूरोप की नकल नहीं कर सकता। उसे अपने विकास के मार्ग खुद बनाने होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले पांच साल में भारत में मानव विकास सूचकांक में बहुत ही बदलाव देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं, आवास और साक्षरता के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में भारत में व्यापक सामाजिक-आर्थिक बदलाव आए हैं।

चीनी विदेश मंत्री से मिले जयशंकर : संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने टवीट किया, 'चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिला। हमारे संबंधों की समीक्षा के लिए मुलाकात सार्थक रही।' जयशंकर ने अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, उक्रेन, इटली और बेलारूस के विदेशमंत्रियों से भी मुलाकात की और द्विपक्षी संबंधों पर चर्चा की।

कैरेबियाई देशों को 15 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा भारत

न्यूयॉर्क, प्रे़ : संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर भारत ने बुधवार को कैरेबियाई देशों के संगठन 'कैरीकॉम' के नेताओं की पहली बैठक की मेजबानी की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'कैरीकॉम' देशों में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 1.4 करोड़ डॉलर के अनुदान की घोषणा की। साथ ही उन्होंने इन देशों को सौर व नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यों के लिए 15 करोड़ डॉलर का कर्ज देने का भी एलान किया।

आधिकारिक विज्ञापित के मुताबिक, इस बैठक से कैरेबियाई देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक और गर्मजोशी भरे रिश्तों को नई गति मिली है। 'कैरीकॉम' के चेयरमैन और सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री एलेन चेस्टनेट ने बैठक की सहअध्यक्षता की। बैठक में मोदी ने गुयाना के जार्जटाउन में रीजनल सेंटर फॉर एक्सलेंस इन इंफ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बेलेज़ में रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करने की भी घोषणा की। उन्होंने 'कैरीकॉम' के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि इन देशों में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग कैरेबियाई देशों के साथ दोस्ती में सेतु का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने 'कैरीकॉम' देशों को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आइएसए) और आपदा रोधी ढांचे के गठबंधन (सीडीआरआई)



अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना सत्र के इतर भारत-कैरेबियाई देशों के संगठन 'कैरीकॉम' के नेताओं की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ।

में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और इन देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडल को भारत आने का न्योता दिया। सहयोग के संभावित क्षेत्रों का

पता लगाने के लिए संयुक्त कार्यदल बनाने का भी फैसला लिया गया। बता दें कि 'कैरीकॉम' में 15 सदस्य और पांच सहायक सदस्य हैं। क्षेत्र के

लिए संयुक्त रूप से नीतियों की रूपरेखा बनाने और आर्थिक वृद्धि व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये 1973 में साथ आए थे।

आतंकवाद समेत विभिन्न मुद्दों पर पीएम मोदी की कई देशों के नेताओं से वार्ता

न्यूयॉर्क, प्रे़ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां 74वीं संयुक्त राष्ट्र आमसभा के इतर आर्मेनिया और न्यूजीलैंड के अपने समकक्षों समेत विभिन्न देशों के नेताओं के साथ बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इन बैठकों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, रक्षा, साइबर सुरक्षा से लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता के लिए समर्थन के मुद्दों पर बातचीत हुई।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान के साथ बुधवार को बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने आर्मेनिया में सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में अवसर तलाशने की भारतीय कंपनियों की इच्छा को भी जाहिर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और यूरेशिया आर्थिक संघ (ईएयू) के बीच व्यापार मजबूत करने के लिए आर्मेनिया का सहयोग मांगा। आर्मेनिया इस संघ का सदस्य है। भारत

▶ **भारत-न्यूजीलैंड ने पुलवामा और क्राइस्टचर्च हमलों की निंदा की, आतंक से मिलकर लड़ेंगे दोनों देश**

▶ **आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में निवेश और व्यापार बढ़ाने पर जोर**

और ईएयू शीघ्र ही इस पर वार्ता करने जा रहे हैं।

बैठक के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और लगातार बढ़ रही घनिष्ठता पर संतुष्टि जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने टवीट किया, 'प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान से विस्तार से बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच वर्षों पुराने संबंधों को और गहरा करने पर फलदायक चर्चा हुई।' संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने पर भारत को सदस्यता देने के आर्मेनिया के समर्थन पर मोदी ने पाशिनयान का शुक्रिया अदा किया।

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बताया

कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने मोदी को आर्मेनिया आने का न्योता दिया जिसे मोदी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्दन के साथ मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने के उपायों पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने टवीट कर बैठक के बारे में बताया।

दोनों देशों ने पुलवामा और क्राइस्टचर्च में हुए आतंकी हमलों की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे को समर्थन देने का संकल्प लिया। अर्दन ने कहा कि न्यूजीलैंड में रहने वाले प्रवासी की और गहरा करने पर फलदायक चर्चा हुई।' संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने पर भारत को सदस्यता देने के आर्मेनिया के समर्थन पर मोदी ने पाशिनयान का शुक्रिया अदा किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने एस्तोनिया की राष्ट्रपति क्रूटी कलजुलेद के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। इसके पहले दिन में मोदी ने बेल्जियम के अपने समकक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ बैठक की।

मजबूत भारत-अमेरिकी रिश्ते के लिए मिलिंद ने की मोदी की सराहना

मुंबई, एएनआइ : कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने अपने दिवंगत पिता मुरली देवड़ा की भारत-अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों की प्रतिबद्धता को याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की।

एक शॉर्ट वीडियो क्लिप अटैंच करते हुए देवड़ा ने गुरुवार को टवीट किया है, 'कल (बुधवार) एक कार्यक्रम में मुझसे नरेंद्र मोदी जी का मेरे पिता के कूटनीतिक प्रयास की याद दिलाने और उसके बाद विवाद पैदा होने के बारे में पूछा गया था। मेरा जवाब था कि जो नेता पार्टी हितों से राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखने में विफल हैं वे भारत को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करें।'

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रतिपक्षी पार्टी से संबंधित नेताओं के योगदान को नहीं स्वीकार करने की परंपरा है। वीडियो में उन्होंने कहा है, 'इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कैसे काम करता हूँ और किस तरह की राजनीति में विश्वास करता हूँ।' उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी को दूसरे के सही काम की सराहना करनी चाहिए।

देवड़ा ने इससे पहले हाउडी मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के भाषण की सराहना की थी। जवाब में मोदी ने उनके पिता मिलिंद देवड़ा को अपना मित्र बताते हुए जवाब दिया था।

सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने मिलाए हाथ

आशुतोष झा, न्यूयार्क

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को आगे बढ़ाने और उसके स्थाई व अस्थायी सदस्यों के विस्तार को लेकर भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान एकजुट हो गए हैं। न्यूयार्क में इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए 2005 में सभी राष्ट्रपक्ष्यों और सरकारों के विश्व सम्मेलन में की गई परिकल्पना को आगे बढ़ाने की जरूरत बताई। यही नहीं, सुरक्षा परिषद में चारों देशों ने स्थाई सदस्यता के लिए एक-दूसरे को सहयोग करने का ऐलान भी किया।

चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा हाल ही में शुरू किए गए इंटर गवर्नमेंटल नेगोसिएशंस (आइजीएन) की भी समीक्षा की गई। जिसमें पाया गया कि आइजीएन शुरू होने के बाद भी कोई ठोस परिणाम नहीं मिल पाया है। आइजीएन में पारदर्शिता के अभाव होने के साथ-साथ काम करने का तरीका भी संदिग्ध है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र आम सभा की 1979 की बैठक के एजेंडे में सुरक्षा परिषद का विस्तार पर उसकी सदस्यता

▶ **इंटर गवर्नमेंटल नेगोसिएशंस की भी समीक्षा की गई**

▶ **चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में कई अस्थायी सदस्यों को भी हुई बात**

बढ़ाने का मुद्दा शामिल था, लेकिन 40 सालों में इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका।

विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान में साफ कर दिया है कि अब सिर्फ सामान्य वक्तव्य देकर बहस पूरी करने की परंपरा को निंदा करने का समय आ गया है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य सुरक्षा परिषद में समग्र सुधार और आइजीएन को लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया से जोड़ने के पक्षधर हैं। अगले साल 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ को देखते हुए चारों विदेश मंत्रियों ने उम्मीद जताई है कि मौजूदा आमसभा का सत्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का गस्ता साफ करेगा, जिनमें स्थाई सदस्यों के साथ-साथ अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाना शामिल है ताकि इसमें दुनिया के सभी भागों और वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके।

मिग-21 हादसा : दिल्ली से पहुंचा दल, कोर्ट ऑफ इक्वायरी शुरु

नईदुनिया, भिंड : मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दुर्घटना का शिकार हुए मिग-21 (टाइप 69) प्रशिक्षण विमान को कोर्ट ऑफ इक्वायरी गुरुवार से शुरू हो गई। दिल्ली से ग्रुप कैप्टन एमएस यादव सहित तीन सदस्यीय टीम गुरुवार सुबह करीब 10 बजे हेलिकॉप्टर से मिग-21 के मलबे के पास पहुंची और उसकी जांच की। विमान के ब्रेक पाट सहित मलबे से दो अन्य कलपुर्जे टीम ने जांच के लिए सुरक्षित रख लिए हैं।

टीम ने दुर्घटनास्थल चौधरी का पुरा गांव में काफी बारीकी से मलबे की जांच की। टीम ने खेत में मिग-21 के दुर्घटनाग्रस्त स्थान से लेकर उन खेतों में भी तलाशी ली, जहां विमान का मलबा गिरा था। टीम ने एयरफोर्स स्टेशन को अधिकारियों से भी बात की है। शुक्रवार को विमान हादसे की जांच करने के लिए दिल्ली से एक और टीम आचकी। यह टीम महाराजपुरा वायुसेना स्टेशन के अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त जांच करेगी। विमान के मलबे को खेत में ही संरक्षित किया गया है।

मोदी के बाद धौनी देश में सर्वाधिक लोकप्रिय महिलाओं में बॉक्सर मैरी कॉम ने मारी बाजी

नई दिल्ली, आइएनएस : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने देश में लोकप्रियता के मामले में मौजूदा कप्तान विराट कोहली तथा क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, धौनी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक पायदान पीछे रह गए हैं। महिला वर्ग में बॉक्सर मैरी कॉम ने लोकप्रियता के मामले में देश में सबसे को पीछे छोड़ दिया है।

यूगोव (वाईओयूजीओवी) की तरफ से कराए गए सर्वे में ये बातें सामने आईं। विश्व के सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों की सूची बनाने के लिए इस सर्वे में 41 देशों के 42 हजार लोगों को शामिल किया गया। इस सर्वे को महिला व पुरुष वर्गों में बांटा गया था। पुरुष वर्ग में प्रधानमंत्री मोदी देश की सबसे लोकप्रिय हस्ती रहे, जबकि महिला वर्ग में बॉक्सर मैरी कॉम शीर्ष पर रहीं।



महेंद्र सिंह धौनी ।

इस सर्वे में पीएम मोदी की रेटिंग 15.66 व धौनी की 8.58 फीसद थी। रतन टाटा की रेटिंग 8.02, बराक ओबामा की 7.36, बिल गेट्स की 6.96, सचिन तेंदुलकर की 5.81 व टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की 4.46 फीसद रही। सूची में कोहली सातवें, जबकि तेंदुलकर उनसे एक पायदान ऊपर



मैरी कॉम ।

रहे। महिलाओं में मैरी कॉम की रेटिंग 10.36 फीसद रही। वह इस सूची की टॉप 25 महिलाओं में जगह बनाने वाली इकलौती भारतीय हैं। पूर्व आइपीएस अधिकारी किरण बेदी की रेटिंग 9.42, गांधिका लता मंगेशकर की 9.23 व अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की 6.35 फीसद रही।

आइपीएस अफसर पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़िता से दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, रांची : बहुचर्चित आइपीएस अफसर पीएस नटराजन यौन शोषण केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इसमें निचली अदालत से नटराजन के बरी होने के बाद पीड़ित महिला ने हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की थी। उसी केस को वापस लेने की धमकी देने व बात नहीं मानने पर दुष्कर्म करने का मामला पीड़िता ने दर्ज कराया है। आरोपित पीड़िता ने पति का दोस्त है। पीड़िता ने दर्ज प्राथमिकी में युवक पर पिस्टल के बल पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवक ने धमकी दी कि केस वापस नहीं लगे तो यह बार बार होगा। गुरुवार की सुबह उसने प्राथमिकी दर्ज कराई।

आइपीएस पीएस नटराजन का रस्टिंग ऑपरेशन करने के बाद पीड़िता ने 2 अगस्त 2005 को यौन शोषण का केस दर्ज कराया था। मुकदमा 12 साल तक चला था। इसके बाद बेदी की रेटिंग 9.42, गांधिका लता मंगेशकर की 9.23 व अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की 6.35 फीसद रही।

हनी ट्रैप : जुवेनाइल जरिस्टस बोर्ड में आठ साल तक सदस्य रही आरोपित श्वेता

नईदुनिया, इंदौर

मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप मामले में आरोपित श्वेता विजय जैन को किशोर न्याय बोर्ड (जुवेनाइल जरिस्टस बोर्ड) में सदस्य नियुक्त किया गया था। शिवराज सिंह सरकार ने वह आठ वर्ष तक बोर्ड में सदस्य के तौर पर पदस्थ रही। सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए राज्य सरकार की ओर से श्वेता की बोर्ड में नियुक्ति की गई थी। गुरुवार को कांग्रेस ने श्वेता की नियुक्ति के दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए आरोप लगाए। कांग्रेस के प्रदेश सचिव व्हेनस सिंह यादव ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हनी ट्रैप की मास्टरमाइंड को संरक्षण दे रहे थे। यादव ने दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए कहा कि 2006 से 2014 तक लगातार श्वेता जैन सागर के किशो न्याय बोर्ड में सदस्य रही। खास बात ये है कि बोर्ड में सदस्य की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश एक चयन समिति करती है। इसमें जिला व सत्र न्यायाधीश, जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक होते हैं।

▶ **कांग्रेस का आरोप- शिवराज सरकार ने आरोपितों पर की नियम विरुद्ध मेहरबानी**

कमेटी के नामों पर राज्य सरकार मुहर लगाकर नियुक्ति आदेश जारी करती है। बोर्ड को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियां होती हैं। किशोरों से जुड़े मामलों व पुनर्वास आदि के प्रकरणों का निराकरण बोर्ड करता है। किशोर बोर्ड की वर्षों तक सदस्य रही महिला आद हनी ट्रैप में पकड़ी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि उस पर राज्य सरकार ने जमकर मेहरबानी क्यों की ? उन्होंने कहा कि नियमानुसार सिर्फ तीन साल के लिए बोर्ड का गठन होता है। साथ ही किसी भी सदस्य को सिर्फ दो कार्यकाल तक नियुक्ति दी जा सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर श्वेता को आठ वर्ष तक सदस्य कैसे बनाए रखा गया ? इस नियुक्ति में उस वक्त पदस्थ अधिकारियों के साथ सरकार की भूमिका भी जांच होनी चाहिए। अंदेशा है कि किशोर न्याय बोर्ड में अपने पद का लाभ लेकर श्वेता ने कई युवतियों को गलत रास्ते पर धकेला हो।

मोदी-इमरान के भाषण के पहले सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

नापाक इरादे ▶ कश्मीर घाटी में बड़े हमले की फिराक में आतंकी

घाटी पहुंचकर खुद डोभाल

ने संभाली सुरक्षा तैयारियों

की बागडोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के शुक्रवार के भाषण के पहले आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए पूरे देश और खासकर कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। घाटी में सुरक्षा तैयारियों पर नजर रखने के लिए खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कश्मीर में डेरा डाल दिया है। इसके पहले अजीत डोभाल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने जाने के बाद लगातार 11 दिनों तक कश्मीर घाटी में रहे थे।

सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय बनाने की पाकिस्तान की हर कोशिश अभी तक विफल रही है। पश्चिमी देश तो दूर खाड़ी के देशों तक का उसे साथ नहीं मिला। अब पाकिस्तान के सामने संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के अंतराष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाने का अंतिम अवसर बचा है। सीमा पार से मिल रही खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने जैश-ए-मुहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन सभी आतंकी संगठनों के आकाओं को अंतर्गत राष्ट्र में अभिभाषण से पहले घाटी में बड़े हमले का फरमान सुनाया है। जाहिर है सुरक्षा एजेंसियां इसे रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं।

जम्मू-कश्मीर में बीडीसी चुनाव में राजनीतिक दलों के भाग लेने पर सशंय

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य प्रशासन ने ब्लॉक विकास परिषदों (बीडीसी) के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। मतदाता सूचियां तैयार हो चुकी हैं, लेकिन चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के भाग लेने को लेकर अभी संशय बना है। कारण भाजपा छोड़ सभी प्रमुख पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एहतियातन हिरासत में हैं या फिर नजरबंद।

2018 में हुए थे पंचायत चुनाव : जम्मू कश्मीर में 4200 पंचायतें हैं। वर्ष 2018 में नवंबर-दिसंबर में पंचायत चुनाव हुए थे, लेकिन ब्लॉक और जिला विकास परिषदों और बोर्डों का गठन नहीं हुआ है। राज्य प्रशासन ने इन्हें मार्च में कराने का फैसला किया, लेकिन संसदीय चुनाव के कारण प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

रियासी हलकों में ज्यादा हलचल नहीं : राज्य के मुख्य निवांचन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार के अनुसार यह प्रक्रिया अक्टूबर के समाप्त होने से



भारत-पाकिस्तान की सीमा के पास विनाब नदी पर मुस्तेद सुरक्षा कर्मी।

प्रेट

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घाटी में आतंकीयों के घुसपैठ के लिए आइएसआइ हरसंभव कोशिश कर रहा है। सीमा पर फायरिंग और समुद्री रास्ते के साथ-साथ श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश के रास्ते भी आतंकीयों को भेजने की कोशिश की सूचना है। उन्होंने कहा कि पांच अगस्त के बाद लगभग 60 आतंकीयों के घाटी में घुसने की खबर है, जिनमें कई आत्मघाती दस्ते के सदस्य भी हैं। लेकिन वे किस रास्ते से पहुंचे इस बारे में साफ तौर पर कुछ

नहीं कहा जा सकता है। यही नहीं, घाटी के भीतर पहले से लगभग 273 आतंकी सक्रिय हैं। ऐसे में सुरक्षा में जग भी चुक की गुंजाइश नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यदि संयुक्त राष्ट्र के अभिभाषण के बाद इमरान खान कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाते में विफल रहे, तो अभी तक उम्मीद बांधे अलगाववादियों के हौसले परस्त होने लगेंगे। इसके बाद घाटी में हालात को तेजी से सामान्य बनाने में मदद मिलेगी।

भाजपा छोड़ सभी प्रमुख पार्टियों के नेता हिरासत में हैं या नजरबंद

राज्य प्रशासन ने ब्लॉक विकास परिषदों के गठन की तैयारी शुरू की

पहले यहां हालात सामान्य होने चाहिए : पीडीपी

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े युवा सिख नेता ने कहा कि हमारे सभी नेता बंद हैं और जो बाहर हैं उन्हें राजनीतिक गतिविधि करने की इजाजत नहीं है। उक्त नेता ने कहा कि परिषद का चेंबरमैन बनने के लिए चुनाव लड़ना है यह पार्टी नेतृत्व तय करेगा।

पहले ही पूरी कर ली जाएगी। संबंधित प्रशासन ने चुनाव दलीय आधार पर कराने का फैसला किया है, लेकिन स्थानीय सिपासी हलकों में

ज्यादा हलचल नहीं है। वहीं, अन्य राजनीतिक दलों में चुनाव को लेकर हलचल नहीं है। क्योंकि इनके ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता पांच अगस्त के बाद से या तो एहतियातन हिरासत में हैं या नजरबंद हैं।

मौजूदा हालात में कौन चुनाव में भाग लेगा

नेका : श्रीनगर से करीब 15 किलोमीटर दूर छत्तरगाम में नेशनल कांफ्रेंस के एक ब्लॉक प्रधान ने नाम न छापे जाने की शर्त पर कहा कि मौजूदा हालात में कौन इन चुनावों में हिस्सा लेगा। हमारी पार्टी से इनमें भाग लेने की उम्मीद नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ भाजपा के स्थानीय नेताओं को हুকूमत देने के लिए चुनाव करा रही है।

प्रशासन की नीयत पर सवाल उठाते हैं : कांग्रेस : प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में यह चुनाव मजाक लगते हैं। इस समय चुनाव कराना प्रशासन की नीयत पर कई सवाल उठाता है। राज्य और केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

30

सितंबर को कलकता हाई कोर्ट में सीरियल धमाके की धमकी दी गई है। इस बाबत हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रवींद्रनाथ सामंत ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा है जिसमें तत्काल प्रभाव से आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया है।

डोभाल ने राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कठोर कार्रवाई के लिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गुरुवार को सभी सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर में हालात जल्द पूरी तरह सामान्य बनाने के लिए आतंकी और राष्ट्रविरोधी तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के अभियान तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही आम लोगों के जान-माल-सम्मान की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए भी कहा। डोभाल ने यह निर्देश जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में परिवर्तित करने की कार्ययोजना और अलगाववादियों व आतंकीयों द्वारा जबरन लागू कराए जा रहे बंद को नाकाम बनाने की रणनीति का एक उच्चस्तरीय बैठक में जायजा लेते हुए दिए। बता दें कि पांच अगस्त के बाद डोभाल का यह दूसरा कश्मीर दौरा है।

27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा कश्मीर मुद्दा उछालने की आशंका से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कश्मीर दौरा बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि जैश-ए-मुहम्मद द्वारा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के सहयोग से आतंकी हमले की साजिश का अलर्ट भी जारी हो चुका है। ऐसे में अगर अभी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो यह पाकिस्तान के हक में जाएगा। डोभाल अपने दूसरे दौर पर बुधवार को श्रीनगर पहुंचने के बाद दक्षिण कश्मीर के अवतीपोर गए थे। यहां उन्होंने पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों व जवानों के अलावा सेना के अधिकारियों से भी भेंट की थी।

एलओसी से अंदरूनी क्षेत्रों के हालात का

शांत हो रही वादी, अब कोई नहीं मांग रहा आजादी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद उपजा तनाव धीरे-धीरे शांत हो रहा है। अब वादी में कहीं आजादी, जिहादी और अलगाववादी नारे नहीं गूंज रहे। धीरे-धीरे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और बाजारों में चलकदमी कर रहे हैं। गुरुवार को श्रीनगर समेत घाटी के किसी भी हिस्से में निषेधाज्ञा नहीं थी।

ऐसे में सुबह ही सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। वादी में डाल चौक, पोलो व्यू सहित सभी प्रमुख बाजारों में सुबह तीन-चार घंटे दुकानें खुली और बंद हो गई, जो दोपहर बाद में चार बजे से रात आठ बजे तक फिर खोली गई। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सामान्य रही। स्कूल भी खुले रहे। हालांकि बच्चों की संख्या कम थी।

गली-बाजारों और फुटपाथ पर रही भीड़ : गली-बाजारों और फुटपाथ पर सामान बेचने वालों की भीड़ आज बीते दिनों की अपेक्षा ज्यादा रही। इससे वादी के प्रमुख बाजारों के बंद होने का अहसास नहीं हुआ। सार्वजनिक यात्री वाहन



यहां बसता है असली कश्मीर : श्रीनगर के नौगाम में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के साथ लगते एक खेत में धान की फसल की कटाई के बाद छटाई में जुटे किसान। अलगाववादी और कई राजनीति दल इन्हीं आम कश्मीरियों की दुहाई देकर हालात बिगाड़कर अपनी सिपासी रोटियां सेंकते हैं, जबकि हकीकत यह है कि इन कश्मीरियों को न तो अलगाववादी सिपासत से कोई संरोकार है और न ही जिहादी नारों से कोई लेना-देना। ये कश्मीरियत-ईसानियत-जम्हूरियत के फलसफे पर चलते हैं। कामरान रशीद बट

सड़कों से नदरद रहें। अलबत्ता, निजी और तिपहिया वाहन दिनभर सड़कों पर दौड़ते रहे। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर वाहनों की आवाजाही लगभग सामान्य रही। श्रीनगर को वादी के अन्य सभी प्रमुख शहरों व कस्बों से जोड़ने वाली

महबूबा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट, ‘पहले बिरयानी खाई थी, अब क्या हलीम खाने आए’

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के कश्मीर दौरे पर तंज कसा गया। इसमें लिखा गया कि पहले बिरयानी खाई थी, अब क्या हलीम खाने आए हैं। पांच अगस्त से एहतियातन हिरासत में ली गई महबूबा मुफ्ती का ट्विटर हैंडल उनकी बेटी इल्टजा मुफ्ती संचालित कर रही है।

डोभाल बुधवार को कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे थे। गुरुवार को महबूबा के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, पिछली बार मेन्सू में बिरयानी थी, क्या इस बार हलीम होगा? आगे लिखा, पिछली बार कुछ अंजान कश्मीरियों के साथ ‘बिरयानी फोटो सेशन’ था। इस बार मेन्सू में क्या है, हलीम? गौरतलब है कि पिछले माह डोभाल ने शोपियां दौर के समय बाजार में कुछ स्थानीय लोगों के साथ खाड़े होकर बिरयानी खाई थी। यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं।

लििया जायजा : संबंधित अधिकारियों ने बताया कि डोभाल ने गुरुवार को सेना, पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और विभिन्न खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करीब दो घंटे बैठक की। इसके अलावा उन्होंने एलओसी पर जारी गतिविधियों का भी जायजा लिया। इस बीच, जम्मू-कश्मीर में खून खराबा करने के लिए पंजाब में डौन से हथियार पंजाब में गिराने की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद सेना और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) रेड अलर्ट पर हैं। जम्मू में दुरमन घुसपैठ करने के लिए अंतःराष्ट्रीय सीमा (आडबी) पर सुरंग खोदने की कई एंथों से कोशिश कर रहा है। ऐसे में बीएसएफ सुरंग निरोधी मुहिम छेड़कर जम्मू में

आडबी के चप्पे-चप्पे को खंगाल रही है। अर्धिया में ठेकी लाने के लिए निर्देश : डोभाल ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन की प्रक्रिया के दौरान आतंकी और गश्द विरोधी तत्वों द्वारा खलल पैदा किए जाने की आशंका और जैश के बड़े हमले की साजिश को नाकाम बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। डोभाल ने राज्य प्रशासन के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अलग बैठक की। उन्होंने वादी में मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा की बहाली से जुड़े मुद्दों, 31 अक्टूबर को अखिरत्व में आ रहे दो केंद्र शासित राज्यों के प्रशासन और परिसंपत्तियों के बंटवारे की प्रक्रिया पर जारी काम का जायजा लिया।

संघ-भाजपा नेताओं की हत्या में शामिल चौथा आतंकी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, किरतवाड़ : जम्मू के किरतवाड़ में भाजपा के पूर्व प्रदेश सचिव अनिल परिहार और आरएसएस अधिकारी चंद्रकांत शर्मा समेत चार लोगों की हत्या में शामिल चौथा आतंकी भी पकड़ा गया। इससे पूर्व 23 सितंबर को आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के तीन आतंकी पकड़े गए थे। चौथे आतंकी ने गहन पूछताछ में अपना जुर्म कुबूल कर लिया है। पुलिस ने गुरुवार को उसे कोर्ट में पेशकर पांच दिन की रिमांड पर ले लिया।

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आतंकी की पहचान तारिक हुसैन गिरि निवासी पुषाल के रूप में हुई है। तारिक की कूकल के पीछे दुकान है। यहीं से वह आतंकी गतिविधियां चलाता था। इससे पहले सेना और पुलिस संयुक्त ऑपरेशन में हिब्ज आतंकी आजाद हुसैन, नासिर शेख, और नौशाद को गिरफ्तार कर चुकी है। तारिक भी चारों हत्याओं में आतंकीयों का साथ देने में शामिल था। वह वास्दात के बाद आतंकीयों को घर में शरण देता था। बता दें कि वह चारों वही आतंकी हैं जो 14 सितंबर को पीडीपी नेता नासिर हुसैन के अंगरक्षक से गश्फल छीनने के बाद फगर थे। सूत्रों के अनुसार, सेना और पुलिस की टीम ने आतंकी तारिक को उसके घर से काबू किया। वह साथी तीन आतंकीयों के पकड़े जाने के बाद भागने की बजाय घर में छिप गया था क्योंकि सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को घेरा था।

वाकी बचे आतंकीयों में खलबली : किरतवाड़ में सेना और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के बाद वाकी बचे आतंकीयों में खलबली मची हुई है। आतंकी ओसामा बिन जावेद, हाकन बानी, नावेद शाह और साजिद का कहीं कोई पता ठिकाना नहीं लग रहा है।

उपायुक्त और सुरक्षा एजेंसियों के कार्यालय में ही उपलब्ध है। संबंधित अधिकारियों के मुताबिक, हालात में सुधार के आधार पर मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को अगले कुछ दिनों में बहाल किया जा सकता है। वहीं, लैंडलाइन सेवा पूरी वादी में बहाल है। संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था : प्रशासन ने गुरुवार को भी वादी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करते हुए बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल तैनात रखे। दर शाम गए कुछेक इलाकों में छिट-पुट थरावर की घटनाओं को छोड़ दें तो हालात पूरी तरह सामान्य व शांत रहे।

हताश है अलगाववादी और आतंकी : पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद प्रशासन ने वादी में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंदियां लगाने सहित टेलीफोन और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था। हालात में बेहतरी के साथ प्रशासन ने पाबंदियां हटा ली हैं, लेकिन अपने एजेंडे को नाकाम होता देख हताश अलगाववादी और आतंकी संगठन जबरन बंद करा रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे : गुर्जर

जागरण संवाददाता, राजौरी

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गुरुवार को कहा कि गांधी, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों ने अपने लाभ के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों से धोखा किया। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गुरुवार को कहा कि गांधी, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों ने अपने लाभ के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों से धोखा किया। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यक्रम का। केंद्र से विकास कार्यों के लिए जो भी पैसा आया, उसे अपनी जेब में डाला। अब इन परिवारों को एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।



(लेखक सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

मोक्ष का मार्ग

बंधन और मोक्ष में फर्क सिद्ध इतना-सा है कि जब आसुरी संपदा हमारे पास बढ़ेगी तो हम बंधन की ओर बढ़ जाएंगे, लेकिन जब देवीय संपदा हमारे पास बढ़ेगी, तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ जाएंगे। बंधन का मकड़जाला हमें जकड़ रहा है, लेकिन इससे छुटकारा पाना हमें व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि वह व्यक्ति के लिए एक मोक्ष जरूरी है। व्यक्ति जो कुछ भी करता है, उसमें मोक्ष, क्रोध, मोह नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका निर्णययोग्य समाज के हित में होना चाहिए। महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन इस के लिए श्रीकृष्ण ने पांडवों के मन में द्वेष नहीं, बल्कि अखंड भारत के कल्याण की भावना जगाई और एक संस्कारी राजा का आदर्श रखते हुए ईश्वर के लिए कर्म करने की भावना जगाकर युद्ध करने को कहा। इस कर्म के मोक्ष प्राप्ति के लिए कानूनी वारे कर्मों में जीवन जीने की कला कहा जाए तो अधिराज्योक्ति नहीं होगी। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, सुनने और मनन की क्षमता को बढ़ाना चाहिए और निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए।

nomananandapadhyay@gmail.com

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
 दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
 डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
 ई-मेल : mailbox@jagran.com

.....

आजकल



राहुल लाल
आर्थिक मामलों के जानकार

मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल में वर्ष 2014 से 2019 के दौरान कुल औसत निर्यात वृद्धि दर चार प्रतिशत रहा। वर्ष 2014-15 से पहले की बात करें तो निर्यात बेहतर था, वर्ष 2013-14 में निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर 17 प्रतिशत थी, जिसमें 2014-15 और 2015-16 में व्यापक कमी आ गई। इसके अलावा भारत की निर्यात प्रतियस्पर्धामकता में 50 फीसद से कम बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में निर्यात बढ़ाने की जरूरत पर बल देकर भारतीय अर्थव्यवस्था की नीतिगत प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट संकेत दिए थे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इसी माह बोर्ड ऑफ ट्रेड की एक बैठक में कहा था कि अगर देश को सरकार द्वारा तय विकास लक्ष्य हासिल करने हैं, तो उसे निर्यात में 19 से 20 फीसद की दर से वृद्धि हासिल करनी होगी। आर्थिक वृद्धि एवं निर्यात वृद्धि की कमी के कई कारण महत्वपूर्ण रहे। सरकार की दलील है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती जा रही है और चीन अमेरिका ट्रेड वॉर के चलते अनिश्चितता का माहौल है। हालांकि यह दलील काफी हद तक सतही है। मसलन, ट्रेड वॉर में उलझे चीन की जुन तिमाही में वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रही। यह कहना मुश्किल है कि चीन की तुलना में भारत पर व्यापार युद्ध का ज्यादा असर पड़ रहा है। आइएमएफ के सुनाबिक वर्ष 2018 में ही वियतनाम ने 10 वर्षों की उच्च वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत हासिल की। बांग्लादेश भी गत वित्त वर्ष में आठ फीसद की दर से आगे बढ़ने के बाद इस समय 7.5 फीसद वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। स्पष्ट है कि वैश्विक वित्तीय परिदृश्य अनुकूल है, बस एक विशिष्ट रणनीति की आवश्यकता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्पादों की प्रमुखता बनाम भारतीय व्यापार में उत्पादों की प्रमुखता : अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्पादों के कारोबार की ही प्रमुखता होती है और सेवा कारोबार उत्पाद व्यापार के कुल मूल्य के एक तिहई से भी कम है। उत्पाद श्रेणी में वैश्विक कारोबार का करीब आधा हिस्सा मध्यवर्ती उत्पादों का होता है और उपभोक्ता उत्पाद, कच्चा माल, पूंजी उत्पाद श्रेणियों में मात्रा बढ़ने के बावजूद यह अनुपात कमीबेश ऐसा ही रहेगा। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक वाणिज्य निर्यात हिस्सेदारी का दोगुना है। वाणिज्य निर्यात की तुलना में सेवा निर्यात का वृत्तवर्ष 2000-01 के 35.8 फीसद से बढ़कर 2016-17 में 58.2 फीसद हो चुका है। भारत का वाणिज्य उत्पाद श्रेणी में सबसे बड़ा हिस्सा उपभोक्ता उत्पादों (44 फीसद) का है,



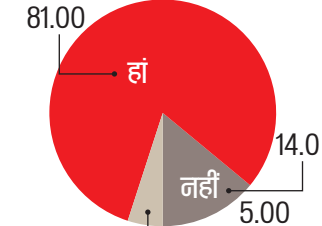
श्रीनिवासन की बेटी तमिलनाडु क्रिकेट संघ की नई प्रमुख हैं। अनुराग ठाकुर के भाई हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की कमान संभाल सकते हैं। वहीं अशोक महलोत के बेटे राजस्थान में। निरंजन शाह के भतीजे सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के मुखिया होंगे। विनोद राय के जरिये भारतीय क्रिकेट को संवांलित कर रहे कोर्ट से यही रोकने की अपेक्षा थी।

मनीष छिन्नर@maneeeshchhibber

मैं आयुधान भारत के बारे में जितना पढ़ता हूं, उतना ही अभिभूत होता हूं। इस पर सही से अमल हो रहा है। भारत में अधिकांश परिवार बीमारी के इलाज में जिंदगी भर की कमाई गंवा देते हैं। इसे अब रोक जा सकेगा। विक्रम साठये@vikramsathaye

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या जसप्रीत भुमराह के चोटिल होने से भारतीय टीम की गेंदबाजी क्षमता प्रभावित होगी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मेसेज बॉक्स में जाकर PHN लिखें, स्पेस देकर **Y ,N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें **Y** - हाँ, **N** - नहीं, **C** - कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

यूएनजीए में गला फाड़ेंगे इमरान, किंतु न देगी आज भी दुनिया उनपर ध्यान। दुनिया उनपर ध्यान जान उनकी नौटंकी, खुद कहते जो पाक पालता है आतंकी। हाफिज के हित मांग रहा जो टीए-डीए, कैसे उसकी बात सुनेगा यूएनजीए।

— ओमप्रकाश तिवारी

प्रतिशत है पर्यटन क्षेत्र का योगदान भारत के संपूर्ण सकल घरेलू उत्पादन में। इस दृष्टि से विश्व में भारत का सातवां स्थान है।

निर्यात की रफ्तार तेज करने की कोशिश

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पांच फीसद ही रह गई है, जबकि पिछली तिमाही में यह 5.8 प्रतिशत और पिछले वर्ष की पहली तिमाही में आठ प्रतिशत रही। भारतीय अर्थव्यवस्था घरेलू मांग में कमी की समस्या से जूझ रही है, ऐसे में भारतीय उद्योगपति विदेशों में बाजार तलाश रहे हैं। वैश्विक तौर पर कर्ज की ऊंची लागत, स्किल एवं इन्ोवेशन की कमी और ज्यादा टैक्स की वजह से भारतीय निर्यात वैश्विक प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पा रहा है। भारतीय निर्यात लंबे समय से निगेटिव ग्रोथ में है यानी इसमें लगातार गिरावट जारी है। निर्यात जीडीपी के चार प्रमुख घटकों में से एक है। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी सुस्त हो रही है जिसमें तेजी लाने में सरकार जुटी है

जिसके बाद मध्यवर्ती उत्पाद निर्यात (33 फीसद) का स्थान आता है। ऐसे में निर्यात वृद्धि में 20 प्रतिशत की वृद्धि हेतु उत्पादों के निर्यात को और प्रोत्साहन देना होगा।

जीवीसी एकीकरण पर जोर : पिछले दो दशकों में वैश्विक कारोबार मुख्य रूप से जीवीसी अर्थात ग्लोबल वैल्यू चेन द्वारा ही पोषित होता रहा है। जीवीसी की अब निर्यात वृद्धि का मुख्य इंजन भी कहा जाता है। जीवीसी के लिए उत्पादों को कई बार सीमा के आर पार जाना पड़ता है। जीवीसी मॉडल के तहत किसी उत्पाद के जीवनचक्र को कई कार्यों में विभाजित किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले देश ‘जस्ट इन टाइम’ परिस्थितियों में क्रमबद्ध रूप से प्रत्येक कार्य को पूरा करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्निहित विखंडन ने अंतरराष्ट्रीय गत वित्त वर्ष में आठ फीसद की दर से आगे बढ़ने के बाद इस समय 7.5 फीसद वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। स्पष्ट है कि वैश्विक वित्तीय परिदृश्य अनुकूल है, बस एक विशिष्ट रणनीति की आवश्यकता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्पादों की प्रमुखता बनाम भारतीय व्यापार में उत्पादों की प्रमुखता : अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्पादों के कारोबार की ही प्रमुखता होती है और सेवा कारोबार उत्पाद व्यापार के कुल मूल्य के एक तिहई से भी कम है। उत्पाद श्रेणी में वैश्विक कारोबार का करीब आधा हिस्सा मध्यवर्ती उत्पादों का होता है और उपभोक्ता उत्पाद, कच्चा माल, पूंजी उत्पाद श्रेणियों में मात्रा बढ़ने के बावजूद यह अनुपात कमीबेश ऐसा ही रहेगा। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक वाणिज्य निर्यात हिस्सेदारी का दोगुना है। वाणिज्य निर्यात की तुलना में सेवा निर्यात का वृत्तवर्ष 2000-01 के 35.8 फीसद से बढ़कर 2016-17 में 58.2 फीसद हो चुका है। भारत का वाणिज्य उत्पाद श्रेणी में सबसे बड़ा हिस्सा उपभोक्ता उत्पादों (44 फीसद) का है,



सतीश चंद्र श्रीवास्तव
समाचार संपादक, पानीपत

विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक उठापटक तेजी पर है। ‘अबकी बार 75 पार’ के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतर रही भाजपा का आत्मविश्वास बुलंदियों पर है। पार्टी नेतृत्व के समक्ष दावेदारों की लाइन लगी हुई है। विपक्ष के कई महत्वपूर्ण नेता, पूर्व सांसद और विधायक भी भाजपा का हिस्सा बन चुके हैं। संगठन के ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सदस्य पदाधिकारी के रूप में विशेष छवि बनाने वाले मनोहर लाल अब सुलझे और दमदार राजनेता की तरह फैंसले ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह साफ तौर पर उद्धं भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर चुके हैं। साथ ही पार्टी नेतृत्व ने यह भी साफ कर दिया है कि परिवारवाद नहीं चलेगा। किसी सांसद के बेटा-बेटी को विधानसभा टिकट नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी (जननायक जनता पार्टी) सहित अन्य



राजनीतिक दल उम्मीदवारों की तलाश में हैं। उम्मीद की जा रही है कि सप्ताहांत तक भाजपा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद भाजपा के बागियों से सुसज्जित विपक्ष दल चुनाव मैदान में होंगे। कांग्रेस फिलहाल जितने नेता, उतने घड़ों में फंसी है। विधानसभा में पिछले महीने तक मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में रहा इनेलो (इंडियन नेशनल लोकदल) घर में फूट से दो चार हो रहा है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में इसमें संदेह है कि पूर्व भाजपा सांसद राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और प्रदेश में बार-बार साझीदार बदलने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी की भूमिका वोट काटने वालों से ऊपर उठ सकेगी।

विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अभी प्रदेश की राजनीति में चर्चा में है। उसके बाद कांग्रेस के बिखरे कुत्ते में भूपेंद्र सिंह हट्टा का भविष्य और विपक्ष की ताकत आकलन का विषय है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव की घोषणा। पहले ही सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा जेजेपी (जननायक जनता पार्टी) सहित अन्य

विश्व पर्यटन दिवस



प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह
कुलपति, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच का यह अनुमान है कि आगामी वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास की दर सामान्य रहेगी, परंतु भारत की अर्थव्यवस्था सशक्त, समर्थ एवं विकासोन्मुख होगी। भारत सरकार के संदर्भों के अनुसार वर्ष 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था पांच खरब डॉलर एवं 2030 तक 10 खरब डॉलर की होगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था की सामान्य वृद्धि दर होते हुए भी, अर्थतंत्र का पर्यटन क्षेत्र रोजगार सृजन एवं आय वृद्धि की दृष्टि से तीव्र गति से बढ़ेगा। जो देश इससे जुड़े कारोबार की संभावनाओं को व्यावहारिक अयोग्य देगा, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन उद्योग महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। भारत के पास वैश्विक पर्यटन एवं घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अद्विभुत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधन उपलब्ध है, जो पर्यटन उद्योग के लिए प्रकृति का उपहार है। आज 27 सितंबर को जब संपूर्ण विश्व में पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है सौभाग्य का

विषय है कि ‘वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन कार्डसिल’ की वार्षिक बैठक भारत में हो रही है। भारत के लिए यह अवसर पर्यटन की संभावनाओं, समस्याओं और व्यावहारिक आयामों पर चिंतन व क्रिया-न्वयन की दृष्टि से सामयामयिक महत्व का है।

‘वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन कार्डसिल’ द्वारा वर्ष 2019 का पर्यटन दिवस का थीम है- पर्यटन एवं रोजगार : सभी के लिए एक बेहतर भविष्य। इसे ध्यान में रखते हुए भारत में पर्यटन की संभावनाओं एवं आगामी चुनौतियों पर मंथन समीचीन है, जो अभी तक उपेक्षित रही। वर्ष 2018 में विदेशी पर्यटकों की संख्या के लिए भारत का विश्व में 26वां एवं पर्यटन द्वारा प्राप्त आमदनी की दृष्टि से भारत का 13वां स्थान है। यदि भारत के संपूर्ण सकल घरेलू उत्पादन में पर्यटन क्षेत्र के योगदान को देखा जाय, तो वह 9.6 प्रतिशत है और इस दृष्टि से विश्व में भारत का सातवां स्थान है।

तेजी से उभरते हुए पर्यटन क्षेत्र के लिए



कर सुधारों से परिदृश्य बेहतर होने की उम्मीद

वर्तमान में भारत के लिए निर्यात वृद्धि अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस माह कई प्रमुख घोषणाएं की हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष जनवरी से एक नई स्क्रीम- रैमिशन ऑफ़ ड्यूटीज और टैक्सस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडन्ट (आरओडीटीईपी) शुरू करने का फैसला लिया है। यह पहले से जारी निर्यात योजना ‘एमईआइएस’ की जगह लेगी। वर्ष 2015 में विदेश व्यापार नीति के तहत लाई गई एमईआइएस योजना 5,000 से अधिक वस्तुओं के वाणिज्यिक निर्यात को प्रोत्साहन दे रही है। दूसरा महत्वपूर्ण घोषणा बकाया इन्पुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है। सरकार ने निर्यातकों को त्वरित एवं स्वचालित रिफंड दिलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉडल अपनाने की घोषणा की। साथ ही सरकार ने 36 हजार करोड़ से 68 हजार करोड़ रुपये तक अतिरिक्त राशि बैंकों को मुहैया कराए जाने की घोषणा की है, जिसका इस्तेमाल निर्यात क्षेत्र को कर्ज देने में किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने दुर्बई शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज पर देश में चार मेगा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला लिया है।

महत्वपूर्ण हैं। आरवीसी के लिए उतने सख्त मानदंडों की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि जीवीसी में देखने को मिलता है। कारण यह है कि संबंधित सामान स्थानीय बाजार की मांग की बारीकियों और खपत के पैटर्न को पूरा करता है, जो समूचे क्षेत्र में एक समान हो। आरवीसी विकास स्तंभ हो सकते हैं।

जहां तक भारत का सवाल है, तो यह

खरी-खरी

किसिम-किसिम की कसम

मुकेश जोशी

मलंग चचा एक गाना गा गए थे- कसमें वादे प्यार, वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। इस गाने में वर्णित प्यार, वफा टाइप की चीजों से तो अपना पाला कम ही पड़ा, मगर ‘कसम’ खाके कह रिया हूं, ‘कसमों’ से भोत पड़ा। प्यार युवा पढ़िंह का काम है और अपन युवा कभी रहे ही नहीं। शुरू में अपन बच्चे थे, फिर किशो हूए और फिर घर वालों ने इसी जल्दी ब्याह करवा दिया कि युवा होने से पहले ही अंधेड़ हो गए।

कसमों का इतिहास किसी को पता नहीं कि पहली कसम किसने, कब, कहा और क्यों खाई थी ! विश्वास न हो तो गूगल कर के देख लो, कसम से... उस पर कुछ नहीं मिलेगा। मगर आज हलत ये है कि दुनिया में लोग रोज जितना भोजन नहीं खाते, उससे ज्यादा कसमें खा जाते हैं। दरअसल कसमें झूठ को सच साबित करने का टॉनिक होती हैं। झूठ को पुष्ट करती हैं। कसम पर मनुष्य भरोसा इसलिए भी कर लेता है कि झुठी कसम से कोई मर न जाए। हालांकि यह भी सच है कि कसमों के इस झूठे दौर में आज तक चींटी भी नहीं मरी।

कसम के मामले में सबसे सॉफ्ट टारगेट बेचारे ‘भगवान’ होते हैं, क्योंकि भगवान तो मरने से रहे। और न ही वे आकर गवाही देंगे, इसलिए हर जगह-भगवान की कसम। कुछ लोगों का मानना है कि मां भगवान का ही स्वस्व होती है, इसलिए भगवान के बाद मां को ही कसम की कसौटी पर सबसे ज्यादा कसते हैं।

लोग गऊ को मां मानते हैं, इसलिए मां के बाद गऊ माता को कसम खाने के लिए सबसे उम्दा जीव मान लेते हैं। क्या ही विडंबना है कि एक तरफ लोग ‘गाय की कसम खाने’ को नैतिकता का पैमाना मानते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नरायम ‘गाय को ही खा जाने’ को भी अनैतिक नहीं मानते। कसम के मामले में फिर आते हैं मसखरे क्रिस्म के लोग, जो हथ में पकड़ी सुलागती हुई ‘तीस नंबर बीड़ी’ की ओर देखकर कहते हैं, ‘अगिन हथ में है, झूठ नहीं बोलूंगा।’ मगर वे उसी क्षण सबसे बड़ा झूठ बोल रहे होते हैं।

कुछ सच्चे चाय के प्याले को ‘गौरस हाथ में है, बताए हुए उसकी कसमें भी खा जाते हैं।

कसम, दरअसल भरोसे और तुरत-तुरत न्याय की अपनी ही तरह की अमूर्ती प्रणाली है। भारत के समाज ने इसे हजारों सालों में विकसित किया है। कसम से... सब बोल रिया हूं। भरोसा भी हो तो गूगल कर लो !

राजनीतिक उठापटक में आई तेजी



रहे हैं कि विपक्षहीन सरकार की स्थिति बन रही है। दावा किया गया है कि 90 में 75 सीटों पर जीत के लक्ष्य से कहीं अधिक 80 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज कर सकती है।

साफ हो चला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अहम भूमिका निभाने वाले मनोहर लाल को भाजपा नेतृत्व ने गुणों के आधार पर ही प्रदेश का नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया था। उन्हें करनाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा गया था। तब कुछ स्थानीय नेताओं

ने भी विरोध किया था, परंतु संगठन में पकड़, ईमानदार और पारदर्शी राजनीतिक दृष्टि के कारण मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल अब बागीक्यों और खपत के पैटर्न को पूरा करता है, जो समूचे क्षेत्र में एक समान हो। आरवीसी विकास स्तंभ हो सकते हैं।

जहां तक भारत का सवाल है, तो यह

महत्वपूर्ण हैं। आरवीसी के लिए उतने सख्त मानदंडों की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि जीवीसी में देखने को मिलता है। कारण यह है कि संबंधित सामान स्थानीय बाजार की मांग की बारीकियों और खपत के पैटर्न को पूरा करता है, जो समूचे क्षेत्र में एक समान हो। आरवीसी विकास स्तंभ हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण हैं। आरवीसी के लिए उतने सख्त मानदंडों की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि जीवीसी में देखने को मिलता है। कारण यह है कि संबंधित सामान स्थानीय बाजार की मांग की बारीकियों और खपत के पैटर्न को पूरा करता है, जो समूचे क्षेत्र में एक समान हो। आरवीसी विकास स्तंभ हो सकते हैं।



पर्यटन सेवा अवस्थापना सुविधा, पर्यावरणीय वहनीयता तथा यातायात की प्राथमिकता इसके कमजोर पक्ष हैं और इस दृष्टि से विश्व में इनका स्थान क्रमशः 98, 109, 128 एवं 94वें क्रमांक पर है। इन कमजोरियों को दूर करते हुए भारत में वर्तमान में पर्यटन को अर्थतंत्र का प्रमुख क्षेत्र मानते हुए ग्रामीण पर्यटन पर विशेष प्राथमिकता उपेक्षित है। टिकाऊ ग्रामीण पर्यटन की व्यवस्था हेतु यहां उल्लिखित सात बिंदुओं पर नियोजन एवं नीति-निर्धारकों का ध्यान वांछित है। प्रथम है- स्थानीय संस्कृति का संरक्षण, जबकि दूसरा है- वन एवं वन्य जीव-जंतु की गुणवत्ता को बनाए रखना। तीसरा है- पर्यटन के विकास के साथ-साथ स्थानीय समुदाय की प्रभावी सहभागिता तथा सामुदायिक विकास

सुनिश्चित करना। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि ग्रामीण पर्यटन का विकास करने समय बात का ध्यान रखा जाए कि बाहर से आने वाले पर्यटक, स्थानीय संस्कृति, धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं को ठेस नहीं पहुंचाएं। टिकाऊ पर्यटन को गरीबी उन्मुक्ति की रणनीति के रूप में देखा जाना पांचवां बिंदु है। पर्यटकों एवं पर्यटन स्थलों की गरिमा बनाए रखने की दृष्टि से कानूनी प्रावधानों को मजबूती देना छठा बिंदु है। सातवां बिंदु है कि राज्य सरकारें पर्यटन की संभावनाओं वाले क्षेत्रों को अभिलक्षित करें और पर्यटकों के अनुकूल आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान करें। पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में भरपूर योगदान दे सकता है।

तकनीक ► चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने बनाया खास कंटेनर

जहरीले रसायन से पर्यावरण को बचाएगा बल्ब-ट्यूबलाइट ईटर

इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाने वाले ट्यूबलाइट और बल्ब के बेहतर निस्तारण में निभाएगा उपयोगी भूमिका

वीणा तिवारी, चंडीगढ़

चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गनाइजेशन, सीएसआइओ) ने ऐसा कंटेनर विकसित किया है, जो अनुपयोगी ट्यूबलाइट और बल्ब के बेहतर निस्तारण में उपयोगी साबित होगा।

इस्तेमाल हो चुके या अनुपयोगी बल्ब और ट्यूबलाइट

रोजाना बड़ी संख्या में कूड़ाघरों तक पहुंचते हैं। कांच और धातु को तो अन्य उपयोग के लिए अलग कर लिया जाता है, लेकिन घातक रसायन आसानी से वातावरण में पहुंच जाते हैं। दरअसल, इनमें मरकुरी और फास्फोरस जैसे अनेक घातक रसायन मौजूद होते हैं, जो



चंडीगढ़ में सीएसआइओ द्वारा विकसित किया गया खास कंटेनर।

सी. सीएसआइओ

निस्तारण की समुचित प्रक्रिया के अभाव में जमीन, पानी और वातावरण में घुलमिल जाते हैं। एक कारण वैज्ञानिक उपकरण का अभाव बना हुआ था, जिसे अब सीएसआइओ ने विकसित किया है।

सीएसआइओ के वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक खास कंटेनर 'बल्ब एंड ट्यूबलाइट ईटर' तैयार किया है। इस कंटेनर में खराब बल्ब या ट्यूबलाइट को तोड़ते ही इनमें मौजूद रसायनों का सुरक्षित समाधान हो जाएगा। इतना ही नहीं इसकी मदद से रसायन में मौजूद अलग-अलग

तत्वों को पुनः प्रयोग में लाने के लिए एकत्रित भी किया जा सकेगा।

कंटेनर को बनाने वाली टीम में शामिल वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आकाशदीप और डॉ. प्रवीण का कहना है कि बल्ब और ट्यूबलाइट में मरकुरी, फास्फोरस, बैरियम, लैंथनम, इट्रियम और मैग्नीज फास्फेट जैसे रसायन मौजूद होते हैं, जो पर्यावरण के अलावा शरीर के लिए भी घातक साबित होते हैं। मरकुरी के संपर्क में आने पर शरीर की कोशिकाएं मर जाती हैं। पर्यावरण में घुलकर इसका श्वास के साथ शरीर में जाना

और भी खतरनाक होता है।

संस्था की वैज्ञानिक डॉ. सुनीता मिश्रा कहती हैं, ट्यूबलाइट में पारा वाष्प, आर्गन, कसीनन, नियोन, क्रिप्टन जैसे रासायनिक तत्व भी भरे होते हैं। सोडियम वैपर लैंप में की ट्यूब में मरकुरी (पारा) भर होता है। पारे के वाष्पीकरण से ही ये जगमगाता है, लेकिन इसका वाष्पीकरण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस भी भरी होती है।

ये भी पर्यावरण के साथ ही मनुष्य के लिए बेहद खतरनाक है। अनुपयोगी बल्ब और ट्यूबलाइट को खुले में फेंकने से पर्यावरण प्रदूषण के साथ ही गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कूड़ाघर में भी यदि सही तरीके से इनका समाधान न हो तो खतरा बना रहता है। ऐसे में इस कंटेनर की मदद से काफी हद तक इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसे इस तरह मरकुरी, फास्फोरस, बैरियम, लैंथनम, इट्रियम और मैग्नीज फास्फेट जैसे रसायन मौजूद होते हैं, जो पर्यावरण के अलावा शरीर के लिए भी घातक साबित होते हैं। मरकुरी के संपर्क में आने पर शरीर की कोशिकाएं मर जाती हैं। पर्यावरण में घुलकर इसका श्वास के साथ शरीर में जाना

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

उग्र में उत्सवों की उमंग से पर्यटन को लगे पंख

विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष

जितेंद्र शर्मा, लखनऊ

‘यूपी नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा...’ ढाई साल से लगातार गूंज रहे सरकार के इस मुगम का वास्ता न ताज के संगमरमरी हुनर से था, न लखनऊ के ऐतिहासिक इमामबाई से और न ही सूबे के किसी मुगल या ब्रिटिशकालीन स्मारक से। सरकार उग्र में भारत की तस्वीर दिखाना चाहती थी। मंशा योजनाओं में ढली। अयोध्या में दीप जले, काशी में घंटा-घड़ियाल तेज हुए और बरसाना से अबीर-गुलाल के लिए पर्सि उठी कि उत्सवों की उमंग में पर्यटक झुमने लगे और विदेशी धरती से भी तेज हो गई यूपी को देखने की रफ्तार।

पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास हर सरकार ने किया है। इससे पहले अखिलेश सरकार ने तमाम स्मारकों के आसपास सुविधाओं का विकास किया तो योगी सरकार पर्यटन विकास के एजेंडे पर चली। प्रदेश में भाजपा ऐसी

सरकार बनने के बाद से ही पर्यटन विभाग की सूची में पर्यटन स्थलों की प्राथमिकता में कुछ बदौलियां हुईं। अन्य क्रियाकलापों से ज्यादा जोर धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन देते पर रहा। लिहाजा, प्रदेश में जिन महत्वपूर्ण स्थलों पर श्रद्धालु ही पहुंचते थे, वहां के प्रति सैलानियों को आकर्षित करने के लिए पारंपरिक अवसरों को उत्सव का रूप दिया गया। मसलन, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव, मथुरा में जन्माष्टमी पर कुण्ठोत्सव, बरसाना में होली पर रंगोत्सव और बनारस में देव दीपावली और गंगा महोत्सव जैसे आयोजनों की शुरुआत योगी सरकार ने की। इससे एक माहौल बना और आस्था के यह केंद्र पर्यटन स्थल के स्वरूप में भी ढले। देश के साथ ही विदेशी सैलानियों की संख्या भी दो-ढाई साल में बढ़ी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

एच बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना के निर्माण कायाँ में धांधली की जांच में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) ने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाने शुरू कर दिये हैं। परियोजना में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदारों को पत्थर के भुगतान में बड़ा खेल किया था। जांच में इन तथ्यों के सामने आने के बाद ईओडब्ल्यू सिंचाई विभाग से कई दस्तावेज जुटा रही है। बताया गया कि करीब 17 करोड़ रुपये की धांधली की गई थी। पूरे मामले में सिंचाई विभाग के 16 अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में है।

शासन में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि व बुंदेलखंड में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एच बहुउद्देश्यीय परियोजना की शुरुआत की थी। परियोजना के कामों में अनियमितता की शिकायत पर तीन सदस्यीय कमेटी ने ठेके की प्रक्रिया, बांध स्थल के चयन, खर्च के खोशख किये गये काम व बिना मुआवजे के भूमि पर काम करने के चार बिंदुओं पर जांच की थी। समिति ने पत्थर के सही दाम व शासकीय क्षति



प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे।

फावल

देने पर रहा। लिहाजा, प्रदेश में जिन महत्वपूर्ण स्थलों पर श्रद्धालु ही पहुंचते थे, वहां के प्रति सैलानियों को आकर्षित करने के लिए पारंपरिक अवसरों को उत्सव का रूप दिया गया। मसलन, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव, मथुरा में जन्माष्टमी पर कुण्ठोत्सव, बरसाना में होली पर रंगोत्सव और बनारस में देव दीपावली और गंगा महोत्सव जैसे आयोजनों की शुरुआत योगी सरकार ने की। इससे एक माहौल बना और आस्था के यह केंद्र पर्यटन स्थल के स्वरूप में भी ढले। देश के साथ ही विदेशी सैलानियों की संख्या भी दो-ढाई साल में बढ़ी।

उग्र में बांध परियोजना में पत्थर की कीमत में हुआ था करोड़ों का खेल

तहकीकात

एच बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना में धांधली का मामला

ईओडब्ल्यू ने सिंचाई विभाग से हासिल किये कई दस्तावेज

का आंकलन भी किया था। पाया गया था कि ठेकेदार को पत्थर के भुगतान में करीब 100 रुपये घन मीटर की दर से खेल किया गया था। पूरे मामले में एक अधीक्षण अभियंता, दो अधिशासी अभियंता, सात सहायक अभियंता व छह अवर अभियंताओं की भूमिका जांच के दायरे में है। आरोपित अधिकारियों में एक सहायक अभियंता सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ईओडब्ल्यू जल्द अनुबंध को स्वीकृत करने वाले तत्कालीन मुख्य अभियंता से भी पृष्ठताछ की जानी है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में एच बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना की शुरुआत हुई थी। शासन ने जनवरी 2019 में धांधली की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी थी।



नदियों के आसपास के कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट होगा।

करोड़ खर्च होगा। इसके तहत तालाबों, पोखरों, जोहड़ों का निर्माण होगा। इसके लिए बड़े स्तर पर ढांचे निर्मित होंगे। जंगलों में 53 बिल्डिंग की छतों पर वर्षा जल संग्रहण किया जाएगा। इस कार्य पर 87 लाख खर्च होंगे। नदियों के आसपास के कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट होगा। भू संरक्षण गतिविधियां आरंभ होंगी। चैक डैम का निर्माण किया जा रहा है।

एनजीटी का आदेश : एनजीटी ने राज्य सरकार

गौरव डुडेजा, इटावा

गुजरात से बुधवार रात इटावा सफारी पार्क जाए गए सात शेरों का गुरवार को चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। इन्हें 30 दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। यहां पहले दिन शेरों ने पांच से सात किलो तक मीट खाया। खास बात यह कि इनमें तीन शेर-शेरनी उम्रदराज हैं।

गुजरात के जनागढ़ से 1400 किमी सफर करके आए शेर पूरी तरह स्वस्थ हैं। वन विभाग के 18 सदस्यीय टीम उन्हें लेने तीन दिन पहले गई थी। इनमें कानपुर डीएफाघर के डॉ.आरके शुक्ला, बिजनौर के डीएफओ सीमोन सहित इटावा सफारी पार्क के डीएफओ सुरेशचंद्र राजपूत, रंजर विनोत सक्सेना, बायोलाॅजिस्ट आरवी उत्तम, डॉ.आरपी वर्मा, डॉ.गौरव श्रीवास्तव, जू कीपर आसिफ थे।

यहां लाकर शेरों को ब्रीडिंग सेंटर से दो किमी दूर एनीमल हाउस में रखा गया है। सभी अलग-अलग बाड़े में हैं। दो एनीमल हाउस की दूरी भी करीब एक किमी है ताकि शेरों को संक्रमण

नैनी झील में ग्लास ब्रिज बनाने का सुझाव

जागरण संवाददाता, नैनीताल : नैनीताल भ्रमण पर पहुंचे चीन के चांगचिया चिये पर्यटन बोर्ड के अधिकारियों के दल ने नैनी झील में ग्लास ब्रिज बनाने समेत कई सुझाव पालिका प्रशासन को दिए हैं। पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी से मिले दल ने केबल कार, एक्सचेंज प्रोग्राम पर भी बातचीत की और आठ व नौ दिसंबर को चीन में होने वाले अंतरराष्ट्रीय मेयर सम्मेलन में उनको आमंत्रित किया। दल नैनीताल भ्रमण कर लौट चुका है। इधर, डीएम सविन बंसल ने कहा है कि चीनी अधिकारियों के दल के आने की सूचना पालिका द्वारा उन्हें नहीं दी गई। शासन से भी इस संबंध में कोई पत्र नहीं आया है।

इंडिया चाइना आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी के अध्यक्ष मुकेश यादव के नेतृत्व में चीनी अधिकारी वांग एर्द्दिमन, जियो रेंगोंओ, जोऊ ज्यूलिंग, डैंग सिकिसिंग बुधवार को नैनीताल पहुंचे थे। दल के सदस्यों का स्वागत पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी व अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने किया। गुरुवार को दल के सदस्यों ने बोट हाउस क्लब में पालिकाध्यक्ष नेगी व ईओ से नैनी झील में ग्लास ब्रिज बनाने, झील संरक्षण पार्किंग, रोप-वे इत्यादि पर चर्चा की। पालिका के अधिशासी अधिकारी वर्मा ने साफ किया है कि दल सिर्फ नैनीताल भ्रमण पर आया था। झील संरक्षण समेत कई विकास कार्यों पर सिर्फ चर्चा हुई थी, यदि बातचीत आगे बढ़ेगी तो इस संबंध में जिला प्रशासन व शासन को अवगत कराया जाएगा। इधर, सूत्रों से पता चला है कि दल में शामिल अधिकारियों को जापान में लेक डेवलप करने का अनुभव है व चीन में ग्लास ब्रिज बनाने वाले विशेषज्ञ टीम के सदस्य इसमें शामिल थे।

एक अक्टूबर से खुलेंगे मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय पार्क-अभयारण्य

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और अभयारण्य एक अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे। इसके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। ज्यादातर पार्क में शुरुआत के दो हफ्ते बुकिंग फुल हो गई है। शुरू के सात दिन पार्कों में वन्यप्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

बारिश और वन्यप्राणियों का प्रजनन सीजन होने के कारण एक जुलाई से पार्कों में पर्यटन बंद कर दिया गया था। तीन माह के तय समय के बाद एक अक्टूबर से पार्कों में पर्यटन शुरू होगा। हालांकि, प्रदेश में भारी बारिश के चलते कुछ पार्कों में पर्यटकों के लिए सैसपाटे की सुविधाएं नहीं हो पाई हैं, इसलिए पर्यटकों को सीमित क्षेत्र में ही घूमने दिया जाएगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सड़कों की मरम्मत और अन्य सुविधाएं जुटाने के लिए दो हफ्ते का समय लग सकता है। पार्क प्रबंधन ने इसकी सूचना जारी कर दी है।

30 दिन डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे गुजरात से इटावा लाए गए शेर

गौरव डुडेजा, इटावा

गुजरात से बुधवार रात इटावा सफारी पार्क जाए गए सात शेरों का गुरवार को चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। इन्हें 30 दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। यहां पहले दिन शेरों ने पांच से सात किलो तक मीट खाया। खास बात यह कि इनमें तीन शेर-शेरनी उम्रदराज हैं।

गुजरात के जनागढ़ से 1400 किमी सफर करके आए शेर पूरी तरह स्वस्थ हैं। वन विभाग के 18 सदस्यीय टीम उन्हें लेने तीन दिन पहले गई थी। इनमें कानपुर डीएफाघर के डॉ.आरके शुक्ला, बिजनौर के डीएफओ सीमोन सहित इटावा सफारी पार्क के डीएफओ सुरेशचंद्र राजपूत, रंजर विनोत सक्सेना, बायोलाॅजिस्ट आरवी उत्तम, डॉ.आरपी वर्मा, डॉ.गौरव श्रीवास्तव, जू कीपर आसिफ थे।

यहां लाकर शेरों को ब्रीडिंग सेंटर से दो किमी दूर एनीमल हाउस में रखा गया है। सभी अलग-अलग बाड़े में हैं। दो एनीमल हाउस की दूरी भी करीब एक किमी है ताकि शेरों को संक्रमण



सभी शेरों को अलग-अलग बाड़े में रखा गया है। फावल

न हो। देखभाल के लिए पांच जू कीपरों की टीम है। इनमें से चार शेरों को कुछ माह में गोरखपुर में बन रहे अशफाक उल्ला प्राणि उद्यान में भेजा जाएगा। 15 साल की तेजस्विनी : गुजरात से आए गए शेरों के इस कुनबे में पांच शेरनी व दो शेर हैं। इनमें सबसे बड़ी शेरनी तेजस्विनी 15 वर्ष की है। इसके बाद 13 वर्ष की मरियम, सात वर्ष की

कलेक्टर ने खून देकर गर्भवती आदिवासी महिला की जान बचाई



छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला अस्पताल में रक्तदान करते कलेक्टर चंदन कुमार।

नईदुनिया

जागरण विशेष

रंजीत बारट, सुकमा

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला में चितलनार थाने से आठ किलोमीटर दूर केरलापेड़ा निवासी 25 वर्षीय हिड़मे गर्भवती हैं। वह गंभीर एनीमिया से पीड़ित हैं। शरीर में मात्र तीन ग्राम ही हीमोग्लोबिन बचा था। पूरे शरीर में सूजन आ गई थी। गांव तक सड़क नहीं होने के कारण परिजन हिड़मे को चारपाई पर लिटाकर आठ किलोमीटर पैदल चलकर चितलनार पहुंचे। यहां से दोरनापाल ले गए, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति गंभीर बताई। तत्काल खून की व्यवस्था करने को कहा।

हिड़मे का ब्लड ग्रुप ए-पॉजीटिव निकला, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य के खून का मिलान इससे नहीं हो पाया। अस्पताल में भी इस ग्रुप का खून नहीं था। महिला के साथ उसकी कोख में पल रहे बच्चे की जान खतरे में थी। महिला को ए पॉजीटिव खून की जरूरत होने का संदेश कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। सुकमा कलेक्टर चंदन कुमार को जैसे ही इसकी जानकारी हुई, वे फौरन जिला अस्पताल पहुंच गए। बताया कि उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजीटिव है और वे रक्तदान को तैयार हैं। इस तरह उन्होंने रक्तदान कर एक साथ दो जिंदगियां बचा लीं। न केवल महिला का परिवार बल्कि क्षेत्र के आदिवासी समुदाय में इस घटना का बेहद सकारात्मक संदेश गया। 2011 बैच के आइएएस अफसर चंदन अपनी संवेदनशील कार्यशैली के बूते आदिवासी परिवारों का विश्वास जीतने में कामयाब हो रहे हैं। यह काम कहेने सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन जिन्हें यहां के जोखिम और चुनौतियों की जानकारी है, वह चंदन को इस पल्लव की सराहना करने से नहीं चूकते। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आदिवासियों की जिंदगी का हर पन्ना संघर्षों की स्याही से लिखा जाता है। यहां पदस्थ अधिकारी भी उन्हीं संघर्षों से गुजर कर नजीर पेश करते रहते हैं।

चंदन कुमार मूलतः नालंदा, बिहार के निवासी हैं। प्रारंभिक शिक्षा रांची, झारखंड में

परिजनों का खून जब नहीं हुआ मैच, वायरल संदेश देख खुद पहुंचे अस्पताल

सुकमा में खून-पसीने से विश्वास जीत रहे युवा कलेक्टर चंदन कुमार

कलेक्टर साहब तो हमारे लिए भगवान बनकर आए। पत्नी और मेरे बच्चे की जान बचाकर उन्होंने हमारे लिए जो किया, उसे कभी नहीं भूल सकते।

महिला के बारे में जानकारी मिलने पर अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि ब्लड बैंक में उसके ग्रुप का रक्त नहीं था। मां और बच्चे की जान बचाना जरूरी था। इस ग्रुप के उपलब्ध रक्तदाताओं ने कुछ दिन पहले ही रक्तदान किया था। इसलिए वे रक्त नहीं दे सकते थे। मैंने रक्तदान की बात कही और डॉक्टर तैयार हो गए।

चंदन कुमार, कलेक्टर, सुकमा

हुई। आइआइटि रुड़की से अध्ययन के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज को करियर के तौर पर चुना। वर्ष 2011 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुने गए और उन्हें छत्तीसगढ़ केन्द्र आवंटित हुआ। वे सहायक कलेक्टर बिलासपुर, एसडीएम बस्तर, जिला पंचायत सीओ कांकेर और राजनांदगांव में सेवा देने के बाद फरवरी 2019 में सुकमा के कलेक्टर पदस्थ किए गए हैं।

जीता दिल, मिल रही सहायता... : सुकमा के कलेक्टर चंदन कुमार ने गर्भवती आदिवासी महिला को खून देकर एक साथ दो जिंदगियां बचाई हैं...। सोशल मीडिया पर चंदन को खूब सराहा जा रहा है। वे यही कार्यशैली के बूते आदिवासी परिवारों का विश्वास जीतने में कामयाब हो रहे हैं। यह काम कहेने सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन जिन्हें यहां के जोखिम और चुनौतियों की जानकारी है, वह चंदन को इस पल्लव की सराहना करने से नहीं चूकते। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आदिवासियों की जिंदगी का हर पन्ना संघर्षों की स्याही से लिखा जाता है। यहां पदस्थ अधिकारी भी उन्हीं संघर्षों से गुजर कर नजीर पेश करते रहते हैं।

चंदन कुमार मूलतः नालंदा, बिहार के निवासी हैं। प्रारंभिक शिक्षा रांची, झारखंड में

साइकिल से पहाड़ नापेंगे 17 देशों के 100 प्रतिभागी

जागरण संवाददाता, शिमला : रोमांच से भरी एमटीबी साइकिल रैली वीरवार को शिमला में शुरू हुई। राज्यपाल बंडारा दत्तात्रेय ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया। पहाड़ पर सपाँले व चुनौतीपूर्ण रास्तों से होते हुए प्रतिभागियों को 470 किलोमीटर की दूरी आठ दिन में तय करनी होगी। रैली का समापन तीन अक्टूबर को कांगड़ा जिला के बीड़ में होगा। रैली में 17 देशों के 100 प्रतिभागी शामिल हैं। इनमें नौ अंतरराष्ट्रीय रेसर व सात महिला प्रतिभागी भी हैं। रैली की शुरुआत के दौरान रिज मैदान पर राइडरों के स्टैंट ने सभी को आकर्षित किया। जयपुर के लक्ष्य के स्टैंट की सभी ने सराहना की। गड्डरों ने पहले दिन रिज से मोशबरा के डाक बंगला तक 25 किलोमीटर सफर किया। हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स संस्था के अध्यक्ष मोहित सूद ने बताया कि राइडर स्कूली विद्यार्थियों को पंचायतों में साइकिल से सवारी देंगे। वे मत्स्याना, जैहलैली व बीड़ में वर्षा जल संग्रहण की जानकारी भी देंगे। वहीं, राज्यपाल ने रैली के आयोजकों के की सराहना की। उन्होंने कहा कि रैली के साथ पर्यावरण को बचाने का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है।

तैयारी

प्रदेश की सात प्रदूषित नदियों का होगा उपचार, वन विभाग ने की बड़ी पहल, एनजीटी के आदेशों का क्रियांवयन आरंभ

हिमाचल में जीवनदायिनियों को मिलेगा नया जीवन

रमेश सिंगटा, शिमला

नदियों को जीवनदायिनी माना जाता है। हिमाचल की कई नदियां आज प्रदूषण की मार झेल रही हैं। अब प्रदेश की सात प्रदूषित नदियों को नया जीवन मिलेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लए वन विभाग ने न केवल कार्ययोजना तैयार की है बल्कि इस दिशा में पहल भी की है। इस संबंध में योजना विभाग को प्रस्तुति दी गई है।

इसके मुताबिक इन नदियों के आसपास के कैचमेंट क्षेत्रों में चौधे लगाए गए हैं। इसकी शुरुआत हो गई है। मौजूदा सत्र में 50 हेक्टेयर भूमि में चौधे रोप धरती का श्रृंगार किया गया है। भू संरक्षण कार्यों का खाका बनाया गया है। संबंधित वन मंडल अधिकारियों को इसके लिए पैसा भी जारी हो गया है। प्राकृतिक झरनों का विकास होगा। इसके लिए 103 प्राकृतिक झरने को चिह्नित किया है। इनका विकास 105.60 लाख से होगा। इससे झरनों को प्राकृतिक रूप प्रदान किया जाएगा। ये वर्षा होते ही कल- कल करने लगेंगे। कईयों में साल भर पानी रहेगा। 11687 जगहों पर वर्षा जल संग्रहण के ढांचे तैयार होंगे। इस पर 425.86 लाख

11687 वर्षा जल ढांचों का होगा निर्माण



नदियों के आसपास के कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट होगा।

करोड़ खर्च होगा। इसके तहत तालाबों, पोखरों, जोहड़ों का निर्माण होगा। इसके लिए बड़े स्तर पर ढांचे निर्मित होंगे। जंगलों में 53 बिल्डिंग की छतों पर वर्षा जल संग्रहण किया जाएगा। इस कार्य पर 87 लाख खर्च होंगे। नदियों के आसपास के कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट होगा। भू संरक्षण गतिविधियां आरंभ होंगी। चैक डैम का निर्माण किया जा रहा है।

एनजीटी का आदेश : एनजीटी ने राज्य सरकार

103 जगहों पर विकसित किए जाएंगे प्राकृतिक झरने



फावल

अश्वनी खड्ड से फैला था पीलिया

कुछ वर्ष पूर्व शिमला के अश्वनी खड्ड में पेयजल का स्रोत के साथ घालमेल हो गया था। इससे शिमला शहर में पीलिया फैला और 32 लोगों को जान गंवानी पड़ी। अभी तक इसका पानी पेयजल के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

प्लास्टिक रिवर में तब्दील हुई थी अश्वनी खड्ड

कुछ समय पूर्व अश्वनी खड्ड प्लास्टिक रिवर में तब्दील हो गई थी। एनजीटी ने इससे संबंधित वायरर वीडियो का कड़ा सजाव लिया था। हिमाचल में प्लास्टिक पर पाबंदी है।

को प्रदूषित नदियों की साफ सफाई के लिए पिछले साल अमरस्थ महीने में कार्ययोजना तैयार करने

के आदेश दिए थे। इसके बाद कई विभागों ने कार्ययोजना तैयार करने पर कसरत की।

सतलुज नदी पर बनेगा पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला

हिमाचल प्रदेश में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सतलुज नदी पर बनाया जाएगा। प्लांट को बिलासपुर जिला में सतलुज नदी पर बने कोल डैम के जलाशय में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) लगाएगा। इसके लिए एनटीपीसी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

एनटीपीसी इससे पहले केरल के कायाकुलम में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगा चुका है। इसकी सफलता के बाद कोल डैम परियोजना के जलाशय में 100 एकड़ क्षेत्र में 15 मेगावाट पानी पेयजल के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। इस पर करीब 65 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से कोल डैम और सतलुज नदी पर कोई प्रभाव नहीं होगा। प्लांट इस तरह लगाया जाएगा जिससे डैम व नदी की खूबसूरती और बढ़ेगी। प्रदेश में इस तरह का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है।



प्रतीकात्मक

फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य पूरा करने के लिए लगाया जा रहा है। इसके लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

आनंद कुमार गुप्ता, निदेशक (वाणिज्य) एनटीपीसी

	संसेक्स 38,989.74 ▲ 396.22	निफ्टी 11,571.20 ▲ 131		सोना ₹ 38,685 ▼ ₹ 497		चांदी ₹ 47,235 ▼ ₹ 1580		डॉलर ₹ 70.88 ▼ ₹ 0.16		कूड (बेट) \$ 62.65 प्रति बैरल
---	--------------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------	--	-----------------------------------	---	---------------------------------	---	---

उम्मीद ▶ कहा – त्योहारी सीजन में जोर पकड़ेगी मांग, दूसरी छमाही में दिखेगी तेज ग्रोथ

किसी भी सेक्टर के सामने लिक्विडिटी का कोई संकट नहीं : सीतारमण

3-7 अक्टूबर तक 250 जिलों में आयोजित होंगे बैंकों के लोन कैंप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लिक्विडिटी में कमी के बारे में जताई जा रही चिंताओं को निराधार साबित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पितृपक्ष के बाद फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने पर उपभोग बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग जोर पकड़ेगी। ऐसा होने पर चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही (अक्टूबर से मार्च) के दौरान अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होगी।

सीतारमण ने गुरुवार को निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ बैठक के बाद यह बात कही। इस बैठक में वित्त सचिव राजीव कुमार और राज्यस्व सचिव अजय भूषण पांडेय के अलावा निजी क्षेत्र के आठ बैंकों, पांच

वित्त मंत्री ने की निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ बैठक



निर्मला सीतारमण

एनबीएफसी, पांच हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनियों, छह छोटे फाइनेंस बैंकों और चार माइक्रोफाइनेंस स्थानों के कुल 29 पदाधिकारी शामिल हुए। सीतारमण ने कहा कि वह निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पदाधिकारियों की बात सुनने के बाद कह सकती हैं कि किसी भी सेक्टर में लिक्विडिटी की समस्या नहीं है। किसी

भी संस्थान ने इस बारे में चिंता प्रकट नहीं की है। उन्होंने कहा कि इनमें से कई संस्थान देश के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं और उनका अनुभव बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों, अप्रोडेंबल हाउसिंग और सर्विस सेक्टर में कर्ज की मांग खासी है। बैंकों के पदाधिकारियों का कहना था कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में मांग में और तेजी आएगी। यह बैठक उनके लिए टॉनिक की तरह रही और इसमें उन्हें कई सकारात्मक बातें सुनने को मिलीं।

वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों के पदाधिकारियों ने उन्हें बताया है कि कॉर्पोरेट वहांनों की बिक्री में सुस्ती की वजह चक्रीय (साइक्लिक) है। 2010 में भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि, पैसेंजर वाहनों की बिक्री में सुस्ती ग्राहकों के मिजाज के चलते है। आने वाले समय में इसमें वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने सरकार की अप्रोडेंबल हाउसिंग योजना के तहत लोन की सीमा 45

लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने एनबीएफसी व एचएफसी के लोन के संबंध नियमों को लेकर निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों की चिंताओं को दूर करने के लिए पहली अक्टूबर को एक निर्देश जारी किया जाएगा।


बैठक में शामिल कोटक समूह के चेयरमैन उदय कोटक ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सभी निजी बैंक कर्ज की ब्याज दरें तय करने के लिए बाहरी बेंचमार्क इस्तेमाल करने के आरबीआइ के नियम का पालन करेंगे। अधिकतर निजी क्षेत्र के बैंक इसके लिए रेपो दर को बाहरी बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि 3-7 अक्टूबर को बैंक देश के 250 जिलों में लोन बांटने के लिए कैप लगाएंगे। इसकी सूची जल्द ही वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। यह पहला चरण होगा और इसमें निजी क्षेत्र के बैंक भी भाग लेंगे। इसके बाद दूसरा कैप दिवाली के आसपास लगाया जाएगा।

हुआवे अमेरिका को 5-जी टेक्नोलॉजी बेचने को तैयार

हंगकांग, शंघई: चीन की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजीज के संस्थापक व सीईओ रेन झेंगफेई ने कहा है कि वे अमेरिका की कंपनी को 5-जी टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करने को तैयार हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि वे इस टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका की चिंताओं को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। झेंगफेई ने कहा कि वे चिप डिजाइन की सभी जानकारी भी साझा करने को तैयार हैं।

6

तीन से सात अक्टूबर तक देशभर के 250 जिलों में लोन मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र के बैंक भी हिस्सा लेंगे।
— राजीव कुमार वित्त सचिव



जेट सीओसी की बैठक में शामिल हो सकेंगे नीदरलैंड्स के अधिकारी

नई दिल्ली, प्रेटर : नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनकलैट) ने नीदरलैंड्स के अधिकारियों को जेट एयरवेज की सीओसी बैठक में शामिल होने की इजाजत दे दी है। इससे पहले जेट एयरवेज के रिजल्टयुशन प्रोफेशनल (आरपी) और नीदरलैंड्स की अदालत के अधिकारियों ने एनकलैट को आश्वस्त किया कि वे भारत में चल रही दिवालिया प्रक्रिया में एक-दूसरे का सहयोग करेंगे। एनकलैट की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि नीदरलैंड्स के अधिकारी जेट एयरवेज के कर्जदाताओं की कमेटी (सीओसी) की बैठक में शामिल हो सकते हैं और उन्हें बैठक के मिनट्स (विचारणीय मुद्दों और उन पर चर्चा की संपूर्ण गतिविधियों का लिखित विवरण) भी मुहैया कराया जाए। एनकलैट ने डच कोर्ट के अधिकारियों को इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया से बाहर रखने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश को भी पलट दिया।

आदेश से पहले एनकलैट ने जेट एयरवेज के आरपी और नीदरलैंड्स की अदालत के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अपने करारनामे की प्रति ट्रिब्यूनल में जमा कराएं। एनसीएलटी ने नीदरलैंड्स की अदालत में जेट एयरवेज के खिलाफ चल रही दिवालिया प्रक्रिया

जेट एयरवेज और नीदरलैंड्स अधिकारियों के आपसी सहयोग के वादे पर एनकलैट ने दी इजाजत



शीर्ष ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों को करारनामे की प्रति भी मुहैया कराने को कहा

कंपनी 18 अप्रैल से परिचालन में नहीं है।

फाइल फोटो

को अमान्य घोषित कर दिया था। एनसीएलटी के इस फैसले के खिलाफ नीदरलैंड्स के अधिकारियों ने एनकलैट में याचिका दायर की। इसी की सुनवाई करते हुए गुरुवार को एनकलैट ने अधिकारियों को जेट एयरवेज की सीओसी बैठक में शामिल होने की इजाजत दे दी।

गौरतलब है कि इस वर्ष अप्रैल के मध्य में अस्थायी तौर पर बंद हो चुकी निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के खिलाफ नीदरलैंड्स की अदालत में भी दिवालिया प्रक्रिया चल रही है।

इसकी वजह यह है कि अप्रैल में ही नीदरलैंड्स की एच. एस्सर फाइनेंस कंपनी और वालेनबॉर्न ट्रांसपोर्ट ने 280 करोड़ रुपये के दावे के साथ स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की थी। उस याचिका के आधार पर जेट एयरवेज को वहां डिफॉल्टर करार दिया गया था और कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की गई थी। उससे पहले नीदरलैंड्स के एक्सटर्नल मैन शिफोल एयरपोर्ट पर खड़े जेट एयरवेज विमान को जब्त कर लिया गया था।

आयकर छूट पर सही समय में फैसला लेगी सरकार

नई दिल्ली, प्रेटर : केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि सरकार सही समय आने पर आयकर छूट सीमा बढ़ाने के बारे में निर्णय लेगी। पिछले सप्ताह सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया था। इसके बाद से मांग और खपत को बढ़ावा देने के लिए आयकर छूट सीमा बढ़ाने की मांग लगातार बढ़ रही है, ताकि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके।

ठाकुर ने कहा, 'जब आयकर राहत पर फैसला लेने का समय आएगा तो सरकार इस पर निर्णय लेगी। सरकार पहले भी आयकर की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर चुकी है। भविष्य में भी जब भी ऐसा समय आएगा, हम इस मामले पर विचार करेंगे।' पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) पर रिजर्व बैंक के प्रतिबंध को लेकर वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक की देश में अपनी भूमिका है और वह अपना काम बेहतर तरीके से करता है।

उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आरबीआइ ने यह फैसला

कॉर्पोरेट टैक्स घटाने से विकास को मिलेगी गति

नई दिल्ली : वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से देश में विदेशी निवेश बढ़ेगा और विकास को गति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नकली, तस्करी किए हुए और पायरेटेड प्रोडक्ट से इकोनॉमी को क्षति पहुंचती है और रोजगार सृजन को भी धक्का लगता है। ठाकुर का कहना था कि टैक्सटाइल, तंबाकू उत्पाद, गारमेंट्स, कैपिटल गुड्स और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में तस्करी रोकने से रोजगार के अवसरों में 16.36 लाख का इजाफा हो सकता है। इन पांच क्षेत्रों में तस्करी से भारत को सालाना 1.17 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है।

किया होगा, ताकि ग्राहकों और बैंक दोनों का लाभ हो।

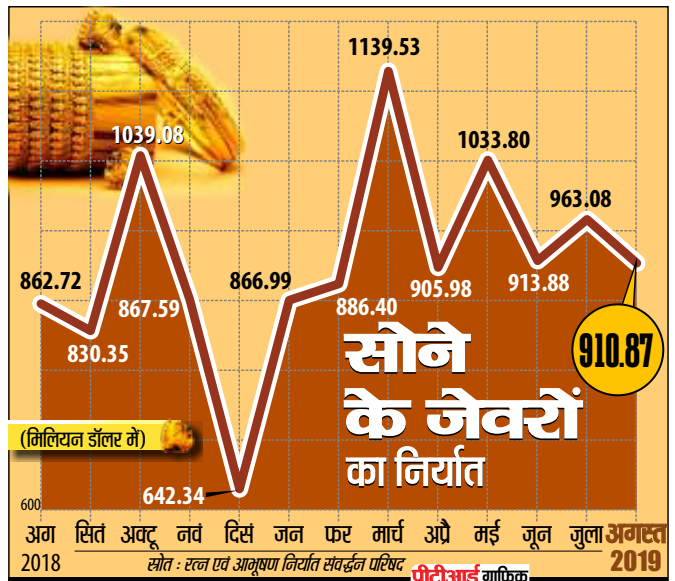
जीएसटी नेटवर्क ने शुरू की ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया

नई दिल्ली, प्रेटर : जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए गुरुवार को ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। जीएसटी परिषद ने इस संबंध में निर्णय किया था। जीएसटी नेटवर्क ने बयान में कहा कि ऑनलाइन रिफंड व्यवस्था पेश करने से अब करदाता आसानी से रिफंड आवेदन (आरएफडी 01 फॉर्म) कर सकते हैं और टैक्स अधिकारी भी इसकी प्रोसेसिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। करदाताओं और अधिकारियों के बीच सभी पत्राचार भी ऑनलाइन होगा। जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया इस सप्ताह बुधवार से प्रभावी हो गई है। इससे पहले, एक ही टैक्स आर्थॉरिटी के द्वारा केंद्र और राज्य जीएसटी के लिए रिफंड प्रोसेसिंग की जाती थी। लेकिन रिफंड के वितरण का काम केंद्र और राज्य कर विभाग के अधिकारी अलग-अलग करते थे। इससे रिफंड में देरी होती थी। इसमें कहा गया है कि नई प्रणाली ने इस पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। टैक्स अधिकारी की ओर से प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद स्वीकृत राशि पीएफएमएस



प्रतीकात्मक

प्रणाली के माध्यम से करदाता के बैंक खाते में जमा हो जाएगा। जीएसटी नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार ने कहा कि नई रिफंड प्रक्रिया करदाताओं और कर अधिकारियों दोनों को एक सहज अनुभव देगी। उन्होंने कहा, 'नई रिफंड प्रक्रिया से रिफंड देने की गति तेजी होगी और जीएसटी अनुपालन में सुधार होगा। करदाता जीएसटी पोर्टल पर यह देख सकेंगे कि उनका रिफंड आवेदन प्रोसेसिंग के किस चरण में है। वे ऑनलाइन नॉटिस का जवाब दे सकेंगे।'



ग्लोबल संकेतों पर सराफा बाजार में सुस्ती

नई दिल्ली, प्रेटर : अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमोडिटी के भाव में गिरावट का असर गुरुवार को सोना-चांदी के भाव पर स्पष्ट देखने में आया। दिन के कारोबार में सोना 497 रुपये टूटकर 38,685 रुपये प्रति 10 का रह गया। चांदी के भाव में गुरुवार को 1,580 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दिन के कारोबार में नई दिल्ली में चांदी 47,235 रुपये किलोग्राम

की रह गई।

एचडीएफसी सिक्युरिटीज में पीसीजी के एडवाइजरी हैड देवर्ष वकील का कहना था कि त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले भाव में कमी से इनकी मांग बढ़ने की उम्मीद है। न्यूयॉर्क में सोना गिरकर 1,508 डॉलर, जबकि चांदी भी सुस्ती के साथ 17.90 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर कारोबार कर रहे थे।

सटीक आंकड़ों से बदल रही कृषि क्षेत्र की तस्वीर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कृषि क्षेत्र में सटीक आंकड़ों और आधुनिक टेक्नोलॉजी की भूमिका अहम है, जिससे खेती की तस्वीर तेजी से बदल रही है। तीसरे एग्रीकल्चरल आउटलुक फोरम, 2019 के उद्घाटन समारोह में कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस ने कृषि क्षेत्र के आंकड़ों को तैयार करने में मदद मिली है।

दो दिवसीय फोरम के पहले दिन कृषि सचिव ने कहा कि कृषि क्षेत्र की योजनाओं के संचालन में किये जाने वाले रजिस्ट्रेशन से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। देश के सभी हिस्सों में किसानों की जोत को डिजिटल किया जा चुका है। फसल बीमा, संचालन हेल्थ कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के दौरान आंकड़े तैयार करने में मदद मिली है। इससे किसानों तक सहयता पहुंचाने में भी सहूलियत हो रही है। उन्होंने बताया कि देश के चार राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के चार जिलों में बायलट परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इन जिलों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी का जमकर प्रयोग किया जा रहा है। इस दौरान देश और दुनिया के दूसरे हिस्से से

तीसरा एग्रीकल्चरल आउटलुक फोरम-2019 दिल्ली में शुरू



प्रतीकात्मक

आये कृषि वैज्ञानिकों और नीति नियामकों के बीच विचार-विमर्श किया जाएगा। आंकड़ों और इन आधुनिक तकनीकों के माफत ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पुनर्वाज के भुगतान में भारी मदद मिली है। दो करोड़ किसानों को 3.5 बिलियन डॉलर तक की धनराशि वितरित की जा चुकी है। कृषि उपज की खरीद बिक्री जैसे प्रावधानों में सहूलियत मिलने लगी है। उन्होंने उम्मीद जताई की इस दौरान कुछ नई बातें उभर कर सामने आएंगी, जिससे किसानों की दशा में सुधार लाने में सहयता मिलेगी। इस दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉ. रमेश चंद ने भी संबोधित किया।

मुंबई, प्रेटर : पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि म्यूचुअल फंड और उनके कर्जदारों के बीच बकाया के भुगतान में 'विराम' देने जैसे समझौते का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी निकायों को यह समझ लेना चाहिए और उन्हें इसका पालन करना होगा। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने संवाददाताओं से कहा कि लेनदेन में कुछ समय के लिए यथास्थिति रखने जैसा प्रावधान किसी भी नियम में नहीं है। हमने इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। निकायों को मौजूद नियमों का ही पालन करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों सुभाष चंद्र के नेतृत्व वाले एक्सेल ग्रुप ने दावा किया है कि उसे विभिन्न म्यूचुअल फंड हाइजेरिंग सहित सभी कर्जदाताओं की तरफ से बकाया की वसूली की समस्याओं का बढ़ाने को लेकर पूरा समर्थन मिला हुआ है। इसी बारे में त्यागी से खूब गुस्सा था कि कुछ निकाय कैसे अब भी विराम देने के समझौते कर रहे हैं।

डीएचएफएल के पुनर्गठन के मामले में एसबीआइ द्वारा छूट मांग जाने के बारे में त्यागी ने कहा कि हमारे पास पहले से म्यूचुअल फंड

राइट्स इश्यू का समय घटाने पर निर्णय जल्द

मुंबई : सेबी ने गुरुवार को कहा कि वह राइट्स इश्यू में लगाने वाले समय को कम करने के प्रस्ताव के बारे में जल्दी ही अपना पक्ष रखेगा। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने फिक्की के एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। अभी राइट्स इश्यू की प्रक्रिया में 55 से 58 दिन लगते हैं। सेबी ने इस समय को घटाकर 31 दिन करने के बारे में प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा, 'सेबी ने राइट्स इश्यू में लगाने वाले समय को कम करने के लिए

परामर्श पत्र जारी किया है। हम जल्दी ही इस बारे में अपनी राय रखेंगे।' त्यागी ने कहा कि हाल के दिनों में राइट्स इश्यू को लेकर गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है। सेबी वैकल्पिक निवेश कोष (एआइएफ) की रूपरेखा को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में है। कंपनी के प्रमोटरों के विचार का भी परीक्षण किया जा रहा है। यह भी देख रहे हैं कि क्या इसकी जगह निरंतर शेयरधारक का विचार अपनाया जा सकता है।

के लिए इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट्स (आईसीए) की व्यवस्था पहले से है, और यही नीति भी है। उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को एनएसई में अपनी हिस्सेदारी बेचना पड़ सकती है। एलआईसी और आइडीबीआई बैंक की एनएसई में करीब 14 प्रतिशत संयुक्त हिस्सेदारी है। सेबी के शेयरधारिता नियम के मुताबिक शेयर बाजारों के मामले में कोई भी संस्थागत निवेशक 15 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं रख

सकता है जबकि कोई कारोबारी सदस्य अथवा ब्रोकर शेयर बाजारों का पांच प्रतिशत से ज्यादा होल्डिंग नहीं रख सकता है। एलआईसी पहले संस्थागत निवेशक के तौर पर जाना जाता था लेकिन आइडीबीआई के अधिग्रहण के बाद वह एक कारोबारी सदस्य के तौर पर जाना जाता है। पीडब्ल्यूसी मामले में सिक्युरिटीज अपीलेंट ट्रिब्यूनल यानी सेंट के फैसले के बारे में उन्होंने कहा कि सेबी की कानूनी मामलों की टीम आदेश का अध्ययन कर रही है।

इन्फोसिस को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड

बेंगलूर, एनएसई : देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड को 'क्लाइमेट म्यूटल नाउ' कैटेगरी में युनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला है। एक बयान में कंपनी ने कहा कि भारत से वह इकलौती कंपनी है जिसके नाम इस अवार्ड की घोषणा की गई है। कंपनी के बयान के मुताबिक उसे यह अवार्ड इस वर्ष दिसंबर में पितली के सैंटीयागो में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले दिनों इन्फोसिस को दुनिया की तीसरी सबसे प्रतिष्ठित कंपनी घोषित किया गया था। मशहूर अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा इस वर्ष के लिए दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची में इन्फोसिस को तीसरा स्थान मिला है। कंपनी के लिए यह इसलिए बेहद महत्वपूर्ण और सम्मानजनक बात है, क्योंकि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों की पिछले वर्ष की फोर्ब्स सूची में इन्फोसिस का स्थान 31वां था।

फोर्ब्स की इस सूची में कंपनियों का



फाइल फोटो

मूल्यांकन ग्राहकों के भरोसे पर खरा उतरने, ईमानदारी, सामाजिक आचरण, कर्मचारियों के प्रति कंपनी का उचित व्यवहार और उसके प्रोडक्ट व सर्विसेज के प्रदर्शन जैसे मानदंडों पर किया जाता है। इस सूची के लिए इस वर्ष फोर्ब्स ने स्टैटिस्टा से करार किया, जिसने 50 देशों में 15,000 से ज्यादा उत्तरदाताओं के बीच सर्वे किया।

संकेत

396.22 अंक सुधरकर 38,989.74 अंकों पर बंद हुआ संसेक्स, 131 अंकों की मजबूती के साथ 11,571.20 अंक पर पहुंचा निफ्टी

मुंबई, प्रेटर : विदेशी बाजारों के सकारात्मक रुख के दम पर घरेलू शेयर बाजारों ने महीने के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) की एक्सपायरी के दिन सधी वापसी की। बैंकिंग, ऑटो और एनर्जी स्टॉक्स में खरीदारी से उत्साहित बीएसई का 30 शेयर्स वाला संसेक्स 396.22 अंक यानी 1.03 फीसद सुधरकर 38,989.74 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयर्स वाला निफ्टी भी गुरुवार को 131 अंक यानी 1.15 फीसद चढ़कर 11,571.20 अंक पर स्थिर हुआ। गुरुवार को संसेक्स ने इंडा-डे में संसेक्स 39,000 के ऊपर भी गया था। सितंबर के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी के बाद घरेलू शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला शुरू हुआ। जानकारों के मुताबिक अगले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक से पहले निवेशकों का रुख सकारात्मक था। संसेक्स में वेदांता, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, एचएंडटी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 6.47 फीसद तक का उछाल देखा गया। हालांकि यस बैंक, इन्फोसिस, एचयूएल, एचएसएल टेक,



प्रतीकात्मक

एचडीएफसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और टीसीएस के शेयरों में 4.93 फीसद की गिरावट देखी गई।

दिन के कारोबार के बारे में जियोजित फाइनेशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर का कहना था कि बाजार में निवेशकों के उत्साह का आधार व्यापक था। ऑटो, बैंक और मेटल सेक्टर के शेयरों ने बढ़त का नेतृत्व किया।

ट्रेड वार में नरमी के संकेतों और घरेलू बाजार में कई तरह की सहूलियतों को देखते हुए यह उछाल जारी रहने की उम्मीद है।

सेक्टरल इंडेक्स के मामले में बीएसई मेटल, रियल्टी, ऑयल व गैस, ऑटो, एनर्जी, बेसिक मैटीरियल, कैपिटल गुड्स, बैंकेक्स और फाइनेंस इंडेक्स में 4.20 फीसद का उछाल दर्ज किया गया।

निवेशकों की संपत्ति 1.57 लाख करोड़ रुपये बढ़ी

नई दिल्ली : बीएसई संसेक्स में करीब 400 अंकों की बढ़ोतरी के साथ ही गुरुवार को निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.57 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। इंडा-डे में संसेक्स ने 564.55 अंकों का उछाल दर्ज किया था। गुरुवार की बढ़त के बाद कारोबार के आखिर में बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 1,48,45,854.70 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

बीएसई-मिडकैप व स्मॉलकैप इंडेक्स भी 0.92 फीसद तक उछले।

एशिया के अन्य बाजारों में हंग सेंग, निक्केई और कोरपी चढ़कर बंद हुए। वहीं, शंघाई कंपोजिट को गिरावट का सामना करना पड़ा। अधिकांश यूरोपीय बाजारों में कारोबार सकारात्मक स्तर पर शुरू हुई।

आसान नहीं है ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाना

यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत के मसले पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैसी पेलोसी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने की हरी झंडी दे दी है। ट्रंप ने महाभियोग प्रक्रिया को राष्ट्रपति का उत्पीड़न बताते हुए मजाक करार दिया है। ऐसे में आइये जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर महाभियोग कैसे लगता है?, क्यों लगता है और इसका मतलब क्या है?



क्या है महाभियोग?

महाभियोग एक ऐसा प्रावधान है, जो कांग्रेस (अमेरिकी संसद) को अमेरिकी राष्ट्रपति को हटाने की अनुमति देता है। अमेरिकी संविधान के तहत, प्रतिनिधि सभा (निचले सदन) में बहुमत के बाद महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। महाभियोग तब लाया जाता है जब देशद्रोह, घूस या फिर किसी बड़े अपराध में शामिल होने का शक हो।

संख्या बल की स्थिति

प्रतिनिधि सभा में अभी डेमोक्रेटिक पार्टी के 235 सदस्य हैं और रिपब्लिकन पार्टी के 199 सदस्य हैं और एक निर्दलीय है। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप पर हमला कर सकती है। वहीं सीनेट में रिपब्लिकन 53 और डेमोक्रेटिक के 45 सदस्य हैं और दो निर्दलीय हैं, जो आमतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वोट करते हैं। राष्ट्रपति को दोषी सिद्ध करने के लिए 67 मतों की आवश्यकता होगी, जो तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कुछ रिपब्लिकन राष्ट्रपति के खिलाफ मतदान करें।

कौन हैं नैसी पेलोसी?

नैसी पेलोसी अमेरिका के कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद हैं। वह इस साल जनवरी में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर चुनी गईं। अमेरिका में राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के बाद वह तीसरी सबसे ताकतवर राजनीतिक शख्सियत हैं। अमेरिका में पिछले साल के अंत में संसद के लिए मध्यवर्धि चुनाव हुए, जिसके बाद निचले सदन यानी कि प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत में आई और नैसी स्पीकर बनीं।

महाभियोग का इतिहास

अमेरिका के इतिहास में कई बार महाभियोग का बदल गहराया है, लेकिन केवल दो राष्ट्रपतियों को ही इसका सामना करना पड़ा। 1968 में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन और 1998 में बिल क्लिंटन पर महाभियोग चलाया गया था, लेकिन सीनेट ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया। वहीं 1974 में राष्ट्रपति रिचर्ड निकसन ने हटायो जाने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।



क्या है प्रक्रिया?

अगर किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है तो संसद की न्यायिक समिति इन आरोपों की जांच करती है। फिर रजामंदी होने पर आरोप तय किए जाते हैं। इन आरोपों पर प्रतिनिधि सभा में वोटिंग होती है। अगर वोटिंग महाभियोग के पक्ष में होती है तो फिर मामला सीनेट को सौंप दिया जाता है। फिर सीनेट कोर्ट की तरह काम करती है और अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं। सुनवाई के लिए सीनेटर्स के बीच से कुछ सांसदों को चुना जाता है, जो कि मैनेजर के रूप में जाने जाते हैं। ये मैनेजर्स अभियोगकों की भूमिका निभाते हैं। इस ट्रायल के दौरान राष्ट्रपति के वकील अपना पक्ष रखते हैं। सुनवाई पूरी होने के बाद सीनेट महाभियोग के हर आर्टिकल पर वोट करती है। यदि वोटिंग में कम से कम दो तिहाई सीनेटर राष्ट्रपति को दोषी पाते हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है।

पहली बार नहीं

2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के लिए रूस के साथ ट्रंप की मिलीभगत के आरोपों के बाद उन पर महाभियोग चलाने की बात हुई थी। इसके अलावा डेमोक्रेटिक कांग्रेस की चार महिला सांसदों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करने पर भी उनके खिलाफ महाभियोग की मांग उठी थी। हालांकि, यह अलग बात है कि इन मामलों में ट्रंप पर महाभियोग नहीं चलाया जा सका और वह पद पर बने रहे।

न्यूज गेलरी

श्रीलंका के आवास मंत्री सजित प्रेमदासा लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव
कोलंबो : श्रीलंका में सत्तारुढ़ यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने अपने उप नेता और आवास मंत्री सजित प्रेमदासा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है।52 वर्षीय सजित पूर्व राष्ट्रपति आर प्रेमदासा के बेटे हैं, जिनकी 1993 में एलटीटीई के आत्मघाती हमले में मौत हो गई थी।16 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए विपक्ष ने पूर्व रक्षा मंत्री गोतभाया राजपक्षे को अपना उम्मीदवार बनाया है।
(संयंतर)

ऑस्ट्रेलिया ने 119 साल बाद गर्भपात को किया वैध

कैनबरा : ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत की विधायिका ने भी गुरुवार को गर्भपात संबंधी नए कानून पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही पूरे ऑस्ट्रेलिया में गर्भपात को कानूनी मान्यता मिल गई है। देश में इससे पहले तक गर्भपात गैरकानूनी था। इस अपराध के लिए दस साल जेल की सजा अपनाया था। यह कानून पिछले 119 साल से प्रभावी था। नए कानून के तहत महिलाएं अब स्वेच्छ से किसी पंजीकृत चिकित्सक की निगरानी में 22 हफ्ते तक के अपने गर्भ को गिरावा सकेंगी।
(आइएनएसएस)

पाक के ट्रांसपोर्टरों के लिए अफगानिस्तान में वीजा अनिवार्य
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर अब बगैर वीजा के अफगानिस्तान की सीमा में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अफगान सरकार ने पाकिस्तानी ट्रांसपोर्टरों के लिए वीजा लेना अनिवार्य कर दिया है। वे वीजा के साथ यात्रा संबंधी अन्य दस्तावेज होने पर ही तोरखाम सीमा के रास्ते अफगानिस्तान में दाखिल हो सकेंगे।
(आइएनएसएस)

सऊदी क्राउन प्रिंस की निगरानी में हुई थी पत्रकार खशोगी की हत्या

रियाद, रायटर/आइएनएसएस : एक डाक्यूमेंटरी में दावा किया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान ने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। क्राउन प्रिंस ने कहा कि खशोगी की हत्या को उनकी निगरानी में अंजाम दिया गया था। इस डाक्यूमेंटरी का प्रसारण एक अक्टूबर को किया जाएगा। खशोगी की पिछले साल दो अक्टूबर को सऊदी एजेंटों ने हत्या कर दी थी। इसे तुर्की के इस्तांबुल शहर स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में अंजाम दिया गया था। खशोगी की हत्या के लिए 15 सऊदी एजेंट विशेष विमान से तुर्की गए थे। उनका शव आज तक नहीं मिला। इस हत्याकांड पर क्राउन प्रिंस ने सार्वजनिक तौर पर कभी कोई बयान नहीं दिया है।

‘द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब’ नामक डाक्यूमेंटरी के अनुसार, मुहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी प्रसारक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेस (पीबीएस) के मार्टिन स्मिथ से कहा, ‘मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूँ क्योंकि यह मेरी निगरानी में हुआ था।’ स्मिथ ने जब उनसे यह पूछा कि आकांक्षी जासकरी के बगैर हत्या को कैसे अंजाम दिया गया? तब उन्होंने कहा, ‘हमारे मुल्ले की आबादी दो करोड़ है और करीब 30 लाख सरकारी कर्मचारी हैं।’ खशोगी की हत्या में सरकारी विमान के इस्तेमाल के सवाल पर सऊदी प्रिंस ने कहा, ‘चीजों का पालन करने के लिए मेरे पास अधिकारी और मंत्री हैं और वे जिम्मेदार हैं। उनके पास यह करने का अधिकार है।’ स्मिथ ने बताया कि यह बातचीत कैमरे के सामने नहीं हुई थी।

डाक्यूमेंटरी का दावा, सलमान ने ली पत्रकार की हत्या की जिम्मेदारी

एक अक्टूबर को प्रसारित होगी ‘द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब’ डाक्यूमेंटरी

डाक्यूमेंटरी में सऊदी पत्रकार का भी इंटरव्यू

डाक्यूमेंटरी में सऊदी पत्रकार खशोगी का भी इंटरव्यू है। यह इंटरव्यू हत्या के कुछ महीने पहले लिया गया था, लेकिन कभी सामने नहीं आया था। इसमें उन्होंने बताया कि वह कैसे क्राउन प्रिंस के समर्थक से आलोचक बन गए थे।

क्राउन प्रिंस ने दिया था आदेश
अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए और कई पश्चिमी देशों ने यह दावा किया था कि खशोगी की हत्या का आदेश क्राउन प्रिंस ने दिया था। जबकि सऊदी अरब ने कहा था कि इसमें उनकी ओकी भूमिका नहीं थी।
क्राउन प्रिंस के थे आलोचक : खशोगी अमेरिका में रहते थे और वाशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखते थे। वह क्राउन प्रिंस के लिए आलोचक थे। सऊदी सरकार ने पहले उनकी हत्या होने की बात नहीं मानी, लेकिन दुनियाभर में आलोचना के बाद स्वीकार किया कि दूतावास में उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सऊदी के 11 संदिग्धों को आरोपित किया गया है।

लंदन, प्रे्ट : सुप्रीम कोर्ट के संसद के निर्लंबन को अवैध ठहराए जाने के बाद गुरुवार को सांसदों के सामने आए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन विपक्ष पर बरस पड़े। कहा कि ब्रेकिजट को टालना देश की जनता के साथ धोखा करना है। विपक्ष में अगर हिम्मत है तो वह सदन में अविवशवास प्रस्ताव लाए और चुनाव का सामना करें। लेकिन मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी के नेता जर्मी कॉर्बिन ने प्रधानमंत्री से उनके इस्तीफे की मांग की है।

आक्रोशित जॉनसन ने कहा, मतदाताओं का सामना करने की जगह विश्वी दुम दबाकर चुनाव से भाग रहे हैं। मतदाताओं का फैसला सुनने की जगह वे कोर्ट के पास लौड़ गए। उन्हें यह कहने में कोई हिचक नहीं कि कोर्ट ने गलत फैसला दिया। जॉनसन ने यह बात मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संसद के निर्लंबन के सरकार के फैसले को रद्द करने पर कही। प्रधानमंत्री ने ये बातें हाउस ऑफ कॉमंस में विपक्ष की संसद के निर्लंबन पर माफ़ी मांगने की लगातार मांग के बीच कही।

विपक्ष के नेता कॉर्बिन ने जॉनसन को खतरनाक नेता करार देते हुए कहा कि वह खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, जबकि वह वास्तव में प्रधानमंत्री पद के काबिल ही नहीं हैं। इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चर्चा के मध्य ही जॉनसन नाटकीय तरीके से सदन के बाहर चले गए जबकि स्पीकर जॉन बर्को

ब्रिटेन में फिर से बैठी संसद में हुई गर्मागर्म बहस



बोरिस जॉनसन।

फाइल

ने उन्हें सीट पर बैठने के लिए कहते रहे। बहन रंचेल जॉनसन ने संसद में प्रधानमंत्री जॉनसन के भाषण से असहमति जताते हुए उसे बेवस्वाद बताया है।

हत्या की शिकार सांसद का उल्लेख कर मांगा समर्थन

सदन में चर्चा के मध्य प्रधानमंत्री जॉनसन ने संसद में बिना शर्त ब्रेकिजट के खिलाफ कानून बनाने को तुच्छ आचरण बताया, जो महज यूरोपीय यूनियन से अलगाव को टालने के लिए किया गया। उन्होंने लेबर पार्टी की सांसद जो कॉक्स की याद करते हुए कहा कि उनकी आत्मा को सम्मान देने के लिए ही विपक्ष ब्रेकिजट के लिए पूरी हो जाने दें। कॉक्स को 2016 में

ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री की सातवीं हार, नहीं दी छुड़ी

लंदन, एएफपी : ब्रिटेन की संसद में गुरुवार को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री ने संसद से तीन दिन का अवकाश मांगा था। इस दौरान संसद की कार्यवाही स्थगित रहती, लेकिन संसद ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। संसद में उनके प्रस्ताव के खिलाफ 306 वोट पड़े जबकि समर्थन में 289 सांसदों ने मतदान किया। बोरिस जॉनसन की संसद में यह लगातार सातवीं हार है। सत्तारूढ़ दल का वार्षिक सम्मेलन आगामी रविवार से बुधवार तक मैनचेस्टर में होगा है। प्रधानमंत्री की ओर से यह प्रस्ताव संसद में ब्रेब्रिजट और संसद के निर्लंबन पर आए सुप्रीम कोर्ट पर गर्मागर्म बहस के बाद आया था।

ब्रिटेन फर्स्ट का नारा लगाते हुए एक विश्विष्ट आदर्श ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में कॉक्स के पति ने राजनीतिक मकसद के लिए अपनी स्वर्गीय पत्नी का नाम इस्तेमाल किए जाने पर अफसोस जाहिर करते हुए सभी से परस्पर सम्मान की अपील की।

ईरान कर रहा आधुनिक सेंट्रीफ्यूज का उपयोग

वियना, एएफपी : दुनिया की महाशक्तियां के साथ 2015 में किए परमाणु समझौते का उल्लंघन कर ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के लिए आधुनिक सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के नतांज संयंत्र में यूरेनियम को संवर्धित करने के लिए आधुनिक सेंट्रीफ्यूज (आइआर-4 और आइआर-6) को एकत्रित किया जा रहा था या एकत्रित करने की तैयारी की जा रही थी। 2015 में दुनिया की महाशक्तियों के साथ समझौते के तहत प्रतिबंधों से ढील के एवज में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कुछ बंदिशें लगाई गई थीं। इसके तहत ईरान को यूरेनियम संवर्धन के लिए कम क्षमता वाले आइआर-1 सेंट्रीफ्यूज के इस्तेमाल की ही अनुमति दी गई थी। आइआर-4 और आइआर-6 सेंट्रीफ्यूज आइआर-1 के मुकाबले ज्यादा तेजी से यूरेनियम का संवर्धन कर सकते हैं।

मालूम हो कि पिछले साल मई में अमेरिका इस समझौते से हट गया था और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए थे। इस समझौते में ईरान और अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस भी शामिल थे। उन्होंने समझौते को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन ईरान का आरोप है कि यूरोपीय देशों ने पर्याप्त कोशिशें नहीं कीं।

रुहानी ने कहा, अमेरिका प्रतिबंध हटाए तो बात करेगे
न्यूयॉर्क, एएफपी : ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी ने गुरुवार को कहा कि वह अमेरिका के साथ अवश्य वार्ता करेंगे अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रतिबंध हटा लें और ईरान पर अधिकतम दबाव की अपनी नीति छोड़ दें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के एक दिन बाद रुहानी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘अगर हम उस दौर में पहुंच सकें जब ये पूर्व शर्तें मेज से गायब हो चुकी हों तो निश्चित तौर पर अमेरिका से बातचीत की संभावना है।’

ईरान ने जांची प्रमुख तेल एवं गैस संयंत्रों की साइबर सुरक्षा

दुबई, रायटर : अमेरिका के संभावित साइबर हमले के मद्देनजर ईरान ने अपने प्रमुख तेल एवं गैस संयंत्रों की सुरक्षा जांच शुरू की है। तेल मंत्रालय की समाचार एजेंसी ‘शाना’ ने यह जानकारी दी है। दरअसल, अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी तेल संयंत्रों पर 14 सितंबर को हुए हमले के मद्देनजर वाशिंगटन ईरान के खिलाफ साइबर हमलों पर विचार कर रहा है। इस क्रम में बुधवार को पारस विशेष आर्थिक ऊर्जा जोन के प्रमुख पिपेज मौसवी ने क्षेत्र का दौरा किया और वरिष्ठ प्रबंधकों से मुलाकात की। इनमें साइबर सुरक्षा के प्रभारी भी शामिल हैं।

इराक युद्ध का विरोध करने वाले फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति का निधन

पेरिस, एपी : फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जाक शिराक का गुरुवार को निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। शिराक फ्रांस के पहले नेता थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के नरसंहार में अपने देश की भूमिका को स्वीकार किया था। 1995 से 2007 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे शिराक अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हुए थे। उन्होंने 2003 में इराक पर अमेरिका के हमले का विरोध किया था। वह पेरिस के मेयर भी रहे थे।

शिराक के दामाद फ्रेडरिक सलात-बैरेक्स ने गुरुवार को अपने ससुर के निधन की जानकारी दी। उन्होंने हालांकि मौत का कोई कारण नहीं बताया। वर्ष 2007 में राष्ट्रपति पद से हटने के बाद शिराक को कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। शिराक की छवि वैश्विक राजनेता की थी, लेकिन वह फ्रांस में आर्थिक सुधार करने में विफल हो गए थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राजनीति के लिहाज से कई साहसी फैसले लिए थे। उन्होंने राष्ट्रपति के कार्यकाल को सात से



फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जाक शिराक की फाइल रायटर फोटो।

घटकर पांच साल कर दिया था। वह 14 साल के सोशलिस्ट शासन को खत्मकर 1995 में राष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा था। 2011 में उन्हें सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में दोषी पाया गया था। इस मामले में उन्हें दो साल की निर्लबित सजा सुनाई गई थी।

रणनीति ▶ अब रिषभ को सबसे ज्यादा जरूरत है अपने खेल को बदलने की, युवराज-धौनी की तरह दबाव में खुद को संभालना सीखना होगा

रिषभ पंत को सीखनी होगी दबाव में संभलने की कारीगरी



निखिल शर्मा, नई दिल्ली

भारतीय टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत को पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के उत्तराधिकारी के तौर पर चयनकर्ता स्थापित करने में जुटे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को विशाखापत्तनम में दो अक्टूबर से पहला टेस्ट मैच खेलना है। इस समय युवराज सिंह, गौतम गंभीर, रवि शास्त्री सहित सभी क्रिकेट दिग्गज उनकी ही बात कर रहे हैं। कई मौकों पर पंत ने खुद को साबित भी किया। हालांकि विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई सीरीज से ही पंत के लिए हालात बिगड़ते चले गए। कोशल के नाम पर पंत को लगातार मौके दिए जा रहे हैं। बात कोशल की ही है तो वह तो केरल के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और बिहार के युवा बल्लेबाज इशान किशन भी कम नहीं हैं। ऐसे कई मौके रहे हैं जहां पंत दबाव में बिखरे हैं।

सच्चाई यह है कि पंत को अगर सफल होना होगा तो उनकी लड़ाई किसी और से नहीं खुद से है, क्योंकि पंत को दबाव में संभलने की कारीगरी सीखनी होगी। जैसा कि धौनी और युवराज सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ी अपने समय में करते आए हैं।

दबाव में बिखरते हैं पंत :

ऐसा नहीं है कि पंत सिर्फ बल्लेबाजी में ही दबाव नहीं संभाल पाए हैं। विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम

भारत के तौर पर थी। पहले

तीन वनडे खेलने के बाद धौनी दो आखिरी वनडे में नहीं खेले। मोहाली में 13 मार्च को हुए वनडे में मैदान पर मौजूद

दर्शक धौनी-धौनी चिल्ला रहे थे।

विकेटकीपिंग में पंत से अचानक कुछ

गलतियां होने लगी। तब दर्शकों ने इसका

शास्त्री और विराट पंत से बात करें : गंभीर

नई दिल्ली : पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर का मानना है कि शॉट चयन भारतीय युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत का खेल है। अब चाहे आप उन्हें टीम में रखें या नहीं। गंभीर का मानना है कि पंत को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आए डेढ़ वर्ष ही हुआ है। इसमें वह दो शतक भी जमा चुके हैं। गंभीर का मानना है कि युवा खिलाड़ी पर फोकस रखने से उन्हें ही परेशानी होगी।

गंभीर ने कहा कि मुझे लगता है कि किसी भी युवा खिलाड़ी के ऊपर इस तरह का फोकस करेंगे तो परेशानी होगी। अभी पंत एक-डेढ़ साल ही हुआ है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। इतने में ही वह टेस्ट में दो शतक जमा चुके हैं। अगर आप कहेंगे कि आपको उनके शॉट चयन से परेशानी है तो यह उनका खेल है। आप उनको टीम में लीजिए या नहीं लीजिए। अगर आप उनको चुन रहे हैं तो फिर आप उनका साथ दीजिए क्योंकि एक युवा खिलाड़ी की इतनी आलोचना सही नहीं है। गंभीर ने कहा कि सिर्फ विराट कोहली को ही नहीं कोच रवि शास्त्री को भी पंत से बात करनी चाहिए। टीम प्रबंधन का काम ही यही है कि आपका जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है या फिर गलत शॉट चयन कर रहा है, उससे बात कर उसे फॉर्म में लाया जाए और उसके खेल को सुधारा जाए। पंत को स्वतंत्रता देने की जरूरत है। धौनी के संन्यास की खबरों पर गंभीर ने कहा कि मैंने हमेशा से कहा है कि संन्यास का फैसला हर किसी का निजी फैसला है। मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं को धौनी से बात करनी चाहिए और पृष्ठना चाहिए कि उनकी रणनीति क्या है क्योंकि अगर आप भारत के लिए खेलते तो

आप सीरीज का चुनाव अपने हिसाब से नहीं कर सकते।

हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के प्रमुख बनाए गए राहुल द्रविड़ पर हितों के टकराव का आरोप है। इस पर गंभीर ने कहा कि यह काफी मुश्किल सवाल है। राहुल अगर एनसीए प्रमुख रहते हैं तो इससे बेहतर बात एनसीए, भारत और देश के युवा खिलाड़ियों के नहीं हो सकती। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा ने कहा था कि विराट कोहली को घर में होने वाले टेस्ट मैचों से जसप्रीत बुमराह को आराम देने चाहिए ताकि उन्हें विदेशों के लिए बचाया जा सके। गंभीर ने कहा कि अगर कोई अच्छा है तो उसे हर परिस्थिति में खेलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को सिर्फ विदेशों के लिए चुनें। आप इस तरह से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। बुमराह हालांकि चोटिल हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो अक्टूबर से शुरू हो रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। बुमराह के न होने पर गंभीर ने कहा कि वह टेस्ट में नंबर-1 गेंदबाज हैं। उनकी कमी निश्चित तौर पर खलेगी। इससे मुहम्मद शमी और इशांत शर्मा को तीन टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलेगा। बुमराह किसी भी टीम के लिए किसी भी प्रारूप में बड़ा खतरा है और वह टीम में नहीं है इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस सीरीज में रोहित शर्मा को बतौर सलामी बल्लेबाज शामिल किया गया है। गंभीर ने रोहित को टेस्ट में सलामी बल्लेबाज के तौर पर चुने जाने पर कहा कि उन्होंने विश्व कप में पांच शतक लगाए हैं तो उनका टेस्ट टीम में शामिल होना जाहिर सी बात है।

फायदा उठाते हुए पंत की हट्टिंग शुरू कर दी। पंत इतना दबाव में आ गए कि उन्होंने कई स्ट्राइंग छोड़ीं। यह साफ बताता है कि इस युवा बल्लेबाज को दबाव संभालना नहीं आता है।

दबाव हटा पंत चले : इसके बाद आइपीएल चल रहा था। सभी खिलाड़ियों को विश्व कप टीम चुने जाने का इंतजार था। इसमें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी पंत

को भी चुने जाने की उम्मीदें थीं। इस बीच पंत लगातार आइपीएल में विफल हो रहे थे। टीम का चयन हुआ, पंत को मौका नहीं मिला। इसके बाद पंत ने नॉकआउट मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब उन्होंने बेहद दबाव भरें मैच में 21 गैद में 49 रन की पारी खेली थी। जाहिर सी बात है इस पारी में उन पर टीम में चयन होगा या नहीं जैसा कोई दबाव नहीं था।

ओपनिंग के लिए विनती करनी पड़ी थी : तेंदुलकर



नई दिल्ली, प्रेटर : महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के 'टर्निंग प्वाइंट' को याद करते हुए कहा कि 1994 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए पारी का आगाज करने के लिए उन्हें 'विनती' करनी पड़ी थी। तेंदुलकर के लिए मध्य क्रम बल्लेबाजी से हटकर पारी का आगाज करने का कदम 'मास्टरस्ट्रोक' साबित हुआ था, जिससे वह 50 ओवर के प्रारूप में विश्व रिकॉर्ड 49 शतक जड़ पाए थे। तेंदुलकर ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे के दौरान हुए क्षणों को याद किया। उन्होंने कहा कि 1994 में जब मैंने भारत के लिए बल्लेबाजी का आगाज किया था तो सभी टीमों की रणनीति विकेट बचाए रखने की होती थी, लेकिन मैंने थोड़ा इससे हटकर करने की कोशिश की। तेंदुलकर ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं आगे बढ़कर प्रतिद्वंद्वी गेंदबाजों से डटकर सामना कर सकता हूं, लेकिन मुझे विनती करनी पड़ी कि कृपया मुझे मौका दो। अगर मैं विफल रहूँगा तो मैं फिर आपके पास नहीं आऊंगा। अपने उस कदम को उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पूर्व बल्लेबाज ने अपने प्रशंसकों से आग्रह किया कि विफलता के डर से जोखिम लेने से डरो मत। तेंदुलकर (46 वर्ष) ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में पहले मैच में मैंने 49 गैद में 82 रन बनाए, इसलिए मुझे दोबारा नहीं पृष्ठना पड़ा कि मुझे दूसरा मौका मिलेगा या नहीं। वे चाहते थे कि मैं पारी का आगाज करूँ, लेकिन मैं यह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि असफलता से डरो मत। पारी का आगाज करने पर उन्होंने सितंबर 1994 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलंबो में अपना पहला वनडे शतक जड़ा था।

चैपल ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में अपना राष्ट्रीय चयनकर्ता का पद छोड़ा

क्रिकेट डायरी

सिडनी, एएफपी : ग्रेग चैपल ने गुरुवार को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) का अपना पद छोड़ने की घोषणा की, जिसके बाद सीए को नए राष्ट्रीय चयनकर्ता की तलाश है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 87 टेस्ट और 74 वनडे अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले पूर्व कप्तान चैपल पिछले नौ साल से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय प्रतिभा मैनेजर और चयनकर्ता थे। पूर्व टेस्ट विकेटकीपर ग्राहम मनाऊ अब 'नेशनल टेलेंट एंड पैथवे मैनेजर' की अतिरिक्त भूमिका भी निभाएंगे। नौ चयनकर्ता की घोषणा बाद में की जाएगी। मौजूदा चयन पैनल में चैपल के अलावा अध्यक्ष ट्रेवर हेंस और कोच जस्टिन लैंगर शामिल हैं।

कोहली, गोयनका ने की इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स अवॉर्ड की तारीख की घोषणा

मुंबई, प्रेटर : भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और आरपी-एसजी ग्रुप के चेयरमैन संजीव गोयनका ने गुरुवार को इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स अवॉर्ड के दूसरे संस्करण की तारीखों का एलान कर दिया है। यह अवॉर्ड शुक्रवार को यहां के एनएससीआइ, एसवीपी स्टेडियम में दिए जाएंगे। यह वार्षिक अवॉर्ड समारोह पहले फरवरी में होना था, लेकिन पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इस साल उन 17 खिलाड़ियों को अवॉर्ड से नवाजा जाएगा, जिनहोंने 2018 में दमदार प्रदर्शन किया। 11 वर्गों में दिए जाने इन प्युरी ऑनर्स पुरस्कारों का चयन छह सदस्यीय समिति ने किया है। इस समिति में भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, सरदार सिंह, महेश भूपति, पीटी उषा और अंजलि शामिल हैं।

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप

आज से शुरू हो रही है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, चोट की वजह से भाग नहीं ले रहे नीरज और हिमा

आइसीसी ने फेसबुक से साझेदारी की घोषणा की

दुबई, प्रेटर : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने गुरुवार को फेसबुक के साथ साझेदारी की घोषणा की जिससे इस सोशल मीडिया साइट के पास भारतीय उपमहाद्वीप में आइसीसी वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए 'एक्सक्लुसिव डिजिटल कंटेंट' अधिकार होंगे। फेसबुक काफी लोकप्रिय सोशल मीडिया मंच है जिसमें 2023 तक पूरी दुनिया में मैच के बाद के 'रिकैप' की पोस्ट भी होंगी। फेसबुक पर चार वर्षों तक डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे।

जो वेतन आर्थर को देते थे मुझे दे पीसीबी : मिस्बाह

कराची, आइएनएसएस : पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नवनियुक्त कोच मिस्बाह उल हक ने कहा है कि उन्होंने बोर्ड से वेतन को लेकर किसी तरह की मांग नहीं रखी और सिर्फ यही कहा कि जितना वेतन बोर्ड/मि की आर्थर को देता था उतना ही उन्हें दें। श्रीलंका टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी जहां दोनों टीमों तीन टी-20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेंगी। वनडे मैच कराची में 27, 29 सितंबर और तीन अक्टूबर को खेले जाएंगे। वहीं टी-20 सीरीज लाहौर में पांच, सात और नौ अक्टूबर को खेली जाएगी। मिस्बाह ने कहा कि मैंने नौकरी पाने के लिए कोई जादू नहीं किया। मैंने किसी तरह के वेतन की मांग भी नहीं की। मैंने उनसे सिर्फ वही वेतन देने का कहा था जो वह आर्थर को दे रहे थे। मिस्बाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) 28 लाख रुपये महीने देगा।

सफल सलामी वल्लेबाज बन सकती है शैफाली : मिताली

मुंबई, प्रेटर : भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान मिताली राज ने 15 वर्षीय शैफाली वर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि यह आक्रामक सलामी बल्लेबाज बेहतर मौके मिलने से लंबे समय तक महिला टीम को सेवाएं दे सकती है। मिताली ने कहा कि वह (शैफाली) प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उन्हें सही तरह के मौके और बेहतर तरीके से सवारे जाने पर वह भारत के लिए भविष्य की खिलाड़ी बन सकती हैं। शैफाली को हाल में टी-20 से संन्यास लेने वाली मिताली की जगह टीम में लिया गया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज में मौका दिया गया, लेकिन वह पहले मैच में खाता खोलने में नाकाम रही। मिताली ने यहां एक कार्यक्रम से इतर कहा कि वह चाहती हैं कि उनकी वनडे टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करे।



टीम की नई जर्सी के साथ भारतीय एथलीट ।

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक भी नहीं पहुंच सकीं, जिससे उनसे पदक की उम्मीद नहीं थी।

एएफआई को हालांकि चार गुणा 400 मीटर की तीन रिले टीमों, विशेषकर मिक्स्ड चार गुणा 400 मीटर रिले टीम से उम्मीद है। मिक्स्ड चार गुणा 400 मीटर रिले स्पर्धा को पहली बार विश्व चैंपियनशिप में जगह मिली है। हालांकि, पदक की उम्मीद करना बेमानी होगा और अंजू बॉबी जॉर्ज का 2003 विश्व चैंपियनशिप में लंबी कूद

में जीता गया कांस्य पदक एकमात्र सफलता बना हुआ है। लंदन में 2017 में पिछली प्रतियोगिता में सिर्फ एक भारतीय फाइनल (पुरुष भाला फेंक में देविंदर सिंह कंग) में जगह बनाने में सफल रहा था, जबकि पैदल चाल और मैराथन धावकों ने निराश किया था।

भारत की 27 सदस्यीय टीम में से 13 खिलाड़ियों को रिले स्पर्धाओं के लिए चुना गया है। धारुन अय्यासामी हालांकि व्यक्तिगत 400

चुनाव

चेन्नई, प्रेटर : बीसीसीआइ के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की बेटी रुपा गुरुनाथ को गुरुवार को यहां तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया जिससे वह भारतीय बोर्ड की राज्य इकाई की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं। रुपा गुरुनाथ मययपन की पत्नी हैं जिन पर 2013 आइपीएल में स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगा हुआ है। रुपा को टीएनसीए की 87वां वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष चुना गया। सीओए ने टीएनसीए संविधान की गलत बताया

वहीं, प्रशासकों की समिति (सीओए) ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) के नए संविधान को लोढ़ा समिति की सिफारिशों के मुताबिक 21 सूत्रों पर गलत बताया है और कहा है कि चार अक्टूबर तक वह अपने संविधान पर दोबारा काम करें ताकि 23 अक्टूबर को होने वाली बीसीसीआइ की एजीएम में शामिल हो सके। टीएनसीए के वक्रील अमोल चित्ताले ने हालांकि साफ कर दिया है कि इस तरह के फैसले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लेगी।

नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया बुधवार शाम पांच बजे खत्म हो गई थी जिसके बाद अध्यक्षपद के लिए सिर्फ रुपा ने नामांकन दाखिल किया। टीएनसीए के नियमों के अनुसार वार्षिक आम बैठक में उनके नाम की घोषणा हुई। टीएनसीए की कार्यकारिणी ने रविवार को बैठक में गुरुवार को चुनाव कराने का फैसला किया था। टीएनसीए हाल में सुविधियों में आया था क्योंकि उसकी फ्रेंचाइजी आधारित तमिलनाडु प्रीमियर लीग में अधिकारियों, कोचों और खिलाड़ियों मैच फिक्सिंग में शामिल होने का आरोप

ये भी जानिए

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शुरुआती दो टेस्ट जीतकर भारतीय टीम 120 अंक के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है। वहीं, आगामी दो अक्टूबर से शुरू हो रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज से दक्षिण अफ्रीका अपने अभियान की शुरुआत करने उतरेगी।

हार्दिक को संयम बरतने की जरूरत थी। कुछ समय तक पंत खुद को संभाल सके, लेकिन जब पारी को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। वह एक गेंद को सीमा पार पहुंचाने की जल्दबाजी में पवेलियन लौट गए।

खुद पर भी करने लगे हैं शक : पंत इस समय ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसमें वह खुद पर भी शक कर लगे हैं। पंत में पहली गेंद से ही आक्रामक शॉट खेलने का कोशल है, लेकिन ऐसे बल्लेबाज जब लगातार मैच में ऐसा करने में विफल होकर अपना विकेट गंवाने लग जाते हैं तो आलोचना शुरू हो जाती है। ऐसा ही समय एक बार वीरेंद्र सहवाग के करियर में भी आया। जब शुरुआत से ही ऑफ ड्राइव खेलने के चक्कर में वह विकेट के पीछे पकड़ें जाने लगे। रिफ्लेक्शन कम होने पर सहवाग को चश्मा लगाकर भी खेलते देखा गया, लेकिन उन्हें सफलता मिली अपने खेल को बदलने से। पंत को भी खुद पर फोकस करना होगा।

बड़ी जिम्मेदारी बन रही है वजह : दरअसल, पंत पर दबाव बढ़ने की सबसे बड़ी वजह नंबर-चार का स्थान भी है। इस स्थान पर युवराज सिंह और सुरेश रैना जैसे दिग्गज बल्लेबाज खेलते आए हैं। शुरुआती विकेट गिरने पर इस स्थान के खिलाड़ी पर दबाव बढ़ता है। ऐसा देखने में भी आया है जब शुरुआती विकेट गिरने पर पंत आए और गलत शॉट खेलकर आउट होकर चले गए। पंत को इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि पंत के निडर कोशल का डेथ ओवरों में इस्तेमाल किया जाए।

बिना दबाव के बनाए टेस्ट शतक : भले ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में पंत ने टेस्ट शतक लगाए, लेकिन इंग्लैंड में खेली गई उनकी 114 रनों की पारी भी सबालों के घेरे में रही। जब टीम को ओवल में पांचवां टेस्ट बचाया था और जिम्मेदारी केएल राहुल और पंत पर थी। राशिद की अदभुत गेंद पर राहुल के आउट होने के बाद पंत के पास हीरो बनने का मौका था लेकिन वह शतक लगाने के बाद छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए और टीवी यह मैच हार गई थी। जहां तक उनके सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए गए शतक की बात है जिस समय पंत क्रीज पर आए थे मयंक अग्रवाल और चेन्नईर पुजार नींव खड़ी कर चुके थे और इससे पंत को खुलकर अपना खेल खेलने का मौका मिला। पंत को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सफल होने के लिए धौनी-युवराज जैसी कारीगरी सीखनी होगी।

तमिलनाडु क्रिकेट संघ की अध्यक्ष बनी श्रीनि की बेटी रुपा गुरुनाथ

किसी भी राज्य संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी

डेनी मारक बने मेघालय संघ के अध्यक्ष

नई दिल्ली : डेनी मारक गुरुवार को मेघालय क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष बन गए, जबकि लेक्चरर मिडेयोन खरकोनगोर सचिव चुने गए हैं। इससे पहले अध्यक्ष कोनराड के. संगमा और सचिव नबी भट्टाचारजी कूलिंग ऑफ पीरियड पर चले गए हैं। ध्रुवाज्योति ठाकुरिया को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। भट्टाचारजी ने कहा कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। मैं नई टीम की पूरी सहजता और मार्गदर्शन करूंगा।

लगा था। इस मामले की जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टीएनसीए को पदाधिकारियों का चुनाव करने की अनुमति दे दी लेकिन कहा था कि इसके परिणाम कोर्ट के फैसले के दायरे में होंगे और राज्य क्रिकेट संघ चुनाव करा सकता है लेकिन वह परिणाम घोषित नहीं करेगा।

परिणाम की घोषणा इस न्यायालय के आदेश के दायरे में आएगी और पक्षकार कानूनी मदद ले सकेंगे। भारतीय क्रिकेट का काम देख रही प्रशासकी की समिति (सीओए) ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की थी कि टीएनसीए ने खुद को बीसीसीआइ के नए संविधान के अनुरूप नहीं खाला है। अन्य पदाधिकारियों का सुची खली है।उज्जय श्रीनिवासराज, डा. पी. अशोक सिगमानी, सचिव-आर एस रामासामी, संयुक्त सचिव-केए प्रशंकर, सहायक सचिव-एन. वेंकटरमन, कोषाध्यक्ष-जे. पार्थसारथी।

यदि कार्सटन गॉर्डन गेको हैं तो मैं आइआरएस हूं : वेंजामिन दोहा, प्रेटर : े वेंजामिन ने गुरुवार को नॉर्थ के 400 मीटर बाधा दौड़ के विश्व चैंपियन कार्सटन वारहोम पर धातु का दस्ताना फेंकते हुए घोषणा की कि 'यदि कार्सटन गॉर्डन गेको हैं तो मैं आइआरएस हूं।' वारहोम अपने आप को गेको के रूप में देखते हैं जो ओलिवर स्टोन की 'वॉल स्ट्रीट' फिल्मों में माइकल डायलस का निर्बाई गई अनीतिक फाइनेंसर की भूमिका है, जिसका आदर्श वाक्य था 'लालच अच्छा है'। यह घटना शुक्रवार से यहां शुरू हो रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक और मसाला जोड़ेगी। दरअसल इस स्पर्धा के कैंबिन रंग के नाम पर दर्ज 27 साल पुराने विश्व रिकॉर्ड को खतरे में देखा जा रहा है, क्योंकि वारहोम और वेंजामिन ने एक रेस में भाग लिया था जो अगस्त में ज्यूरिख में डायमंड लीग सत्र में आयोजित हुई थी, जिसे इन दोनों ने ही 47 सेकेंड के जादुई बैरियर के अंदर पूरा कर लिया था। टेस्टेडडीज के पूर्व क्रिकेटर विस्टर वेंजामिन के पुत्र रे वेंजामिन

ज्यूरिख में वारहोम के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। वेंजामिन ने कहा कि मैंने लालच के बारे में कोट दिया।

पहले दिन का खेल बारिश में धुला

विजयनगरम (आंध्र प्रदेश), प्रेटर : दक्षिण अफ्रीका और बोर्ड अध्यक्ष एकादश के बीच गुरुवार से यहां शुरू हुए तीन दिवसीय अभ्यास मैच के पहले दिन का खेल बारिश के कारण संभव नहीं हो पाया।

लगातार हो रही बारिश के कारण गुरुवार को टॉस भी नहीं हो पाया। इस मैच में रोहित शर्मा को पहली बार सलामी बल्लेबाज के तौर पर जगह मिली है। यह अभ्यास मैच रोहित को अपने आप को तैयार करने का मौका देगा। रोहित इस मैच में बोर्ड अध्यक्ष एकादश की कप्तानी कर रहे हैं। उनके अलावा करुण नायर को भी इसमें जगह मिली है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई तीन मैचों की टी-20 सीरीज 1-1 से ड्र रही थी। दोनों टीमों अब अभ्यास मैच के बाद दो अक्टूबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेंगी।

